खबर पेज 7 पर

गंभीर समाचार

समय–समाज–संस्कृति

खबर पेज 8 पर

वर्ष -12 | अंक–28 | पाक्षिक समाचार पत्रिका | कोलकाता, शुक्रवार 1 – 15 मई 2026 | मूल्यः 5 रुपये | RNI No.WBHIN/2014/59321, ISSN No. 2456/3005 Kolkata | कुल पृष्ठ – 8

सुविचार

- 'दो अक्षर का होता है लक, ढाई अक्षर का होता है भाग्य, तीन अक्षर का होता है नसीब, साढ़े तीन अक्षर की होती है किस्मत, पर ये चारों के चारों चार अक्षर, मेहनत से छोटे होते हैं!'
- अपने लक्ष्य के लिए जोशीले और जुनूनी बनिए.. विश्वास रखिए, परिश्रम का फल सफलता हि है!
- समझनी है जिंदगी तो पिछे देखो, जीनी है जिंदगी तो आगे देखो।
- ज़िंदगी का सफ़र मानो तो मौज है वरना समस्या तो रोज है।
- घायल तो यहां हर परिंदा है। मगर जो फिर से उड़ सका वहीं जिंदा है..

शेरो-शायरी

- हथेली पर रखकर नसीब, तू क्यों अपना मुकद्दर ढूंढता है, जरा सीख उस समंदर से, जो टकराने के लिये पत्थर ढूंढता है...!!
- बुरा वक्त एक ऐसी तिजोरी है जहां से सफलता के हथियार मिलते हैं।
- ठोकरें खा के भी ना संभले तो मुसाफ़िर का नसीब वर्ना पत्थरों ने तो अपना फर्ज निभा ही दिया।

1 जून से महिलाओं को मिलेंगे 3000 रुपए और मुफ्त बस यात्रा की सुविधा

निज संवाददाता : बंगाल में 1 जून से 'अन्नपूर्णा भंडार' के तहत महिलाओं को 3000 रुपए के साथ-साथ मुफ्त बस यात्रा की सुविधा मिलेगी। 3000 रुपए महिलाओं के बैंक अकाउंट में आने लगेगा। मालूम हो कि चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने महिलाओं के लिए अन्नपूर्णा भंडार का बार-बार वादा किया था। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने नई सरकार के पहले वर्किंग डे पर उन वादों को पूरा करना शुरू कर दिया। पिछले दिनों नवान्न में सीएम शुभेंदु अधिकारी की पहली कैबिनेट बैठक हुई। उस बैठक के बाद राज्य सरकार ने 'अन्नपूर्णा भंडार' शुरू करने की तारीख का ऐलान किया। इतना ही नहीं, यह भी ऐलान किया गया है कि 1 जून से सरकारी बसों में सफर करने वाली महिलाओं को कोई किराया नहीं देना होगा। तत्कालीन मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 2021 के विधानसभा चुनाव से पहले महिलाओं को 'लक्ष्मी भंडार' देने का वादा किया था। उन्होंने 2021 में चुनाव जीतने के बाद इस प्रोजेक्ट को शुरू किया। शुरुआत में यह प्रोजेक्ट 500 रुपये प्रति महीने से शुरू हुआ

था। उसके बाद धीरे-धीरे पैसे बढ़ाए गए। पिछली सरकार के आखिरी बजट में लक्ष्मी भंडार में मिलने वाले पैसे को बढ़ाकर 1,500 रुपये प्रति महीने कर दिया गया था और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की महिलाओं को हर महीने 1,700 रुपये दिए जाते थे। हालांकि, 2026 के चुनाव से पहले बीजेपी ने ममता बनर्जी को हराने के लिए ममता के बनाए हथियार का इस्तेमाल किया। उन्होंने अपने घोषणा पत्र में कहा कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हर महीने 3,000 रुपये की आर्थिक मदद दी जाएगी। शुभेंदु सरकार ने घोषणा की कि वह उस वादे को पूरा करेगी। चुनाव प्रचार के दौरान, पीएम मोदी और शाह ने लगभग हर जनसभा में इस अन्नपूर्णा भंडार की बात की थी। राज्य सरकार ने घोषणा की कि वह वादा पूरा किया जाएगा। महिलाएं 1 जून से सरकारी बसों में मुफ्त में सफर कर सकेंगी। गौरतलब है कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल सरकार ने सबसे पहले यह सुविधा शुरू की थी। दिल्ली में सरकार बदल गई है। हालांकि, दिल्ली की बीजेपी सरकार ने केजरीवाल द्वारा शुरू की गई सुविधा को अभी भी बनाए रखा है। प्रशासनिक सूत्रों के मुताबिक, अन्नपूर्णा भंडार के तहत सिर्फ उन्हीं लोगों को तीन हजार रुपये महीने मिलेंगे जिन्हें लक्ष्मी भंडार मिलता था। फिलहाल, अन्नपूर्णा भंडार के लिए दोबारा अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। अगर बाद में किसी जानकारी या डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ी तो सरकार आपको बता देगी। राज्य में बदलाव के बाद यह सवाल उठा कि क्या राज्य के लोगों को पिछली तृणमूल सरकार द्वारा शुरू किए गए प्रोजेक्ट्स का फायदा अब भी मिलेगा या नहीं? उस शक को दूर करते हुए, शुभेंदु अधिकारी ने पहली कैबिनेट बैठक के बाद घोषणा की कि राज्य के लोगों को उन सभी सोशल प्रोजेक्ट्स का फायदा अब भी मिलेगा जो उन्हें पहले मिलता था। कुछ ही घंटों में राज्य सरकार ने अन्नपूर्णा भंडार शुरू करने की तारीख की घोषणा कर दी।

राज्य सरकार ने सार्वजनिक रूप से पशु वध पर लगाई रोक

निज संवाददाता : पश्चिम बंगाल सरकार ने 1950 के बंगाल कानून और 2018 के कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश का हवाला देते हुए एक नोटिस जारी किया है। इसमें कहा गया है कि बिना अनिवार्य फिटनेस प्रमाण पत्र के किसी भी गाय या भैंस का वध पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। सरकार ने बताया कि यह फिटनेस प्रमाण पत्र केवल नगरपालिका के अध्यक्ष या पंचायत समिति के अध्यक्ष और सरकारी पशु चिकित्सक मिलकर जारी करेंगे, जब दोनों लिखित रूप में इस बात पर सहमत हों कि पशु की उम्र 14 साल से ज्यादा है और वह काम या प्रजनन के लायक नहीं रहा है या फिर किसी पुरानी बीमारी, चोट, शरीर की खराबी या ठीक न होने वाली बीमारी के कारण हमेशा के लिए अक्षम हो गया है। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया कि अब सार्वजनिक रूप से पशु वध की अनुमति नहीं होगी। केवल नगरपालिका की ओर से तय या अधिकृत वधशाला में ही पशुओं का वध किया जा सकेगा। नियम का उल्लंघन करने पर छह महीने तक की जेल, 1000 रुपये तक का जुर्माना या दोनों सजा हो सकती है। यदि फिटनेस प्रमाण पत्र देने से इनकार किया जाता है, तो व्यक्ति 15 दिनों के भीतर राज्य सरकार में अपील कर सकता है। मालूम हो कि मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व वाली पश्चिम बंगाल सरकार ने ममता बनर्जी के 15 साल के शासन के बाद कई बड़े फैसले लिए हैं।

बंगाल की मां कैंटीन में अब मिलेगा मछली-भात

निज संवाददाता : पश्चिम बंगाल की नई भाजपा सरकार अब मां कैंटीन में पांच रुपए में लोगों को मछली-भात मुहैया कराएगी। सूत्रों के मुताबिक, राज्य की नई भाजपा सरकार मा कैंटीन को बंद करने के बजाय उसे और बेहतर बनाने की योजना बना रही है।नई सरकार के एक वरिष्ठ विधायक के अनुसार-हम केवल अंडे तक सीमित नहीं रहना चाहते। बंगाली अपनी पहचान माछे-भाते (मछली-चावल) से रखते हैं। इसलिए, मा कैंटीन के मेन्यू में अंडे की जगह अब मछली-चावल देने के प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है। खास बात यह है कि भोजन की कीमत में कोई बढ़ोतरी नहीं की जाएगी; यह पहले की तरह मात्र 5 रुपये में ही उपलब्ध होगा।योजना को जारी रखते हुए सरकार इसका नाम बदलने की तैयारी में है। कृषि विपणन विभाग को इस मामले की समीक्षा करने का निर्देश दिया गया है। गौरतलब है कि सुफल बांग्ला के माध्यम से इन कैंटीनों को सस्ती सब्जियां और सरकारी कोटे से मुफ्त चावल की आपूर्ति जारी रहेगी। गौरतलब है कि मां कैंटीन की शुरुआत 2021 के विधानसभा चुनाव से पहले ममता बनर्जी सरकार ने की थी। दक्षिण कोलकाता के देशप्रिय पार्क से इसकी शुरुआत हुई थी। 32 केंद्रों से शुरू होकर आज राज्य भर में लगभग 249 मां कैंटीन संचालित हैं।

बांग्लादेशी घुसपैठ और मुस्लिम तुष्टिकरण की विकृत राजनीति के खिलाफ जनादेश

निज संवाददाता : हाल में संपन्न पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव ने कई सबक दिए हैं। बड़ी बात यह कि 69 वर्षों के अथक संघर्ष के बाद भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत वाली सरकार प्रथम सरकार शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में कार्यभार ग्रहण करके काम पर लग गयी है। बंगाल में बीजेपी की विजय बहुत बड़ी व ऐतिहासिक है। बंगाल ही नहीं भारत के अन्य भागों में भी इस विजय का आनंद दिखाई वातावरण दे रहा है। इस विजय के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कर्नाटक, तेलंगना और गुजरात के दौर में जो भीड़ उमड़ रही है उससे स्पष्ट रूप से जनसामान्य और भाजपा कायकर्ताओं के उत्साह का अनुमान लगाया जा सकता है। बंगाल विधानसभा चुनावों मे हिंदू समाज ने पहली बार बांग्लादेशी घुसपैठ और मुस्लिम तुष्टिकरण की विकृत राजनीति के विरुद्ध एकजुट होकर मतदान किया और जिसका परिणाम आज पूरा भारत देख रहा है। बंगाल की जिस धरती पर 75 वर्ष पूर्व डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जनसंघ की वैचारिक नींव रखी थी उसी बंगाल में पहली बार भाजपा 27 सीटों के साथ सत्ता के शिखर पर पंहुची

बंगाल चुनाव का सबक

और भगवा वस्त्रों में शुभेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। बंगाल की कैबिनेट में अभी पांच मंत्रियों को ही शपथ दिलाई गई है, जिसमें बंगाल में भाजपा का संगठन खड़ा करने में अहम भूमिका निभाने वाले दिलीप घोष, फैशन डिजाइनर से बंगाल भाजपा की सबसे मुखर नेत्री बनी अग्निमित्रा पॉल जिन्होंने तृणमूल के खिलाफ आक्रामक मोर्चा संभाला, बांग्लादेश के हिंदू शरणार्थी मतुआ समुदाय के प्रमुख चेहरे अशोक कीर्तनिया जो उत्तर 24 परगना जिले के भारत-बांग्लादेश सीमा से सटे इलाको में भाजपा के जमीनी संगठनकर्ता के रूप मे अत्यंत सक्रिय रहे हैं, छात्र राजनीति से उभरे नेता निशीथ प्रामाणिक जो 2019 में भाजपा से जुड़े और जंगल महल के आदिवासी समुदाय के बड़े नेता खुदीराम टुडू शामिल हैं। अभी इस मंत्रिमंडल है का विस्तार होना बाकी है। बंगाल में शपथ ग्रहण समारोह के मंच पर एक भारत श्रेष्ठ भारत की संकल्पना के अनुरूप लघु भारत के भव्य दर्शन हो रहे थे तथा भविष्य की राजनीति के संकेत भी मिल रहे थे। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से आज तक बंगाल में कांग्रेस, वामपंथ और तृणमूल की सरकारें रहीं जो तुष्टिकरण में आकंठ डूबी रहीं और हिंदुओ को दोयम दर्जे का नागरिक बना दिया। स्थितियां इतनी विकट हो गयी थीं कि बंगाल की धरती पर जय श्रीराम बोलने पर नफरत का कहर टूट पड़ता था। आज उसी बंगाल में जब जयश्रीराम के नारे गूंज रहे हैं तो बंगाल का हर सनातनी खुशी से सराबोर हो रहा है। बंगाल में भाजपा सरकार आने से पश्चिम बंगाल के हिन्दुओं को तुष्टिकरण की दमनकारी नीतियों और भय के माहौल से आजादी मिली है। यह विजय केवल सत्ता का परिवर्तन नही अपितु बंगाल के पुनरुत्थान का शंखनाद है। अब बंगाल सही मायने में सोनार बांग्ला बनने की ओर अग्रसर होगा। भाजपा नेताओं का कहना है कि मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में पश्चिम बंगाल सांस्कृतिक, आध्यात्मिक व आर्थिक उत्थान के नए दौर मे प्रवेश करेगा। हार की कुंठा से ग्रसित तृणमूल व विरोधी दलों के नेता अभी भी एसआईआर, चुनाव आयोग और केंद्रीय सुरक्षाबलों वाले आरोप दोहरा रहे हैं जबकि वास्तविकता यह है कि भाजपा ने यह चुनाव लम्बे संघर्ष और अपने कार्यकर्ताओं के बलिदान के बाद जीता है। तृणमूल के राज में वर्ष 2011 से 2025 के बीच भाजपा के 321 कार्यकर्ता मारे गए, उनके विरुद्ध हुई हिंसा में हजारों घर उजाड़ दी गए, भाजपा व संघ के किसी कार्यकर्ता को बम से उड़ाया गया किसी को पेड़ से लटकाया गया। 2021 में तो भाजपा कार्यकर्ताओं के प्रति तृणमूल के लोगों ने क्रूरता की सभी सीमाएं लांघ दी थीं। नंदीग्राम से लेकर वीरभूम तक, कूच बिहार हो या बशीर हाट चुनाव के बाद बदले के नाम पर पूरे-पूरे गांव खाली करवा दिए गए थे। 2021 की चुनावी हिंसा में हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच के आदेश दिए किंतु ममता सरकार उन सभी में अड़ंगा डालती रही। आज संदेशखाली से आर जी कर कांड तक सभी पीड़ित परिवारों के मन में एक नया सबेरा आया है कि अब न्याय होकर रहेगा। बंगाल के हिंदू जनमानस को नयी सरकार पर भरोसा है इसलिए नई सरकार को भी अत्यंत तत्परता और सतर्कता के साथ संकल्प पत्र को पूरा करना होगा।

देश के प्रति योगदान शून्य, फिर भी राहुल-प्रियंका बने हैं मीडिया के 'हीरो'!

निज संवाददाता : किसी जमाने में भारतीय राजनीति में कांग्रेस और नेहरू-गांधी परिवार की जड़ें समान रूप से काफी मजबूत हुआ करती थीं। लोग तो यहां तक कहते थे कि नेहरू-गांधी परिवार के बिना कांग्रेस अधूरी मानी जाती थी। कांग्रेस ने देश को जितने प्रधानमंत्री दिए, उनमें इस परिवार के तीन सदस्य प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी तक ने कुल मिलाकर कई दशक तक देश पर राज किया। कांग्रेस तब तक उभार पर रही, जब तक पार्टी के भीतर इन तीनों का सिक्का चला, लेकिन इसके बाद सोनिया गांधी के हाथ में कांग्रेस की बागडोर आने के बाद धीरे-धीरे कांग्रेस का बुरा दौर शुरू हो गया। हालांकि यह इतना बुरा भी नहीं था कि कांग्रेस हाशिये पर चली गई हो। 2014 तक वह किसी न किसी तरह सत्ता की सीढ़ियां चढ़ने में कामयाब हो ही जाती थी, परंतु जब से सोनिया गांधी की पकड़ पार्टी पर कमजोर और राहुल गांधी की मजबूत होना शुरू हुई, तब से कांग्रेस का बेहद बुरा दौर आ गया। केंद्र की सत्ता तो कांग्रेस से फिसली ही, राज्य दर राज्य भी कांग्रेस की सरकारें जाती रहीं। हालात यह हो गया कि नेशनल पार्टी का तमगा हासिल किए हुए कांग्रेस क्षेत्रीय दलों की पिछलग्गू बनकर रह गई। यूपी में समाजवादी पार्टी, बिहार में लालू यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल, तमिलनाडु में डीएमके, झारखंड में शिबू सोरेन की झारखंड मुक्ति मोर्चा, महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की शिवसेना और शरद पवार की एनसीपी के साथ कांग्रेस पिछलग्गू बनी हुई है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के साथ मिलकर कांग्रेस चुनाव लड़ चुकी है। यहां भी अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस को अपनी इच्छानुसार सीटें दी थीं। हाल में सम्पन्न हुए विधानसभा चुनाव में केरल में

कांग्रेस मुस्लिम लीग के सहारे सत्ता में आई है।कांग्रेस का क्षेत्रीय दलों का पिछलग्गू बनने का दौर राहुल गांधी के समय ही शुरू हुआ था। कांग्रेस के खोते जनाधार और गिरते मनोबल को बचाने में जब राहुल गांधी कामयाब होते नहीं दिखे, तो प्रियंका वाड्रा को भी कांग्रेस का ट्रंप कार्ड बताते हुए मैदान में उतार दिया गया, लेकिन उनका भी जादू चल नहीं पाया। भाई-बहन की जोड़ी भी कांग्रेस की तस्वीर नहीं बदल पाई। यह और बात है कि आज भी कांग्रेस को अर्श से फर्श पर ला देने वाले राहुल गांधी की ही पार्टी के भीतर तूती बोलती है। कांग्रेस का छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा नेता राहुल-प्रियंका के सामने हाथ बांधे खड़ा रहता है, जबकि राहुल के कई फैसले पार्टी के लिए घातक साबित हो चुके हैं। बहरहाल, यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि आज की तारीख तक राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा गांधी का देश और पार्टी को आगे ले जाने में किसी तरह का कोई खास योगदान नहीं है। पार्टी के लिए इन दोनों ने अभी तक कुछ ऐसा नहीं किया, जिससे कांग्रेस आगे बढ़ती दिख रही हो। इसके उलट कांग्रेस लगातार जनाधार खोती जा रही है। सवाल यह है कि कांग्रेस के पतन के लिये जिम्मेदार राहुल गांधी और प्रियंका को भारतीय मीडिया इतना हाईलाइट क्यों करता है, जबकि देश-विदेश में भारत की छवि दागदार करने, राहुल के देश विरोधी ट्वीट और हिंदू विरोधी छवि के कारण जनता इन्हें लगातार नकारती जा रही है। आश्चर्य होता है कि क्यों मीडिया की दुनिया में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा का नाम आज भी प्रमुखता से चमकता रहता है। यह सवाल भारतीय राजनीति और मीडिया के गठजोड़ की उस जटिल गुत्थी को खोलता है, जहां वोट की बजाय व्यूअरशिप और एडवर्टाइजमेंट राज करता है। गहराई से विश्लेषण करें तो पता चल जाता है कि कैसे ये दोनों नेहरू-गांधी परिवार के वारिस बनकर राजनीति में बने हुए हैं। दरअसल, राहुल गांधी की राजनीतिक यात्रा शुरू से ही विवादों और असफलताओं से भरी रही। 2004 में अमेठी से सांसद बने, फिर 2014 और 2019 में हार का सामना करना पड़ा। 2019 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की बुरी हार के बाद उन्होंने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। प्रियंका गांधी ने 2019 में महासचिव बनकर पूर्वी उत्तर प्रदेश संभाला, लेकिन 2022 यूपी विधानसभा चुनाव में पार्टी को महज 2 सीटें मिलीं। 2024 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को 99 सीटें जरूर मिलीं, लेकिन यह राहुल या प्रियंका के व्यक्तिगत करिश्मे से कम, गठबंधन और मोदी विरोधी माहौल से ज्यादा जुड़ा रहा। आंकड़े साफ कहते हैं कि 2014 में कांग्रेस के पास 44 लोकसभा सीटें थी, 2019 में 52, लेकिन राज्य स्तर पर हाहाकार मचा रहा। यूपी में 403 सीटों वाली विधानसभा में 2022 में कांग्रेस को केवल 2 सीटें मिलीं, पंजाब में 2022 विधानसभा चुनाव में पार्टी 92 से घटकर 18 सीटों पर पहुंच गई। हिमाचल में भले कांग्रेस जीती, लेकिन गुजरात में 156 में से केवल 1 सीट मिली। ये आंकड़े दिखाते हैं कि इन दोनों का नेतृत्व पार्टी को मजबूत बनाने में नाकाम रहा। जनाधार का सिकुड़ना भी छिपा हुआ नहीं है। 2014 में कांग्रेस का वोट शेयर 19.5 फीसदी था, 2019 में 19.3 फीसदी, जबकि बीजेपी 38 फीसदी से ऊपर कायम रही। फिर भी मीडिया का फोकस इन पर क्यों रहता है? पहला कारण परिवार का ब्रांड है। नेहरू-गांधी परिवार भारतीय राजनीति का सबसे पुराना राजनीतिक वंश माना जाता है। जवाहरलाल नेहरू से इंदिरा और राजीव गांधी तक, यह नाम ही समाचार बन जाता है। मीडिया हाउस जानते हैं कि राहुल गांधी का कोई बयान चाहे 'चौकीदार चोर है' वाला हो या फिर देश को हिंदू आतंकवाद से खतरा बताने वाला तुरंत वायरल हो जाता है। प्रियंका की साड़ी-स्टाइल या भावुक अपील पर टीआरपी बढ़ती है। 2024 चुनाव में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को कई न्यूज चैनलों ने घंटों कवर किया, जबकि बीजेपी के विकसित भारत अभियान को अपेक्षाकृत कम। टीआरपी के आंकड़े बताते हैं कि राहुल के भाषणों पर डिबेट शो की रेटिंग 2-3 पॉइंट तक ऊपर चली जाती है। क्यों? क्योंकि विवाद बिकता है। राहुल के विदेशी दौरे, अमेरिका और यूके में 'भारत में डेमोक्रेसी खतरे में है' जैसे बयान,अंतरराष्ट्रीय मीडिया भी प्रमुखता से दिखाता है, जिसे भारतीय चैनल भी तुरंत उठाते हैं। दूसरा कारण मीडिया का राजनीतिक एजेंडा माना जाता है। मुख्यधारा मीडिया के एक हिस्से में लेफ्ट-लिबरल विचारधारा का प्रभाव अब भी मजबूत बताया जाता है। कुछ डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म राहुल-प्रियंका को मोदी के विकल्प के रूप में पेश करते हैं। यही वजह है कि 2023 में मणिपुर हिंसा पर राहुल गांधी के मार्च को कई चैनलों ने लाइव दिखाया, जबकि प्रधानमंत्री मोदी के बयान को कम प्राथमिकता मिली। प्रियंका के महिलाओं के लिए न्याय अभियान को फेमिनिस्ट एंगल से हाइलाइट किया गया। कुल मिलाकर यह राहुल-प्रियंका की राजनीति को जिंदा रखने की रणनीति मानी जाती है। अगर कांग्रेस खत्म हो गई, तो विपक्ष के बिना डिबेट शो कैसे चलेंगे? कई न्यूज चैनलों के पैनल में राहुल गांधी को प्रधानमंत्री पद का दावेदार बताया जाता है, भले जनता उन्हें 2014 और 2019 में नकार चुकी हो। 2014 में अमेठी में स्मृति ईरानी से राहुल गांधी की हार, 2019 में रायबरेली में सोनिया गांधी की सीट पर प्रियंका की सक्रियता के बावजूद घटता मार्जिन, और 2024 में राहुल गांधी की वायनाड व रायबरेली दोनों सीटों पर जीत इन सबके बावजूद कांग्रेस 100 का आंकड़ा नहीं छू पाई, जबकि बीजेपी 240 सीटें जीतने में सफल रही।

> आज की तारीख तक राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा गांधी का देश और पार्टी को आगे ले जाने में किसी तरह का कोई खास योगदान नहीं है। पार्टी के लिए इन दोनों ने अभी तक कुछ ऐसा नहीं किया, जिससे कांग्रेस आगे बढ़ती दिख रही हो। इसके उलट कांग्रेस लगातार जनाधार खोती जा रही है। सवाल यह है कि कांग्रेस के पतन के लिये जिम्मेदार राहुल गांधी और प्रियंका को भारतीय मीडिया इतना हाईलाइट क्यों करता है, जबकि देश-विदेश में भारत की छवि दागदार करने, राहुल के देश विरोधी ट्वीट और हिंदू विरोधी छवि के कारण जनता इन्हें लगातार नकारती जा रही है।

लोकतंत्र की ताकत दिखाता है बंगाल का बदलाव

'इंडिया' से बांग्लादेश तक मची हलचल

निज संवाददाता : पश्चिम बंगाल की राजनीति में बड़ा उलटफेर हुआ है। भारतीय जनता पार्टी ने राज्य में अपनी सरकार बना ली है, जो दशकों पुरानी तृणमूल कांग्रेस की सत्ता को समाप्त करने वाला ऐतिहासिक कदम है। इस बदलाव ने न केवल राज्य की सीमाओं को पार किया है, बल्कि पूरे देश और पड़ोसी बांग्लादेश तक हलचल मचा दी है। विपक्षी दलों के नेताओं से लेकर बुद्धिजीवियों तक सबकी चिंता बढ़ गई है। मुस्लिम समुदाय के कुछ मौलाना और कट्टरपंथी तत्व सदमे में हैं, जबकि 'इंडिया' गठबंधन से लेकर बांग्लादेश तक संसद से सड़क तक विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। जबकि बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना जैसी प्रमुख हस्तियां बंगाल में बीजेपी की जीत पर खुशी जता रही हैं, वहीं ममता बनर्जी हार के गम में डूबी हुई हैं।

यह बदलाव राज्य की राजनीति को नई दिशा और सोच दे रहा है। भारतीय जनता पार्टी की जीत ने कांग्रेस और गांधी परिवार को सबसे ज्यादा झटका दिया है। लंबे समय से पश्चिम बंगाल को वामपंथी और उसके बाद तृणमूल के गढ़ के रूप में देखा जाता रहा, लेकिन अब भाजपा का उदय विपक्ष की एकजुटता को चुनौती दे रहा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने इस हार को लेकर चुप्पी साध ली है, लेकिन उनके करीबी सर्कल में चर्चा है कि इससे राष्ट्रीय स्तर पर गठबंधन की रणनीति प्रभावित होगी। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर टिप्पणी की है कि यह जीत अल्पसंख्यक तुष्टिकरण की राजनीति के खिलाफ जनादेश है, लेकिन आंतरिक रूप से वे चिंतित हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी भाजपा मजबूत हो रही है।राष्ट्रीय जनता दल के तेजस्वी यादव ने इसे बिहार के लिए खतरे की घंटी बताया है। वे मानते हैं कि पश्चिम बंगाल का मॉडल बिहार में मुस्लिम-यादव गठजोड़ को कमजोर कर सकता है।

आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली से बयान दिया कि भाजपा की जीत विकास के नाम पर सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का परिणाम है। केजरीवाल की पार्टी, जो खुद अल्पसंख्यक समर्थन पर निर्भर है, अब पंजाब और दिल्ली में अपनी रणनीति पर पुनर्विचार करने को मजबूर हो गई है। बुद्धिजीवी वर्ग, जो लंबे समय से धर्मनिरपेक्षता के नाम पर तुष्टिकरण की राजनीति का समर्थन करता रहा, अब असहज है। टीवी डिबेट्स में वे भाजपा की जीत को लोकतंत्र के लिए खतरा बता रहे हैं, लेकिन जनता का जनादेश उनके तर्कों को कमजोर कर रहा है। पश्चिम बंगाल में मुस्लिम आबादी करीब 27 प्रतिशत है, जो तृणमूल की जीत का प्रमुख आधार रही। भाजपा की सरकार बनने से कई मौलाना और कट्टरपंथी नेता स्तब्ध हैं। मुर्शिदाबाद और मालदा जैसे जिलों में, जहां मुस्लिम बहुल इलाके हैं, वहां अब चिंता की लहर है। कुछ मौलाना ने फतवे जारी करने की धमकी दी है, जबकि मदरसों में बैठकें हो रही हैं। वे डर जता रहे हैं कि भाजपा की नीतियां उनके प्रभाव को कम करेंगी। वास्तव में, भाजपा ने चुनाव में हिंदू एकजुटता के साथ-साथ विकास और सुशासन का एजेंडा चलाया, जिससे अल्पसंख्यक वोट बंट गए। तुष्टिकरण की राजनीति करने वाले नेता अब अपनी रणनीति बदलने पर मजबूर हैं। यह बदलाव लंबे समय से चली आ रही सांप्रदायिक संतुलन को तोड़ सकता है। सबसे चौंकाने वाली बात है पश्चिम बंगाल में बीजेपी की जीत पर बांग्लादेश का मातम। सत्ता परिवर्तन का असर सीमा पार बांग्लादेश ही नहीं, पाकिस्तान में भी दिख रहा है। बांग्लादेश की संसद में विपक्षी नेता पश्चिम बंगाल की भाजपा सरकार को अपने देश के लिए खतरा बता रहे हैं। वे दावा कर रहे हैं कि इससे अवैध घुसपैठ और सीमा विवाद बढ़ेंगे। ढाका की सड़कों पर प्रदर्शन हो रहे हैं, जहां नारे लगाए जा रहे हैं कि भाजपा की सरकार बांग्लादेशी हितों के खिलाफ है। बांग्लादेश की वर्तमान सरकार, जो शेख हसीना के बाद आई है, इस बदलाव से असहज है। उनका मानना है कि ममता बनर्जी की सरकार बांग्लादेश के साथ नरम रुख रखती थी, जबकि भाजपा कठोर रवैया अपनाएगी। नागरिकता कानून और घुसपैठ के मुद्दे पर अब दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ सकता है। विशेषज्ञों का कहना है कि यह हंगामा आंतरिक राजनीति का हिस्सा है, जहां पश्चिम बंगाल का मुद्दा बांग्लादेशी विपक्ष अपने एजेंडे के लिए इस्तेमाल कर रहा है। उधर, भारत में शरणार्थी जीवन जी रही बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना इस सत्ता परिवर्तन से बेहद प्रसन्न हैं। उन्होंने निजी बातचीत में कहा कि भाजपा की जीत उनके लंबे संघर्ष को मजबूती देगी।

हसीना का मानना है कि ममता बनर्जी की सरकार ने बांग्लादेशी कट्टरवादियों को संरक्षण दिया था, जो अब समाप्त होगा। वहीं, ममता बनर्जी हार के सदमे से उबर नहीं पा रही हैं। कोलकाता के निवास पर वे चुपचाप बैठी रहती हैं, जबकि उनकी पार्टी तृणमूल कांग्रेस सड़कों पर चुनावी धांधली के आरोप लगा रही है। वे राज्यपाल के खिलाफ मोर्चा खोल रही हैं और अदालतों में याचिकाएं दायर कर रही हैं। ममता की पार्टी के कार्यकर्ताओं में भटकाव है, कई विधायक भाजपा की ओर झुक रहे हैं। यह स्थिति तृणमूल के भविष्य को अनिश्चित बना रही है।बहरहाल, पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार बनने से राज्य में नई ऊर्जा आई है। नए मुख्यमंत्री ने विकास, बेरोजगारी हटाओ और भ्रष्टाचार मुक्त शासन का वादा किया है।

सिंदूर सहायता योजना और दुर्गा पूजा को राष्ट्रीय उत्सव का दर्जा देने जैसे कदम पहले ही लोकप्रिय हो चुके हैं। लेकिन चुनौतियां भी कम नहीं हैं तृणमूल का विरोध, मुस्लिम बहुल इलाकों में तनाव और बांग्लादेश सीमा पर दबाव। फिर भी, भाजपा का राष्ट्रीय एजेंडा राज्य को केंद्र के करीब लाएगा। केंद्रीय योजनाओं का बेहतर क्रियान्वयन होगा, जैसे आयुष्मान भारत और पीएम आवास। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह जीत 2026 के विधानसभा चुनावों में भाजपा को मजबूत बनाएगी। विपक्ष को अब नई रणनीति बनानी होगी, जहां तुष्टिकरण के बजाय विकास पर जोर देना पड़ेगा। इस सत्ता परिवर्तन ने न केवल पश्चिम बंगाल बल्कि भारतीय राजनीति की धरती हिला दी है। जहां एक ओर खुशी की लहर है, वहीं चिंता और विरोध की धाराएं बह रही हैं। आने वाले दिनों में यह देखना रोचक होगा कि भाजपा कैसे इन चुनौतियों का सामना करती है। कुल मिलाकर, जनता ने बदलाव चुना है, जो लोकतंत्र की ताकत दिखाता है।

दागी शिक्षकों से वसूला जाए वेतन

शिक्षा विभाग का सभी जिलाधिकारियों को आदेश

निज संवाददाता : शिक्षा विभाग ने सभी जिलाधिकारियों को जारी एक महत्वपूर्ण निर्देश में उन दागी उम्मीदवारों की सूची तैयार करने को कहा गया है, जिन्होंने पैसे देकर राज्य-संचालित स्कूलों में शिक्षण और गैर-शिक्षण पद प्राप्त किए थे। विभाग ने जिलाधिकारियों से इन उम्मीदवारों द्वारा सेवा अवधि के दौरान प्राप्त वेतन और उस पर अर्जित ब्याज की गणना करने को भी कहा है। यह राशि राज्य सरकार को वापस की जाएगी, जो अदालती आदेशों का पालन सुनिश्चित करेगा। दागी उम्मीदवार वे हैं जिन्होंने भर्ती परीक्षाओं में खाली या अधूरे उत्तर-पत्र जमा करके नौकरी हासिल की थी। कुछ ने रैंक में हेरफेर या पैनल से बाहर नामांकन के माध्यम से भी पद प्राप्त किए। शिक्षा विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि कलकत्ता उच्च न्यायालय ने 2024 में पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग के लगभग 26,000 स्कूल नौकरियों के पूरे पैनल को रद्द कर दिया था। इसके बाद, उच्चतम न्यायालय ने 2025 में इस फैसले की पुष्टि की। भर्ती प्रक्रिया में भारी अनियमितताओं के कारण यह निर्णय लिया गया था। दोनों अदालतों ने दागी उम्मीदवारों को भुगतान किए गए वेतन और ब्याज की वसूली का निर्देश दिया था। यह वसूली कार्य लंबे समय से लंबित था, जिसे अब राज्य शिक्षा विभाग ने राज्य प्रशासन के उच्चतम अधिकारियों के निर्देशों के बाद शुरू किया है।

जिलाधिकारियों को भेजे गए निर्देशों में यह बताया गया है कि उच्चतम न्यायालय ने 3 अप्रैल, 2025 को अनिवार्य किया था कि 2016 के डब्ल्यूबीएसएससी पैनल में पैसे के बदले नौकरी पाने वाले अयोग्य शिक्षकों को अपना वेतन वापस करना होगा। इस प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य उन लोगों से धन वापस लेना है जिन्होंने अवैध तरीकों से सरकारी पद प्राप्त किए। कोलकाता उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय ने भर्ती प्रक्रिया में गंभीर अनियमितताओं के कारण लगभग 26,000 शिक्षण और गैर-शिक्षण पदों को रद्द कर दिया था। इन रद्द की गई नौकरियों में 18,418 शिक्षण कर्मचारी शामिल थे, जबकि शेष गैर-शिक्षण कर्मचारी थे। अदालतों ने अपने फैसले सुनाते हुए दागी उम्मीदवारों से वेतन और ब्याज की वसूली का स्पष्ट निर्देश दिया था। राज्य सरकार ने इस मुद्दे पर पिछली उपेक्षा के कारण अब शीर्ष अदालत के आदेश को लागू करने का फैसला किया है। प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए भी कदम उठाए जा रहे हैं। कुछ साल पहले, जब अयोग्य शिक्षकों की सूची सार्वजनिक की गई थी, तो यह देखा गया था कि इसमें तृणमूल कांग्रेस के नेताओं के कई रिश्तेदारों और करीबी सहयोगियों के नाम शामिल थे। इस पृष्ठभूमि में, राज्य सरकार ने अब उच्चतम न्यायालय के आदेश को तुरंत लागू करने का निर्णय लिया है। विभाग का लक्ष्य है कि वसूली प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरा किया जाए। यह कदम न्यायिक निर्देशों का पालन सुनिश्चित करेगा और सार्वजनिक धन के दुरुपयोग को रोकने में मदद करेगा।

सुंदरबन के लोगों के जीवन की त्रासदी

रोजी-रोटी के दूसरे तरीकों की कमी की वजह से जान जोखिम में डालने को मजबूर

निज संवाददाता : बंगाल में विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद नई सरकार भी बन गई है। वहीं सुंदरबन के कई इलाकों में रहने वाले लोगों का जीवन बदस्तूर उसी धारा में चल रहा है। वे रोज की तरह मछली पकड़ने, केकड़े पकड़ने या शहद इकट्ठा करने के बाद जंगलों से सुरक्षित लौटने की उम्मीद कर रहे हैं। यहां के लोगों का कहना है कि चुनाव आते हैं और जाते हैं, लेकिन सुंदरबन में उनके लिए ज़िंदगी वैसी ही रहती है। जब भी ये मछुआरे जंगलों से होकर बहने वाली छोटी नदियों में जाते हैं, तो उन्हें बाघ के हमले का खतरा रहता है। फिर भी, कमाई के कुछ ही दूसरे सोर्स होने की वजह से, उनके पास पानी में लौटने के अलावा कोई चारा नहीं होता। सुंदरबन में, नुकसान और बचने की कहानियां दिखाती हैं कि कैसे जंगलों के किनारे रहने वाले परिवार रोज़ी-रोटी के दूसरे तरीकों की कमी की वजह से खतरे में पड़ जाते हैं।

2024 में एक बाघ के हमले में बच गए 58 साल के गौर मंडल ने कहा-यहां गुज़ारा करने के लिए कोई नौकरी नहीं है। सरकार की तरफ़ से इनकम देने की कोई कोशिश नहीं की जा रही है। इसलिए, या तो जंगल में जाना है या दूसरे राज्यों में जाना है। दक्षिण 24-परगना के गोसाबा ब्लॉक के छोटो मोल्ला खाली के रहने वाले गौर, 17 अगस्त की सुबह झिला इलाके के जंगल में केकड़े पकड़ने गए थे। उनके साथ दो और लोग, मनोरंजन मंडल और झोंटू मंडल भी थे। वे घने जंगल में चारे के तौर पर डंडियों के सिरे में केकड़े का चारा डुबो रहे थे। अचानक, बाघ नाव पर कूद गया और गौर के चेहरे के दाहिने हिस्से पर पंजे से मारा, और चप्पू उनके हाथ से गिर गया। गौर और बाघ कमर तक गहरे पानी में गिर गए। जानवर ने उनकी गर्दन पर काट लिया, जिससे वह लगभग बेहोश हो गए। उन्होंने पहले बाघ को अपनी कोहनी से धक्का दिया। हालांकि बाघ ने उन्हें छोड़ दिया, लेकिन वह फिर से उनकी गर्दन पर झपटा। कुछ मिनट तक लड़ाई चलती रही, फिर उसके दो साथी, जो पहले तो सदमे में जम गए थे, नाव को गौर की तरफ ले गए। जब उन्होंने नाव को चप्पू से मारा तो बाघ भाग गया। गौर ने कहा-मैं एक कान से सुन नहीं सकता, और चोट की वजह से मैं अपने सिर या कंधे पर वज़न नहीं उठा सकता। लेकिन मुझे अभी भी नदी में मछली पकड़ने जाना पड़ता है क्योंकि मुझे गुज़ारा करना है। उन्होंने कहा-राज्य में चाहे कोई भी सत्ता में आए, उसे डेल्टा के मछुआरों के लिए रोज़ी-रोटी पक्की करनी होगी। दक्षिण 24-परगना के कुलतली ब्लॉक के कांतामारी के रहने वाले 58 साल के मोंटू विश्वास ने कहा कि वह 30 साल से ज़्यादा समय से मछली पकड़ रहे हैं और उन्हें याद नहीं कि वह कितने लोगों को जानते हैं जो बाघ के हमलों में या तो मर गए या गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्होंने कहा-मैं 15 या 16 साल पहले एक रॉयल बंगाल टाइगर के जबड़े से बच निकला था। बाघ ने 30 से ज़्यादा लोगों पर हमला किया है जिनके साथ मैं मछली पकड़ता था। उनमें से एक कैनिंग के अकबर अली शेख थे। करीबन 12 साल पहले एक सुबह, विश्वास ने शेख के साथ एक खाड़ी में नाव पर चाय पी। विश्वास ने याद करते हुए कहा-बाद में, हाई टाइड के दौरान, हम चामता धुत्रखली जंगल में एक और खाड़ी में गए। हमने कुछ केकड़े पकड़े थे जब हमने लोगों को चिल्लाते हुए सुना। हम 15 से 20 मिनट तक नाव चलाकर उस जगह तक पहुंचे जहां मछुआरों ने कहा था कि एक टाइगर शेख को ले गया था।

उन्होंने कहा-हमें जंगल में जाने के लिए मजबूर होना पड़ता है क्योंकि हमारे परिवार का गुज़ारा करने के लिए काफ़ी काम नहीं है। कुछ सरकारी स्कीम हैं, लेकिन वे सिर्फ़ रिकॉर्ड में हैं। उनकी पत्नी को लक्खी भंडार स्कीम से हर महीने 1,500 रुपए मिलते हैं। उन्होंने कहा कि यह काफ़ी नहीं है। वोट आते-जाते रहते हैं, और नेता वादे करते रहते हैं। कुछ नहीं बदलता। ह्यूमन राइट्स ऑर्गनाइज़ेशन, एसोसिएशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ़ डेमोक्रेटिक राइट्स (एपीडीआर) ने कहा कि सुंदरबन में 200,000 से ज़्यादा लोग मछुआरे हैं और मछली, केकड़े और शहद के लिए जंगल पर निर्भर रहते हैं। दक्षिण 24-परगना में एपीडीआर के सहायक सचिव मिथुन मंडल ने कहा-इतने सालों में, रोड नेटवर्क तो बन गया है, लेकिन रोज़गार के काफ़ी मौके नहीं बने हैं। छोटे-मोटे काम तो हैं, लेकिन उनसे परिवार नहीं चल पाता। इस इलाके के कई लोग भारत के अलग-अलग हिस्सों में माइग्रेंट लेबर के तौर पर काम करते हैं।

उन्होंने आगे कहा-कुछ लोगों के पास ज़मीन के छोटे-छोटे प्लॉट हैं, लेकिन ज़्यादातर लोगों के पास ज़मीन नहीं है। मंडल के मुताबिक, राज्य सरकार ने मई, जून और जुलाई के लिए हर मछुआरे को 5,000 रुपए महीने का अलाउंस देने का ऐलान किया था, जब मछली पकड़ना मना होता है। उन्होंने कहा-हालांकि, पिछले तीन सालों से पेमेंट जारी नहीं किया गया है। कुलतली से तृणमूल कांग्रेस के विधायक और इस साल के उम्मीदवार गणेश चंद्र मंडल ने इसके लिए बीजेपी की सरकार वाली केंद्र सरकार को ज़िम्मेदार ठहराया। मंडल ने कहा-केंद्र का 100-दिन का काम का प्रोग्राम 2021 से रुका हुआ है। हमने हाउसिंग स्कीम के तहत कई लोगों को 1.2 लाख दिए।

गणना कर्मियों को सही तथ्य और जानकारी न देने पर हो सकता है जेल-जुर्माना

22 मई से शुरू होगी जनगणना

निज संवाददाता : आगामी 22 मई से पूरे देश में एक बार फिर जनगणना शुरू हो रही है। पिछली जणगणना वर्ष 2011 में कराई गई थी। उसके बाद देश की आबादी में कितना इजाफा हुआ है, इसका पता लगाने के लिये जनगणना कर्मी 22 मई से लोगों के घर पहुंचना शुरू कर देंगे। आजादी के बाद यह आठवीं जनगणना है। इससे पहले 1951, 1961, 1971, 1981, 1991, 2001, 2011 में भी जनगणना का कार्य हो चुका है। 2021 में कोरोना महामारी के चलते जनगणना का काम नहीं हो पाया था, जो अब 2026 में सम्पन्न होने जा रहा है। जनगणना के लिये सरकार को काफी व्यय और व्यवस्था करनी पड़ती है। इसलिये आम हिन्दुस्तानी भी बाध्य है कि वह जनगणना कर्मी को सही तथ्य और जानकारी प्रदान करें। यदि जनगणना के दौरान कोई पुरुष/महिला किसी तथ्य को जानबूझकर छिपाता/छिपाती है, तो इसका अंजाम सही नहीं होगा। ऐसे लोगों पर जुर्माना लगाया जा सकता है और जेल भी भेजा जा सकता है। मतलब जनगणना कर्मी से कुछ भी छिपाना अब हल्की बात नहीं मानी जाएगी। जनगणना अधिनियम, 1948 के प्रावधानों के अनुसार यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर गलत जानकारी देता है, कोई तथ्य छिपाता है या जनगणना से जुड़े दायित्व का पालन नहीं करता, तो उस पर दंडात्मक कार्रवाई हो सकती है। अधिनियम की धारा 11 के तहत ऐसे मामलों में एक हजार रुपये तक का जुर्माना और तीन साल तक की सजा का प्रावधान है। यही नहीं, यह प्रावधान केवल उत्तरदाता पर ही नहीं, बल्कि प्रगणक पर भी समान रूप से लागू होता है। यदि प्रगणक अपने काम के दौरान मिली जानकारी को बाहर किसी से साझा करता है, तो आरोप साबित होने की स्थिति में उस पर भी कार्रवाई हो सकती है। जनगणना से जुड़ी इस कानूनी व्यवस्था को लेकर इन दिनों प्रगणक और पर्यवेक्षक भी खासे सतर्क हो गए हैं। स्वगणना के दौरान कुछ लोगों द्वारा जानकारी छिपाने या अधूरी जानकारी देने की चर्चाओं ने जनगणना से जुड़े अमले को और अधिक सावधान कर दिया है। अधिकारियों का मानना है कि जनगणना केवल औपचारिक आंकड़ा जुटाने की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि इसके आधार पर सरकारें योजनाएं बनाती हैं, संसाधन तय करती हैं और सामाजिक-आर्थिक स्थिति का आकलन करती हैं। ऐसे में अगर किसी स्तर पर जानकारी गलत दर्ज होती है या जानबूझकर छिपाई जाती है, तो उसका असर पूरी व्यवस्था पर पड़ सकता है। प्रगणकों को निर्देश दिया जा रहा है कि वे घर-घर जाकर दर्ज की जाने वाली सूचनाओं को पूरी गंभीरता से सत्यापित करें। खासकर हाउस लिस्टिंग ब्लॉक में किसी भी तरह की अनियमितता मिलने पर जिम्मेदारी सीधे प्रगणक पर आ सकती है। प्रशासनिक स्तर पर यह माना जा रहा है कि यदि किसी ब्लॉक में परिवारों की संख्या, लोगों की संख्या या अन्य बुनियादी विवरण असामान्य रूप से कम पाए जाते हैं, तो यह संदेह का कारण बन सकता है। ऐसी स्थिति में पुनरीक्षण कराया जा सकता है, ताकि वास्तविक स्थिति सामने आ सके।जनगणना का सबसे बड़ा आधार विश्वास है। सरकार को सही आंकड़े चाहिए और नागरिकों को यह भरोसा होना चाहिए कि दी गई जानकारी सुरक्षित रहेगी। यही कारण है कि जनगणना से जुड़े कर्मचारियों को गोपनीयता के नियमों का कड़ाई से पालन करना होता है। जनगणना में एकत्र की गई सूचनाएं व्यक्तिगत स्तर पर संवेदनशील मानी जाती हैं। किसी भी प्रगणक द्वारा इन तथ्यों को बाहर साझा करना कानून के दायरे में गंभीर लापरवाही माना जाता है। यदि यह साबित हो जाता है कि किसी कर्मचारी ने जानकारी लीक की, तो उसके खिलाफ दंडात्मक प्रावधान लागू हो सकते हैं। इस बार स्वगणना को लेकर भी विशेष चर्चा बनी हुई है। स्वगणना में लोग स्वयं अपने बारे में और अपने परिवार के बारे में जानकारी दर्ज करते हैं। लेकिन यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर कुछ तथ्य छिपा देता है, तो इसका असर अंतिम आंकड़ों पर पड़ता है। कुछ मामलों में लोग आय, शिक्षा, परिवार के सदस्यों की संख्या, निवास की स्थिति या अन्य सामाजिक जानकारी को अधूरा छोड़ देते हैं। ऐसी हरकतें भले ही व्यक्तिगत स्तर पर छोटी लगें, लेकिन जब यह हजारों-लाखों घरों में होती हैं, तो राष्ट्रीय आंकड़ों की विश्वसनीयता प्रभावित हो सकती है। इसी वजह से प्रगणकों को यह भी कहा जा रहा है कि वे केवल फॉर्म भरवाने तक सीमित न रहें, बल्कि जानकारी की संगति भी देखें। अगर किसी घर में लोगों की संख्या बहुत कम दिखाई देती है, जबकि आसपास की परिस्थिति कुछ और संकेत देती है, तो उसे तुरंत चिह्नित किया जा सकता है। कई बार ऐसा भी होता है कि किसी घर में रहने वाले लोग बाहर चले गए हों, या किसी सदस्य का नाम जानबूझकर दर्ज न कराया गया हो। ऐसे मामलों में पुनरीक्षण की प्रक्रिया अपनाकर वास्तविक तथ्य जुटाए जा सकते हैं। प्रशासन का कहना है कि संदेह के आधार पर जांच कराना जनगणना की विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए जरूरी है। हाउस लिस्टिंग ब्लॉक के स्तर पर यह व्यवस्था इसलिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यही जनगणना की प्राथमिक इकाई मानी जाती है। इसी स्तर पर मकानों, परिवारों और निवासियों का प्रारंभिक रिकॉर्ड तैयार होता है। यदि यही रिकॉर्ड गलत या अधूरा हो गया, तो आगे के सभी आंकड़ों में त्रुटि आ सकती है। इसलिए प्रगणकों को साफ निर्देश हैं कि वे किसी भी तरह की लापरवाही न बरतें। यदि किसी ब्लॉक में ज्यादा अनियमितता मिलती है, तो इसकी जवाबदेही तय की जाएगी। इससे न केवल संबंधित प्रगणक की भूमिका सवालों के घेरे में आएगी, बल्कि पर्यवेक्षण व्यवस्था पर भी प्रश्न उठ सकते हैं। अधिकारियों का मानना है कि जनगणना के काम में सतर्कता सिर्फ नियमों की वजह से नहीं, बल्कि सार्वजनिक हित की वजह से भी जरूरी है। देश की योजनाएं, विकास कार्य, स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा सुविधाएं, रोजगार से जुड़े आकलन और कई तरह के संसाधन वितरण जनगणना के आंकड़ों पर निर्भर करते हैं। यदि किसी क्षेत्र की वास्तविक जनसंख्या कम दिखाई जाती है, तो वहां मिलने वाले संसाधनों पर असर पड़ सकता है। इसी तरह यदि किसी समुदाय, बस्ती या इलाके की सही गिनती नहीं हुई, तो वे लाभ से वंचित रह सकते हैं।

इसलिए जनगणना अमले को यह समझाया जा रहा है कि हर विवरण की अहमियत है। एक गलत प्रविष्टि भी पूरे क्षेत्र की तस्वीर बदल सकती है। यही वजह है कि प्रगणक, पर्यवेक्षक और संबंधित अधिकारी अब अधिक चौकन्ने हो गए हैं। वे इस बात पर जोर दे रहे हैं कि जनता भी सहयोग करें और सही जानकारी दे। जनगणना को लेकर किसी तरह की अफवाह, डर या लापरवाही से बचना होगा। विशेषज्ञों का कहना है कि जनगणना केवल सरकारी दस्तावेज नहीं, बल्कि देश की सामाजिक और आर्थिक वास्तविकता का आईना है। इसमें जितनी सच्चाई होगी, नीति निर्माण उतना ही मजबूत होगा। अगर लोग अपनी जानकारी छिपाते हैं, तो वे सिर्फ नियम का उल्लंघन नहीं करते, बल्कि अपने इलाके और समुदाय के हिस्से के अधिकारों को भी कमजोर कर सकते हैं। इसी तरह यदि जनगणना कर्मी गोपनीयता भंग करते हैं, तो वे पूरी प्रक्रिया की विश्वसनीयता को नुकसान पहुंचाते हैं।

मनमर्जी से सरकारी दफ्तर आने वालों की अब खैर नहीं!

कार्य संस्कृति बहाल करने को शुभेंदु सरकार का फरमान

निज संवाददाता : मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की अगुवाई वाली नई सरकार ने एक नया फरमान जारी किया है। इसके तहत सरकारी दफ्तरों में कार्य संस्कृति बहाल करने पर जोर दिया गया है। अब से बंगाल के सरकारी ऑफिसों में मनमर्जी से आने और जाने के दिन अब गए। शुभेंदु अधिकारी की सरकार में अब मनमर्जी से आना और दोपहर 12:00 बजे के बाद ऑफिस में घुसना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसको लेकर राज्य सरकार ने सख्त निर्देश जारी किए। इसमें राज्य सरकार के न्यायिक विभाग के सभी कर्मचारियों के लिए ऑफिस आने और जाने का समय अनिवार्य कर दिया गया है।

हालांकि तकनीकी रूप से पहले भी ऐसे समय निर्धारित थे, लेकिन सूत्रों का कहना है कि इन नए दिशानिर्देशों को जारी करने का मतलब है कि इस बार नियमों को सख्ती से लागू किया जाएगा। ऐसी चर्चा है कि इस नियम को धीरे-धीरे अन्य सरकारी विभागों में भी बढ़ाया जा सकता है। राइटर्स बिल्डिंग में तैनात न्यायिक विभाग के सभी कर्मचारियों के लिए एक निर्देश जारी किया गया। इसमें साफ तौर पर कहा गया है कि सभी को सुबह 10:15 बजे तक ऑफिस पहुंच जाना चाहिए। किसी को भी शाम 5:15 बजे से पहले ऑफिस छोड़ने की अनुमति नहीं है। आधिकारिक अधिसूचना में आगे स्पष्ट किया गया है कि यह निर्देश यह सुनिश्चित करने के लिए जारी किया गया है कि सरकार से संबंधित सभी काम कुशलतापूर्वक और निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरे हों। यह बात भी सामने आई है कि ऑफिस के लिए निर्धारित समय होने के बावजूद अब तक उपस्थिति के मामले में सख्ती की साफ कमी थी।

काफी समय से इस मुद्दे को लेकर अलग-अलग विभागों में कई शिकायतें जमा हो गई थीं। कई लोगों ने आरोप लगाया है कि कर्मचारी जब मन करता ऑफिस आते थे और अपनी मर्जी से ही चले जाते थे। ऐसी शिकायतें कोई नई बात नहीं हैं। कुछ लोगों का गैर-जिम्मेदाराना रवैया अक्सर पूरे कार्यबल की प्रतिष्ठा को धूमिल कर देता है। राज्य सरकार के एक सूत्र के अनुसार, ये कड़े कदम विशेष रूप से ऐसी अनियमितताओं पर अंकुश लगाने के लिए लागू किए जा रहे हैं। फिलहाल यह पहल न्यायिक विभाग से शुरू की गई है। ऐसी चर्चा है कि इन नियमों को अंततः अन्य सरकारी विभागों में भी बढ़ाया जा सकता है। राज्य में सत्ता परिवर्तन के बाद मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने इस आदर्श वाक्य को बढ़ावा दिया है कि मैं नहीं, बल्कि हम। अब मुख्य चुनौती सरकारी ऑफिस के भीतर एक मजबूत कार्य संस्कृति को बहाल करना है। कई पर्यवेक्षकों का मानना है कि मौजूदा पहल ठीक उसी लक्ष्य को हासिल करने के प्रयासों की शुरुआत है।

'ज्ञान, भाषिक और तकनीकी दक्षता से हिंदी में रोजगार की विपुल संभावनाएं हैं'

विद्यासागर विश्वविद्यालय में कार्यशाला एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम

निज संवाददाता : विद्यासागर विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग की ओर से 'हिंदी में रोजगार की संभावनाएं' विषय पर कार्यशाला एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर चतुर्थ सेमेस्टर के विद्यार्थियों के लिए विदाई समारोह का भी आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत टी. दिव्यांशी और प्रीति सिंह द्वारा सरस्वती वंदना के साथ हुई। स्वागत भाषण देते हुए विभागाध्यक्ष डॉ. प्रमोद कुमार प्रसाद ने कहा कि विश्वविद्यालय केवल सर्टिफिकेट प्रदाता मात्र नहीं होता है बल्कि यह हमारे व्यक्तित्व को गढ़ता भी है।

हिंदी में रोजगार की अपार संभावनाएं हैं बशर्ते उसके लिए हम अपनी पात्रता अर्जित करें। विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर डॉ. संजय जायसवाल ने कहा कि हिंदी पढ़ने वाले विद्यार्थियों के समक्ष असंख्य संभावनाएं हैं। हमें अपनी भाषा ,विषय का ज्ञान और तकनीकी रूप से दक्षता अर्जित करने की जरूरत है।

हिंदी पढ़ने वाले शिक्षक, अनुवादक, राजभाषा अधिकारी, हिंदी सहायक, टाइपिस्ट, दुभाषिए, फ्रीलांसर, रिपोर्टर, एंकर, कंटेंट लेखक आदि में अपना कैरियर बना सकते हैं। विभाग के सहायक प्रोफेसर डॉ. श्रीकांत द्विवेदी ने कहा कि आज आनंद के साथ दुख का भी क्षण है लेकिन यह एक ऐसा समय भी है जब आप अपने अंदर झांक कर इसकी तलाश करें कि आपको क्या करना है और आप कैसे उसे हासिल कर सकते हैं। विभाग की शोधार्थी उष्मिता गौड़ ने कहा कि आज आपके लिए एक बड़ा दिन है। आपको यह सुनिश्चित करना है कि यह डिग्री आपके लिए महज एक डिग्री तक सीमित न रहे बल्कि इसके सहारे आप अपनी मंजिल प्राप्त करें। रूपेश कुमार यादव ने कहा कि किसी भी क्षेत्र में हम अपनी उपस्थिति तभी दर्ज कर पाते हैं जब हम लगन से उस क्षेत्र में अपना योगदान देते हैं। आज विभाग से विदा हो रहे सभी विद्यार्थी अपने सपनों को साकार करने के लिए ईमानदारी और लगन से प्रयास करें, सफलता जरूर मिलेगी। सुषमा कुमारी ने कहा कि हमें सबसे पहले यह तय करना चाहिए कि हम किस क्षेत्र में जाना चाहते हैं और उसके अनुसार तैयारी करने की दिशा में बढ़ना चाहिए। रिया श्रीवास्तव ने कहा कि आज का दिन आपके लिए दुख भरा जरूर है लेकिन साथ ही यह आपको अपने भविष्य के प्रति सचेत रहने का संकल्प भी है। इस अवसर पर अर्जुन सार्की ने गीत और निसार अहमद, अंजली शर्मा, रूथ कर ने काव्य पाठ किया। इस अवसर पर प्रियांशु ठाकुर, रंभा कुमारी, प्रिया मिश्रा, काजल ठाकुर ने विशेष सहयोग दिया। कार्यक्रम का संचालन सुषमा कुमारी, शबाना खातून और प्रिंशु ठाकुर ने किया।

जलपाईगुड़ी की गीता को मिला भारत का सबसे बड़ा 'नर्सिंग अवॉर्ड'

निज संवाददाता : जलपाईगुड़ी की नर्स गीता कर्माकर को फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवॉर्ड मिला। जलपाईगुड़ी से शुरू हुआ उनके करियर का सफ़र अब देश के सबसे बड़े सम्मान से पहचाना जाता है। इंटरनेशनल नर्स डे पर नई दिल्ली में आयोजित एक खास समारोह में, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जलपाईगुड़ी की नर्स गीता कर्माकर को प्रतिष्ठित फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवॉर्ड 2026 से सम्मानित किया। यह सम्मान 4 दशकों से ज़्यादा समय से लोगों की सेवा में खुद को समर्पित करने की एक अनोखी पहचान है।.

जमीनी स्तर पर सेवा का एक शानदार उदाहरण

गीता कर्माकर जलपाईगुड़ी के बेलाकोबा रूरल हॉस्पिटल में एक ऑक्ज़ीलियरी नर्स मिडवाइफ (एएनएम) हैं। उनके करियर के बिल्कुल आखिर में मिले इस सम्मान ने उनकी चार दशकों की कड़ी मेहनत को सफल बना दिया। रिटायरमेंट से कुछ हफ़्ते पहले ही उन्हें राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने इस अवॉर्ड के लिए नॉमिनेट किया था। उनके साथ काम करने वालों और सीनियर अधिकारियों का दावा है कि वह सिर्फ़ एक नर्स नहीं थीं, बल्कि इलाके के लोगों के लिए उम्मीद की किरण थीं।

मुश्किल समय में भी डटी रहीं

स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के मुताबिक, गीता ने जलपाईगुड़ी के दूर-दराज के गांवों में वैक्सीनेशन प्रोग्राम और इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी में बहुत अहम भूमिका निभाई। उन्होंने ट्यूबरक्लोसिस (टीबी), थैलेसीमिया और रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए बहुत मेहनत की है। मीडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक, जलपाईगुड़ी सदर के ब्लॉक हेल्थ ऑफिसर प्रीतम बसु ने कहा-वह बहुत मेहनती और कुशल थीं। वह बहुत कम छुट्टी लेती थीं। मरीज़ों के साथ उनका इंसानियत भरा बर्ताव और रिकॉर्ड रखने का तरीका हम सभी के लिए एक क्रेडिट है।

वैक्सीन स्टोरेज में एक्सपर्ट

गीता ने एक बहुत ही ज़रूरी ज़िम्मेदारी संभाली। वह हमेशा यह पक्का करने के लिए तैयार रहती थीं कि वैक्सीन सही टेम्परेचर पर स्टोर हों और ब्लॉक के हर कोने तक अच्छी क्वालिटी के साथ पहुँचें। उनकी एक्सपर्टीज़ यूनिवर्सल इम्यूनाइज़ेशन प्रोग्राम (यूआईपी) की सफलता में एक बड़ा स्तंभ थी।

नर्सिंग की दुनिया की शान

गौरतलब है कि सिर्फ़ 15 नर्सों को यह खास सम्मान मिला है। इनमें पश्चिम बंगाल की प्रतिनिधि के तौर पर गीता कर्माकर का नाम सबसे ऊपर था। उन्हें राष्ट्रपति से पुरस्कार मिला।

चीतों को रास आने लगी है कूनो नेशनल पार्क...

(पेज 5 का शेष)

2008 में नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी से अनुमति मिलने के बावजूद यह प्रस्ताव दशकों से लटका रहा लेकिन मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के कार्यकाल में इसे मंजूरी मिली। इतना ही नहीं पुरातत्वविद् विष्णु श्रीधर वाकणकर के नाम पर इसका नामकरण कर उन्होनें इसे सांस्कृतिक गौरव से भी जोड़ा। मार्च-2025 में माधव टाइगर रिजर्व को प्रदेश का 9वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। चीतों का पुनर्वास घास के मैदानों के पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करता है, शिकार प्रबंधन में मदद करता है और अन्य वन्यजीवों के लिए भी लाभ पैदा करता है। कूनो में चीतों की आमद बढ़ने के साथ ही इसे अब पर्यटन स्थल के रूप में भी विकसित किया जा रहा है, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा। प्रोजेक्ट चीता' की अपार सफलता के बाद भारत में दशकों बाद चीतों की वापसी ने यह संदेश दिया है कि यदि सही वैज्ञानिक प्रबंधन और राजनीतिक प्रतिबद्धता हो तो विलुप्त प्रजातियों का पुनर्वास संभव है। चीतों को क्वारंटीन एवं अनुकूलन प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद गांधी सागर एवं नौरादेही जैसे अन्य अभयारण्यों में भी बसाने की भी सरकार ने पूरी तैयारी की जा रही है। अब कूनो को ग्लोबल ब्रीडिंग सेंटर के रूप में विकसित करने की दिशा में तेजी से कार्य चल रहा है। इसके साथ ही गांधी सागर वाइल्डलाइफ सेंचुरी को चीतों के दूसरे आवास और नौरादेही वाइल्डलाइफ सेंचुरी को तीसरे बड़े चीता लैंडस्केप के रूप में भी विकसित किया जा रहा है। बीते दिनों श्योपुर में कूनो नेशनल पार्क के क्वारंटीन बाड़े से मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने दो मादा चीतों को कूनो नदी के समीप स्थित साइट से खुले जंगल में मुक्त किया जिसने मध्यप्रदेश के वन्यजीव संरक्षण इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ने का काम किया है। ये चीते भी अब कूनो के वातावरण में तेजी से घुल-मिल जाएंगे। मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि मध्यप्रदेश की धरती ने चीतों को अनुकूल वातावरण उपलब्ध कराकर उन्हें पुनर्स्थापित करने का महत्वपूर्ण कार्य कर अपने परिवार का हिस्सा बनाया है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने लगभग साढ़े तीन वर्ष पहले कूनो में चीता प्रोजेक्ट की शुरुआत की थी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि नाइजीरिया, दक्षिण अफ्रीका और अब बोत्सवाना से लाए गए चीतों के पुनर्स्थापन को निरंतर सफलता मिल रही हैं और आज प्रदेश ने देशभर में चीता स्टेट के रूप में पहचान बनाई है।

कूनो में इन चीतों के सफल प्रजनन से भरोसा बढ़ा है कि यह परियोजना न केवल वन्यजीव संरक्षण का प्रतीक है, बल्कि भारत की पर्यावरणीय प्रतिबद्धता और वैश्विक सहयोग का उदाहरण अनुपम उदाहरण भी पूरे देश के सामने प्रस्तुत करता है। कूनो में प्रोजेक्ट चीता की सफलता हर नए शावक के जन्म के साथ मध्यप्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार और पर्यटन को नई गति देगी।

शुभेंदु ने बचपन के दर्जी को दिया सम्मान

'रविदा' की बनाई पंजाबी पहनकर ली शपथ

निज संवाददाता : कांथी में एक छोटी सी टेलरिंग की दुकान में बैठे रवींद्र चौधरी, जिन्हें सब रविदा के नाम से जानते हैं, आज भी पुराने दिनों को याद करते हैं। जब वे आठवीं कक्षा में थे। तब से शुभेंदु अधिकारी कपड़े बनवाने उनकी दुकान पर आते थे। रविदा ने उस शांत लड़के को कभी बातें करते नहीं देखा। जब भी उन्हें समय मिलता, वे रामकृष्ण मिशन चले जाते। शुभेंदु को बचपन से ही रेडीमेड कपड़े पहनने की आदत थी और रविदा ने कहा कि यह आदत आज भी नहीं बदली है।

अब वह लड़का बंगाल का मुख्यमंत्री है। ब्रिगेड परेड मैदान में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते समय शुभेंदु ने जो पंजाबी कुर्ता पहनी थी, वह भी रविदा ने ही बनाई थी। पता चला कि रवींद्र ने शुभेंदु के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के समय जो पंजाबी का एक्स्ट्रा कपड़ा पहना था, उसे आशीर्वाद के तौर पर संभालकर रखा है। कांथी का यह पुराना टेलर शुभेंदु को याद करते हुए भावुक हो गया। उसके मुताबिक, जिले के कई राजनीतिक नेता अब उसकी दुकान पर अपने कपड़े बनवाने आते हैं क्योंकि शुभेंदु ने अधिकारी के लिए पंजाबी बनाई थी। लेकिन उसने कई लोगों को बड़े मुकाम पर पहुंचकर अपने पुराने रिश्ते भूलते देखा है। शुभेंदु अधिकारी इस मामले में बिल्कुल अलग हैं। कांथी से राइटर्स बिल्डिंग पहुंचने के बाद भी वह रविदा को नहीं भूले, और यह टेलर इसे अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी कामयाबी मानता है।

रविदा ने कहा कि वह शुभेंदु के लिए फुल स्लीव्स से लेकर हाफ स्लीव्स तक सभी तरह की खादी पंजाबी बनाते हैं। कपड़ा कोलकाता से आता है। मुख्यमंत्री को अपने कपड़ों में चमक-दमक का कोई खास शौक नहीं है, लेकिन अगर उनमें हल्का सा दाग भी लग जाए तो वह उनका इस्तेमाल नहीं करते। वह बहुत समय से चाहते थे कि एक दिन बंगाल की मुख्यमंत्री के लिए कपड़े बनाएं। उन्होंने शुभेंदु अधिकारी के शपथ ग्रहण समारोह में पंजाबी परिधान पहनकर अपना सपना पूरा किया।

बर्तन मांजकर 2,500 महीना कमाने वाली घरेलू कामगार बनी विधायक

कालिता मांझी ने कायम की मिसाल

निज संवाददाता : जिनके हौसले बुलंद होते हैं, उनकी जीत निश्चित होती है कठिनाइयां भी हार जाती हैं, मेहनत जिनकी मजबूत होती है बंगाल विधानसभा चुनाव में इस बात को साबित किया है सुदूर ग्रामीण इलाके की एक साधाराण महिला ने, जो लोगों के घरों में बर्तन मांजकर अपनी आजीविका चलाती है। इस बार के चुनाव में इसी महिला की एक बेहद प्रेरक कहानी सामने आई है। राज्य में बीजेपी की प्रचंड लहर के बीच एक ऐसी जीत हुई है जिसकी चर्चा हर तरफ हो रही है। चुनाव में कालिता मांझी नाम की इस महिला ने जीत हासिल की है, जिनका नाम सुर्खियों में छाया हुआ है। कालिता दूसरों के घरों में बर्तन मांजने और साफ-सफाई का काम करती थीं, लेकिन अब विधायक चुन ली गई हैं। आउसग्राम सीट से कालिता मांझी, जो महज 2,500 महीना कमाने वाली घरेलू कामगार थीं, अब विधायक बन गई हैं। गुस्कारा नगर पालिका की रहने वाली मांझी चार घरों में काम करती थीं, लेकिन उनकी जमीनी पकड़ और जनता से जुड़ाव ने उन्हें राजनीति में खास पहचान दिलाई। कालिता मांझी की जीत बीजेपी के लिए एक व्यापक जनादेश के साथ आई है, जिसने राज्य में सत्ता हासिल की है। मांझी ने 1,07,692 वोट हासिल कर अपने प्रतिद्वंदी श्यामा प्रसन्ना लोहार को 12,535 वोटों के अंतर से हराया। उनकी जीत ने राज्य में व्यापक राजनीतिक बदलाव के बीच जमीनी स्तर के उम्मीदवारों को बढ़ावा देने के बीजेपी के प्रयासों को रेखांकित किया है। उनकी उम्मीदवारी पहले ही चर्चा में थी क्योंकि वह बेहद साधारण पृष्ठभूमि से आती हैं। यह जीत सामाजिक और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए उम्मीद की नई किरण मानी जा रही है। मांझी ने 2021 के विधानसभा चुनाव में भी किस्मत आजमाई थी, लेकिन तब उन्हें तृणमूल कांग्रेस के अभेदानंद थंडर से 11,815 वोटों से हार का सामना करना पड़ा था। हालांकि, पार्टी ने उन पर भरोसा बनाए रखा और इस बार उनकी मेहनत रंग लाई। घरेलू कामगार से विधायक बनीं बीजेपी की कलिता मांझी ने अपनी जीत के बाद भी सादगी नहीं छोड़ी। सोमवार देर रात जीत का प्रमाण पत्र मिलने के बाद जब वह घर लौटीं, तो उनका स्वागत किसी भव्य जश्न या दावत के साथ से नहीं हुआ। उन्होंने बताया 'मुझे रात 10:30 बजे के बाद अपना जीत का प्रमाण पत्र मिला। मैंने मुश्किल से कुछ खाया था और दिनभर के तनाव के बाद मुझे बहुत भूख लगी थी। मैंने अपनी सास के हाथ का बना 'आलू-पोटोलर झोल' खाया'। मंगलवार (5 मई) को विधायक बनने के अगले ही दिन, मांझी ने कपड़े धोने और अन्य घरेलू कामों में खुद को व्यस्त रखा। कई हफ्तों से चुनाव प्रचार में व्यस्त रहने के बाद उन्होंने सामान्य दिनचर्या अपनाई। एक धार्मिक हिंदू होने के कारण वह हर मंगलवार व्रत रखती हैं, इसलिए उन्होंने उस दिन कुछ भी नहीं खाया। कलिता मांझी का जीवन संघर्षों से भरा रहा है। साल 2006 में उनकी शादी एक प्लंबर से हुई थी। परिवार की आर्थिक स्थिति बेहद साधारण रही है। शादी के बाद वह गुस्कारा इलाके में घरेलू कामगार के रूप में काम करती रहीं। दो घरों में काम कर वह हर महीने करीब 4,500 रुपये कमाती थीं। इसके बावजूद उन्होंने राजनीति में सक्रिय भागीदारी जारी रखी। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषणों से प्रभावित होकर उन्होंने राजनीति में कदम रखा। घरेलू सहायिका का काम करने के बावजूद वो अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए बीजेपी के सभी कार्यक्रमों में भाग लेती थीं। उन्होंने बताया कि दो घरों में काम करने के साथ-साथ पार्टी के काम को संतुलित करना मुश्किल था। जहां उनकी मासिक आय 4,500 रुपए थी। कलिता मांझी ने कहा कि वो जीत से बहुत खुश हैं और अपने जैसे गरीब लोगों के लिए काम करना चाहती हैं। उन्होंने कहा 'मैं इतनी उत्साहित हूं कि पिछले कुछ दिनों से ठीक से सोए बिना भी मुझे थकान महसूस नहीं हो रही है। मांझी ने कहा-मुझे विश्वास है कि बीजेपी महिलाओं और गरीबों का उत्थान कर सकती है और सभी महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित कर सकती है।

हल करो हीरो बनो का उत्तर

1.कैथोड रे दोलनदर्शी, 2. बैकलाइट कम बिजली की खपत करती है, 3.सभी तीन, 4.एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर, 5.3200,

संपादकीय

बंगाल सरकार के उद्योगों को बढ़ावा देने वाले नए कदम और आगे की चुनौतियां

बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ मंत्री समिक भट्टाचार्य का हाल ही में पश्चिम बंगाल के लिए एक पूरी औद्योगिक नीति की ज़रूरत के बारे में दिया गया बयान, शायद नई चुनी हुई सरकार की प्राथमिकताओं की सूची में सबसे ज़रूरी चीज़ को बताता है। पुनरुद्धार योजना में एक ज़रूरी चीज़ तेज़ी से औद्योगीकरण के लिए एक टेम्पलेट होना चाहिए। लेफ्ट फ्रंट के शासन के शुरुआती सालों में, बंगाल ने खेती में अच्छा किया था: यह सेक्टर अभी भी राज्य की इकॉनमी का मुख्य आधार बना हुआ है। सिंगूर और नंदीग्राम में औद्योगिक परियोजनाओं के लिए को राजनीतिक रूप से बंद करने से निवेशक पश्चिम बंगाल आने से कतराने लगे। लेफ्ट फ्रंट की राजनीतिक उत्तराधिकारी, तृणमूल कांग्रेस का रिकॉर्ड इस मामले में काफ़ी नहीं था। इसलिए, जब बंगाल के औद्योगीकरण की ज़रूरत की बात आती है, तो इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। भट्टाचार्य ने कहा है कि एक असरदार औद्योगिक नीति में ज़मीन अधिग्रहण को रेगुलेट करने वाले कानूनों, जैसे कि अर्बन लैंड (सीलिंग एंड रेगुलेशन) एक्ट में बदलाव, साथ ही स्पेशल इकोनॉमिक ज़ोन बनाना, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को मंज़ूरी देना वगैरह शामिल होंगे। नई सरकार को पता होना चाहिए कि यह कहना जितना आसान है, करना उतना ही मुश्किल है : इस मामले में कई बड़ी चुनौतियों का सामना करना होगा। सबसे बड़ी और शायद सबसे बड़ी चुनौती ज़मीन से जुड़ी है। बंगाल में 82 फीसदी ज़मीन छोटे किसानों और मार्जिनल किसानों के पास है। उनमें से ज़्यादातर के लिए, ज़मीन सिर्फ़ बेचने लायक एसेट नहीं है। यह उनके जीवन भर इनकम कमाने वाला एकमात्र एसेट है। इस मुद्दे को उस तरह से देखना, जैसा पहले लेफ्ट फ्रंट ने, मान लीजिए नंदीग्राम में किया था, बहुत बुरा होगा : औद्योगिक परियोजनाएं के लिए खेती की ज़मीन लेने का यह तरीका नहीं है। टीएमसी ने दूसरी तरफ़ का रास्ता चुना, ज़मीन लेने के खिलाफ़ एक संरक्षणवादी ढाल बनाई जिससे राज्य के औद्योगीकरण के मौकों को नुकसान पहुंचा। यह भी आगे बढ़ने का रास्ता नहीं है। नई सरकार को ज़मीन लेने की समस्या से सावधानी और सेंसिटिविटी से निपटना होगा। ज़बरदस्ती या संरक्षणवाद को मानने के बजाय, कल्पनाशील, हमदर्दी वाले और सहभागी समाधान को प्राथमिकता देनी होगी। अगर सरकार इस चुनौती को हल करने में सफल हो जाती है राज्य के लिए यह ज़रूरी है तो बंगाल के औद्योगीकरण के रास्ते में आने वाली दूसरी रुकावटें जैसे निवेशकों का भरोसा वापस लाना, सुस्त वर्क कल्चर और उससे जुड़े सेक्टर्स को फिर से खड़ा करना भी दूर हो सकती हैं।

नीट परीक्षा कांड : कब थमेगीं शिक्षा माफिया की साजिशें?

निज संवाददाता : नीट पेपर लीक के बाद परीक्षा रद्द होने की घटना को लेकर केंद्र सरकार की शिक्षा व्यवस्था पर एक बार फिर से सवालिया निशान लग गया है। इस मुद्दे पर विपक्षी भी मोदी सरकार पर हमलावर है। वहीं, तीन मई को संपन्न हुई नीट अंडर ग्रेजुएट परीक्षा पर एक बार फिर ग्रहण लग गया है। देशभर के लाखों छात्रों की उम्मीदों पर पानी फिर गया, जब नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने परीक्षा रद्द करने का ऐलान कर दिया। नीट परीक्षा में करीब 24 लाख परीक्षार्थी बैठे थे। पेपर लीक की खबरों ने पूरे सिस्टम को हिला दिया। राजस्थान से पेपर आउट होने की अफवाहें तेज हैं और विपक्ष ने इसे लेकर मोदी सरकार पर सीधा हमला बोल दिया। छात्र सड़कों पर उतर आए, आक्रोश की लहर दौड़ गई। सरकार ने आनन-फानन में नीट पेपर लीक मामले की जांच सीबीआई से कराने का आदेश दे दिया है, लेकिन सवाल यह है कि आखिर बार-बार ऐसा क्यों हो रहा है? शिक्षा माफिया की साजिशें कब थमेगी? यह कोई नई घटना नहीं। पिछले सालों में कई महत्वपूर्ण परीक्षाओं के पेपर लीक हो चुके हैं। इन घटनाओं ने न सिर्फ छात्रों का भविष्य दांव पर लगा दिया, बल्कि राजनीतिक घमासान भी खड़ा कर दिया। सवाल यह भी उठ रहा है कि क्या परीक्षा प्रणाली में सुधार की बातें बेईमानी साबित हो रही हैं? क्या सरकार भरोसा दिला सकती है कि दोबारा परीक्षा लीक नहीं होगी? बात नीट कांड की शुरुआत कैसे हुई, से की जाए तो तीन मई को सुबह नौ बजे शुरू हुई परीक्षा के कुछ घंटों बाद ही सोशल मीडिया पर पेपर के सवाल वायरल हो गए। राजस्थान के सीकर और जयपुर इलाकों से लीक की पुष्टि हुई। तत्पश्चात, पुलिस अब तक आठ लोगों को गिरफ्तार भी कर चुकी है, जिनमें परीक्षा केंद्र के कुछ कर्मचारी और दलाल शामिल हैं। ये गिरफ्तारियां साजिश के एक बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश कर रही हैं। छात्रों का कहना है कि बिहार, गुजरात और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में भी पेपर पहले से बिक रहा था। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए ने रद्दीकरण का फैसला लेते हुए नई तारीख जल्द घोषित करने का वादा किया है, लेकिन छात्रों का गुस्सा ठंडा होने का नाम नहीं ले रहा। दिल्ली, मुंबई और पटना में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। परिवार वाले चिंतित हैं कि दोबारा परीक्षा का बोझ कैसे झेलें।पिछले सालों के काले अध्याय याद आते हैं, जब परीक्षा प्रणाली पर सेंध लग चुकी थी। 2015 में वाइब्रेंट गुजरात के दौरान आयोजित जीएलओई परीक्षा का पेपर लीक हुआ। सैकड़ों उम्मीदवारों को फायदा पहुंचा। फिर 2021 में बिहार के बीपीएससी परीक्षा का मामला सामने आया, जहां पेपर सॉल्वर गिरोह ने हल्ला बोल दिया। 2022 में यूपीटीईटी का पेपर लीक हुआ, जिसके बाद परीक्षा रद्द करनी पड़ी। उत्तर प्रदेश सरकार ने जांच के आदेश दिए, लेकिन दोषियों को सजा मिलने में देरी हुई। इसी साल फरवरी में रोहिणी परीक्षा का पेपर भी लीक हो गया। बिहार में नीट पीजी का कांड तो सुर्खियों में रहा। सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप कर परीक्षा स्थगित की। महाराष्ट्र में एमपीएससी का पेपर लीक होने से हड़कंप मच गया। ये घटनाएं बताती हैं कि शिक्षा माफिया का जाल कितना गहरा है। ये गिरोह परीक्षा केंद्रों के अंदरूनी लोगों से सेटिंग कर पेपर हासिल कर लेते हैं और अमीर छात्रों को बेच देते हैं। इन पेपर लीक मामलों पर राजनीति का खेल हमेशा चरम पर रहता है। विपक्ष इसे सरकार की नाकामी बताकर हमला बोलता है। इस बार नीट रद्दीकरण के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ट्वीट कर कहा कि मोदी सरकार छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ कर रही है। राहुल गांधी ने संसद में बहस की मांग की। आप के अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में छात्रों का साथ देते हुए शिक्षा मंत्री पर सवाल उठाए। वहीं भाजपा ने इसे राज्य सरकारों की साजिश बताया, खासकर राजस्थान और बिहार में। 2022 के यूपीटीईटी कांड में सपा ने योगी सरकार को घेरा था, जबकि भाजपा ने विपक्षी राज्यों को जिम्मेदार ठहराया। बिहार में नीट पीजी लीक पर आरजेडी और जदयू ने नीतीश कुमार सरकार पर तीर चलाए। हर बार चुनावी मौसम में ये मामले राजनीतिक हथियार बन जाते हैं। पार्टियां वोट बैंक के लिए छात्र आंदोलनों का फायदा उठाती हैं, लेकिन स्थायी समाधान कोई नहीं देता। यह राजनीतिक नौटंकी छात्रों के दर्द को और बढ़ा देती है। वैसे, पेपर लीक कराने वालों के खिलाफ कार्रवाई का सिलसिला लंबा है, लेकिन नाकाफी। पुलिस अक्सर गिरफ्तारियां तो करती है, मगर सजा मिलना मुश्किल होता है। 2022 के यूपीटीईटी मामले में एसटीएफ ने 15 लोगों को पकड़ा, लेकिन अदालत में केस लंबा खिंच गया। बिहार में 2024 के बीपीएससी कांड में 20 से ज्यादा गिरफ्तारियां हुईं, कई को जमानत मिल गई। राजस्थान पुलिस ने नीट मामले में अब तक आठ को हिरासत में लिया, लेकिन मास्टरमाइंड फरार हैं। कानून में सख्त प्रावधान हैं। पब्लिक एग्जामिनेशन अथॉरिटी एक्ट 2024 के तहत पेपर लीक पर दस साल की सजा और जुर्माना है। फिर भी अमल कमजोर है। सॉल्वर गिरोहों पर नकेल कसने के लिए विशेष अदालतें बनाई गईं, लेकिन भ्रष्टाचार की जड़ें गहरी हैं। कई मामलों में अधिकारी ही शामिल पाए गए, जिससे जांच प्रभावित होती है। कार्रवाई दिखावटी रह जाती है। परीक्षा लीक मामले में न्यायपालिका ने कई बार सख्त रुख अपनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने नीट पीजी लीक पर केंद्र को फटकार लगाई और निष्पक्ष जांच का आदेश दिया। यूपीटीईटी मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने परीक्षा रद्द कर दोबारा आयोजित करने को कहा। कोर्ट ने कहा कि छात्रों का भविष्य दांव पर नहीं लग सकता। 2023 में बिहार पुलिस भर्ती परीक्षा पर पटना हाईकोर्ट ने हस्तक्षेप किया। जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ की बेंच ने स्पष्ट कहा कि पेपर लीक पारदर्शिता का उल्लंघन है। सुप्रीम कोर्ट ने डिजिटल सर्विलांस और सख्त सुरक्षा के निर्देश दिए। लेकिन कोर्ट के फैसले लागू करने में देरी होती है। न्यायपालिका ने कई बार सरकार को केंद्रीय एजेंसी बनाने का सुझाव दिया, ताकि राज्य स्तर पर भ्रष्टाचार रोका जा सके। कोर्ट छात्रों के हित में खड़ा दिखता है, लेकिन सिस्टम की कमजोरी उजागर करता रहता है। एनजीओ ने भी इस लड़ाई में अहम भूमिका निभाई है। राइट टू एजुकेशन फोरम और सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जैसे संगठन ने कई पिटीशन दाखिल कीं। 2022 में यूपीटीईटी पीड़ित छात्रों ने एनजीओ की मदद से हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। ट्रांसपेरेंसी इन एजुकेशन सोसाइटी ने नीट कांड पर रिपोर्ट जारी कर मांग की कि परीक्षा प्रक्रिया में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हो। ये संगठन छात्रों को कानूनी सहायता देते हैं और जागरूकता फैलाते हैं। बिहार में जस्टिस फॉर स्टूडेंट्स एनजीओ ने सॉल्वर गिरोह के खिलाफ स्टिंग ऑपरेशन किए। एनजीओ ने सरकार पर दबाव डाला कि पेपर लीक रोकने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित सिस्टम अपनाया जाए। इनकी सक्रियता से कई मामलों में तेज कार्रवाई हुई, लेकिन संसाधनों की कमी से प्रभाव सीमित रहता है। फिर भी ये सिविल सोसाइटी की आवाज बनते हैं। बहरहाल, लाख टके का सवाल यही है कि यह सिलसिला कब थमेगा? नीट रद्दीकरण ने पूरे सिस्टम पर सवाल खड़े कर दिए हैं। लाखों छात्रों का एक साल बर्बाद हो गया। शिक्षा माफिया को कुचलने के लिए कड़े कदम उठाने होंगे। न्यायपालिका और एनजीओ की भूमिका सराहनीय है, लेकिन सरकार की जिम्मेदारी सबसे बड़ी है। अगर अब भी सुधार नहीं हुए, तो आने वाली पीढ़ी का भविष्य खतरे में पड़ जाएगा। छात्रों की मेहनत व्यर्थ नहीं होनी चाहिए। उम्मीद है कि इस कांड से सबक लिया जाएगा।

जानें अपना राशिफल

मेष

किसी के काम से प्रभावित होकर काम करने वाला समय हो सकता है, कोई चमत्कारी काम बन सकता है, अपनी सोच सकारात्मक रखने की आवश्यकता है, आपसी प्रेम बनाये रखें।

वृषभ

समस्या का समाधान निकलने वाला समय हो सकता है, कोई बहुत दिनों से रुका हुआ काम आगे बढ़ सकता है प्रयास करे, किसी नये व्यक्ति से काम करने से फायदा भी हो सकता है, मन स्थिर रखे।

मिथुन

रणनीति बनाकर काम करने वाला समय हो सकता है, किसी के बहकावे में आने से बनता काम बिगड़ सकता है, अपनी सोच सकारात्मक रखने की आवश्यकता है, मन शान्त रखें।

कर्क

तनाव भरा समय हो सकता है इसलिए सिर्फ काम करने पर ध्यान रखने की आवश्यकता है, कोई परिवार का सदस्य आपका काम बिगाड़ सकता है, आपसी सहमति बनाये रखें, मन चंचल रहेगा।

सिंह

गुमराह करने वाला समय हो सकता है, किसी के बहकावे में आने से बनता काम बिगड़ सकता है, किसी अन्य व्यक्ति से काम बिगड़ सकता है सावधान रहे, अपने परिवार को प्रसन्न रखें।

कन्या

हैसियत दिखाने वाला समय हो सकता है, कोई बहुत दिनों से रुका हुआ काम आगे बढ़ सकता है प्रयास करे, कोई वाहन खरिदने का विचार हो सकता है, आपसी प्रेम बनाये रखें, मन में उत्साह रहेगा।

तुला

समझौता करके काम करने वाला समय हो सकता है, किसी पर ज्यादा भरोसा परेशानी का कारण बन सकता है सावधान रहे, अपनी बुद्धिमानी से काम करने की आवश्यकता है, मन चंचल रहेगा।

वृश्चिक

प्रेरणा लेकर काम करने वाला समय हो सकता है, कोई अधूरा काम पूरा हो सकता है प्रयास करे, अपनी बुद्धिमानी से काम करने की आवश्यकता है, अपने परिवार को प्रसन्न रखे, मन शान्त रखें।

धनु

मार्गदर्शन मिलने वाला समय हो सकता है इसलिए सिर्फ काम करने पर ध्यान रखने की आवश्यकता है, कोई बड़ा काम करने का अवसर मिल सकता है जो फायदेमंद होगा, मन स्थिर रखें।

मकर

सशक्त समय हो सकता है इसलिए जो भी काम कर रहे हैं फायदा अवश्य होगा, अचानक धन लाभ भी हो सकता है, अपनी सोच सकारात्मक रखने की आवश्यकता है, आपसी प्रेम बनाये रखें।

कुंभ

गलतफहमी वाला समय हो सकता है इसलिए सिर्फ काम करने पर ध्यान रखने की आवश्यकता है, किसी के चक्कर में आने से बनता काम बिगड़ सकता है सावधान रहे, मन वश में रखें।

मीन

सुरक्षित समय हो सकता है इसलिए ज्यादा से ज्यादा काम करने पर ध्यान रखने की आवश्यकता है, कोई रुका हुआ मांगलिक कार्य पूरा हो सकता है, जीवनसाथी पूरा साथ दे सकते हैं, मन प्रसन्न रहेगा।

शेर पंडित और चालाक कौआ

पूरनपुर नामक गाँव के पास एक घना जंगल था। एक दिन कही से भटकते हुए एक शेर उस जंगल में आ पहुँचा। उसने उस जंगल के जानवरों को मार कर खाना शुरू कर दिया। शेर के आतंक से पूरे जंगल में खौफ का माहौल रहने लगा। शेर कभी-कभी उसी जंगल से सटे गाँव में भी चला जाता था। जिससे उस गाँव के लोगों को भी नुकसान पहुँचाता था। गाँव वालों ने शेर से परेशान होकर एक सभा का आयोजन किया। सभी ने मिलकर शेर को पकड़ने की योजना बनाई। एक दिन गाँव के किनारे एक बकरी बांध दी गई। किसी ने बकरी को डंडे से पीटा जिससे बकरी ने आवाज की। उसकी आवाज को सुनकर शेर उस तरफ तेजी से भागा। गाँव वालों के बनाए योजना के अनुसार शेर बकरी के पास पहुँचने से पहले ही एक गड्ढे में गिर गया। गाँव वालों ने उसे पकड़कर एक पिंजरे में बंद कर दिया।

अब वह शेर लोगों से अपनी आजादी के लिए भीख माँगने लगा। लेकिन उसे कोई आजाद नहीं कर रहा था। एक दिन एक पंडित उसी शेर के पिंजरे के पास से गुजर रहे थे। शेर ने रोते हुए पंडित जी से कहा, महाराज! मुझे छोड़ दीजिए। अब मैं किसी को परेशान नहीं करूँगा। मैं इस जंगल और गाँव को भी छोड़कर दूर चला जाऊँगा। पंडित जी को शेर के ऊपर दया आ गई। उसने पिंजरे को खोल दिया। पिंजरे से बाहर निकलते ही शेर ने कहा,

''मैं कई दिनों से भूखा हूं। मैं अपनी भूख तुम्ही से मिटाऊँगा। अपनी मौत सामने खड़ी देख पंडित जी के पैरों तले जमीन खिसक गई। वहीं पेड़ पर बैठा एक कौवा पंडित जी और शेर को देखे जा रहा था। उसने पूछा क्या बात हैं पंडित जी, तुम्हें शेर महाराज क्यों खाना चाहते हैं।

पंडित जी ने सारी घटना सुना दी। कौवे ने पंडित जी से कहा, ''मैं मान ही नहीं सकता कि शेर महाराज पिंजरे में कैद थे। उन्हे तुमने आजाद करवाया है।'' उसने शेर महाराज से कहा आप मुझे फिर से दिखाओ कि इस पंडित ने तुम्हें कैसे आजाद करवाया। शेर फिर से पिंजरे में चला गया। पंडित जी ने मौका पाकर दरवाजा बंदकर दिया। शेर अंदर ही दहाड़ मार-मार कर परेशान हो उठा। पंडित जी ने कौवे को उसकी बुद्धिमत्ता के लिए धन्यवाद कहा।

नैतिक सीखः

बुद्धिमानी से लिया गया निर्णयबड़ी से बड़ी परेशानी को टाल देती है।

हल करो हीरो बनो

1. एक निश्चित संकेत की तरंग का अध्ययन किसके द्वारा किया जा सकता है?
(क) स्पेक्ट्रोमीटर (ख) कैथोड रे दोलनदर्शी
(ग) पी-एन जंक्शन डायोड (घ) सोनोमीटर
2. एलईडी टीवी मुख्य रूप से अधिक ऊर्जा कुशल हैं क्योंकि:
(क) हाई वोल्टेज ऑपरेशन (ख) बड़े पैनल
(ग) बैकलाइट कम बिजली की खपत करती है
(घ) एनालॉग सिग्नल
3. निम्नलिखित में से कौन सी घटना आकाश में इंद्रधनुष के निर्माण के लिए जिम्मेदार होती है?
(क) परावर्तन (ख) अपवर्तन
(ग) प्रकीर्णन (घ) सभी तीन
4. एम.एस.वर्ड किसका उदाहरण है?
(क)ऑपरेटिंग सिस्टम (ख) प्रोसेसिंग डिवाइस
(ग) एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर (घ) इनपुट डिवाइस
5. किसी समांतर श्रेणी का पहला पद 2 और सार्व अंतर 4 है। इसके 40 पदों का योग क्या होगा?
(क) 3200 (ख) 1600
(ग) 200 (घ) 2800

(उत्तर इसी अंक में)

मार लो मुस्की

टीचर- तुमने कभी कोई अच्छा काम किया है?
गोलू- जी सर, बिल्कुल किया है!
टीचर - कौन सा?
गोलू- एक बार एक महिला आराम से घर जा रही थी, मैंने उनके पीछे कुत्ता दौड़ा दिया, वह जल्दी घर पहुंच गई।

▶▶ ▶▶ ▶▶ ▶▶ ▶▶

पूजा के वक्त बीवी ने पति से पूछा बीवी : सुनिए जी, आपको आरती याद है ना
पति : हाँ वही पतली सी, वही न? इसके बाद भगवन की बाद में, पति की पूजा पहले हुई !!

▶▶ ▶▶ ▶▶ ▶▶ ▶▶

मालिक- तुमने पिछली नौकरी क्यों छोड़ी?
संता- परेशानी के कारण
मालिक- कैसी परेशानी थी तुम्हें?
संता- मुझे नहीं, वे लोग मुझसे परेशान हो गए थे।

▶▶ ▶▶ ▶▶ ▶▶ ▶▶

पति अपनी पत्नी से मेरी शर्ट को उल्टी करके प्रेस करना।
पत्नी- ठीक है, कुछ देर बाद
पति- शर्ट को प्रेस कर दिया क्या
पत्नी- नहीं अभी नहीं, पति- क्यों?
पत्नी- अभी मुझे उल्टी ही नही आ रही तो उल्टी करके कैसे प्रेस करूं। पति बेहोश।

▶▶ ▶▶ ▶▶ ▶▶ ▶▶

चिंटू- मम्मी प्लीज ये रस्सी अपनी जीभ से काट दो।
मम्मी- बेवकूफ रस्सी जीभ से कैसे कट सकती है?
चिंटू- क्यों? कल ही तो पापा कह रहे थे कि आपकी जुबान कैंची की तरह चलती है।

▶▶ ▶▶ ▶▶ ▶▶ ▶▶

महिला: मेरा वजन कैसे कम होगा
डॉक्टर : अपनी गर्दन को दाएं बाए हिलाएं।
महिला : कब
डॉक्टर : जब कोई खाना खाने के लिए पूछे।

▶▶ ▶▶ ▶▶ ▶▶ ▶▶

ग्राहक : आपके होटल में सफाई बहुत ध्यानपूर्वक की जाती है।
मैनेजर (खुश होकर) : धन्यवाद! आपको किस बात से ऐसा एहसास हुआ?
ग्राहक : ऐसा आभास तब हुआ जब किसी ने होटल में घुसते ही मेरी जेब की सफाई कर दी !!

▶▶ ▶▶ ▶▶ ▶▶ ▶▶

लड़की: मेरे पापा ने कहा है कि यदि मैं फेल हुई तो वह मेरी शादी रिक्शे वाले से करा देंगे।
चंगू: अरे वाह! और मेरे पापा ने कहा है कि यदि मैं फेल हुआ तो वह मुझे रिक्शा दिला देंगे।

▶▶ ▶▶ ▶▶ ▶▶ ▶▶

टीचर (चिंटू से) - होमवर्क क्यों नहीं किया?
चिंटू - मैम, मैं जब पढ़ने बैठा तो लाइट चली गई।
टीचर - तो लाइट आने के बाद क्यों नहीं की पढ़ाई?
चिंटू- बाद में मैंने इस डर से पढ़ने नहीं बैठा कि कहीं मेरी वजह से फिर से लाइट न चली जाए।

माथापच्ची–26

3		7				2	6	
8	2							
		6		2	5			4
		9	6	7		4		
		1				7		
		3		1	2	9		
7			3	4		6		
							4	8
	6	8				3		5

नियम : प्रत्येक पंक्ति में 1 से 9 तक अंक भरे जाने आवश्यक है, इनका क्रमवार होना आवश्यक नहीं है। आड़ी एवं खड़ी पंक्ति में एवं 3X3 के वर्ग में अंक की पुनरावृत्ति न हो, पहले से मौजूद अंकों को आप हटा नहीं सकते।

उत्तर अगले अंक में

माथापच्ची 25 का हल

7	2	5	9	3	4	1	6	8
9	8	6	2	1	7	5	3	4
3	4	1	8	6	5	9	2	7
5	9	4	1	8	6	2	7	3
2	6	3	7	5	9	8	4	1
1	7	8	4	2	3	6	9	5
6	3	9	5	7	1	4	8	2
8	1	7	6	4	2	3	5	9
4	5	2	3	9	8	7	1	6

ममता व स्टालिन की हार से दरका क्षेत्रीय दलों का अभेद्य किला

इंडिया गठबंधन के अस्तित्व को बचाने की बड़ी चुनौती

निज संवाददाता : भारतीय राजनीति के फलक पर 2026 के विधानसभा चुनाव नतीजों ने एक ऐसी लकीर खींच दी है, जिसने विपक्षी एकजुटता के दावों और इंडिया गठबंधन के भविष्य पर गंभीर सवालिया निशान लगा दिए हैं। चुनावी मैदान के जो आंकड़े सामने आए हैं, वे न केवल चौंकाने वाले हैं, बल्कि गठबंधन के भीतर की गहरी दरारों और वैचारिक विरोधाभासों को भी पूरी तरह नग्न कर देते हैं। एक तरफ कांग्रेस केरल में यूडीएफ के जरिए सत्ता पर काबिज हो गई है, तो दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु जैसे राज्यों में गठबंधन के दो सबसे मजबूत स्तंभों तृणमूल कांग्रेस और डीएमके का सत्ता से बेदखल होना पूरे विपक्ष के लिए किसी वज्रपात से कम नहीं है। विडंबना देखिए कि केरल में कांग्रेस की जीत उसी वामपंथ की हार की कीमत पर मिल रही है, जो राष्ट्रीय स्तर पर उसके साथ इंडिया ब्लॉक में कंधे से कंधा मिलाकर चलने का दावा करता है।

यह अंतर्विरोध बताता है कि गठबंधन की जमीन कितनी दरक चुकी है। ममता बनर्जी और एम.के. स्टालिन जैसे कद्दावर नेताओं की अपने-अपने राज्यों में हार ने इस धारणा को पुख्ता कर दिया है कि क्षेत्रीय दलों का अभेद्य किला अब दरक रहा है। बंगाल में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने अपनी जड़ें जमाई हैं और अंततः सत्ता हासिल की है, उसने न केवल राज्य की राजनीति को बदला है, बल्कि पूरे देश में विपक्ष के मनोबल को तोड़कर रख दिया है। अब सवाल सिर्फ सत्ता हासिल करने का नहीं रह गया है, बल्कि अस्तित्व को बचाने की एक बेहद कठिन लड़ाई सा बन गया है। ममता बनर्जी अब भी एकजुटता का राग अलाप रही हैं, सोनिया गांधी और राहुल गांधी के फोन कॉल्स का हवाला देकर यह जताने की कोशिश कर रही हैं कि गठबंधन अभी टूटा नहीं है, लेकिन धरातल पर हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में ममता का यह कहना कि हम हारे नहीं, हमें हराया गया है और चुनाव आयोग को खलनायक बताना, हार की हताशा को ही दर्शाता है।गठबंधन के भीतर का विरोधाभास तब और गहरा हो जाता है जब हम चुनाव प्रचार के दौरान के बयानों को याद करते हैं। इसी बंगाल की जमीन पर राहुल गांधी ने ममता बनर्जी की तुलना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से की थी। उन्होंने केंद्रीय एजेंसियों की पूछताछ का हवाला देकर ममता की नीयत पर सवाल उठाए थे। हालांकि, अब नतीजों के बाद राहुल गांधी के सुर बदले हुए हैं। वह एक्स पर बंगाल और असम के जनादेश की चोरी की बात कर रहे हैं और इसे लोकतंत्र की हत्या बता रहे हैं। लेकिन क्या यह हृदय परिवर्तन केवल राजनीतिक मजबूरी है? कांग्रेस के भीतर ही अधीर रंजन चौधरी जैसे नेताओं के बयान राहुल के स्टैंड से मेल नहीं खाते। अधीर ने स्पष्ट रूप से इसे सत्ता विरोधी लहर और भगवा लहर का परिणाम बताया था। गठबंधन की इस खींचतान का सीधा फायदा सत्ताधारी दल को मिल रहा है, जो अब और भी अधिक आक्रामक होकर अपने एजेंडे को आगे बढ़ाने की तैयारी में है।पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु के नतीजों ने एक नई चिंता को जन्म दिया है वह है क्षेत्रीय दलों के सांसदों के टूटने का डर। जिस तरह से आम आदमी पार्टी के सांसदों ने पाला बदला, वही खतरा अब टीएमसी और डीएमके पर भी मंडरा रहा है। लोकसभा में इन दोनों दलों के पास 81 सांसदों का बड़ा आंकड़ा है। यदि परिसीमन या यूसीसी (समान नागरिक संहिता) जैसे महत्वपूर्ण विधेयकों पर बीजेपी को रोकना है, तो इन दलों को अपने कुनबे को बिखरने से बचाना होगा। लेकिन सत्ता हाथ से जाने के बाद विधायकों और सांसदों को एकजुट रखना किसी हिमालयी चुनौती से कम नहीं है। क्षेत्रीय राजनीति का दबदबा जो कभी भारतीय राजनीति की पहचान हुआ करता था, अब सिमटता जा रहा है। बिहार, दिल्ली और अब बंगाल-तमिलनाडु के उदाहरण बताते हैं कि मतदाता अब डबल इंजन या एक मजबूत केंद्रीय नेतृत्व की ओर अधिक आकर्षित हो रहे हैं।अगले साल यानी 2027 में होने वाले सात राज्यों के विधानसभा चुनाव विपक्ष के लिए और भी बड़ी अग्निपरीक्षा साबित होने वाले हैं। इन सात में से पांच राज्यों में पहले से ही बीजेपी का कब्जा है। केवल पंजाब और हिमाचल प्रदेश में गैर-भाजपा सरकारें हैं, जिन पर अब तलवार लटकती नजर आ रही है। असम में अपनी पकड़ मजबूत करने और बंगाल में झंडा गाड़ने के बाद बीजेपी का आत्मविश्वास सातवें आसमान पर है। वहीं, विपक्षी खेमा आंतरिक कलह, नेतृत्व के संकट और स्पष्ट विजन की कमी से जूझ रहा है। बदरुद्दीन अजमल जैसे नेताओं के तीखे बयान, जो कांग्रेस को मुस्लिम लीग बता रहे हैं, इस बात का सबूत हैं कि गठबंधन के घटक दल अब एक-दूसरे के खिलाफ ही कुआं खोद रहे हैं। सत्ता अब विपक्ष की पहुंच से कोसों दूर दिखाई दे रही है। बीजेपी का बढ़ता ग्राफ और विपक्षी दलों का सिमटता प्रभाव यह संकेत दे रहा है कि आने वाले समय में यूसीसी और सीएए-एनआरसी जैसे विवादास्पद मुद्दों पर सरकार को किसी भी बड़े प्रतिरोध का सामना नहीं करना पड़ेगा। विपक्ष के पास न तो अब चुनावी राज्यों का संसाधन बचा है और न ही वह नैतिक बल, जो जनता को आंदोलित कर सके। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे और शरद पवार की स्थिति हो या झारखंड और बिहार में क्षेत्रीय क्षत्रपों का संघर्ष, हर जगह कहानी एक ही है बिखरता कुनबा और बढ़ता भगवा दबाव। ऐसे में इंडिया ब्लॉक का भविष्य केवल नेताओं की मुलाकातों और फोन कॉल्स तक सीमित रह जाएगा या वह सच में कोई ठोस विकल्प दे पाएगा, यह कहना अभी मुश्किल है। फिलहाल तो स्थिति यह है कि विपक्ष अपने घर को बचाने की जद्दोजहद में ही इतना उलझ गया है कि उसे सत्ता की लड़ाई का होश ही नहीं रहा। यह भारतीय लोकतंत्र के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ है, जहां संतुलन पूरी तरह से एक तरफ झुकता हुआ नजर आ रहा है।

> चुनावी मैदान के जो आंकड़े सामने आए हैं, वे न केवल चौंकाने वाले हैं, बल्कि गठबंधन के भीतर की गहरी दरारों और वैचारिक विरोधाभासों को भी पूरी तरह नग्न कर देते हैं।एक तरफ कांग्रेस केरल में यूडीएफ के जरिए सत्ता पर काबिज हो गई है, तो दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु जैसे राज्यों में गठबंधन के दो सबसे मजबूत स्तंभों तृणमूल कांग्रेस और डीएमके का सत्ता से बेदखल होना पूरे विपक्ष के लिए किसी वज्रपात से कम नहीं है।

चीतों को रास आने लगी है कूनो नेशनल पार्क की आबोहवा

हर्षवर्धन पान्डे

भारत में विलुप्त हो चुकी चीता प्रजाति को वापस लाने की महत्वाकांक्षी 'प्रोजेक्ट चीता' के तहत मध्यप्रदेश का कूनो नेशनल पार्क की आबोहवा अब चीतों को रास आने लगी है। 1952 में भारत से चीतों के विलुप्त होने के बाद सितंबर 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नामीबिया से लाए गए आठ चीतों को कूनो में छोड़कर इस ऐतिहासिक परियोजना की शुरुआत की। आज कूनो न केवल आयातित चीतों का आश्रय स्थल है, बल्कि दूसरी पीढ़ी के भारतीय चीतों के जन्म और प्राकृतिक प्रजनन का साक्षी भी बन गया है। कूनो नेशनल पार्क श्योपुर जिला मध्यप्रदेश में लगभग 74,000 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला है। कूनो अभयारण्य श्योपुर जिले के विन्ध्याचल पर्वत श्रेणी के उत्तरी भाग में स्थित है। इसमें विविध शुष्क पर्णपाती वन, घास के मैदान और प्रचुर शिकार चितल, सांभर, नीलगाय, चिंकारा आदि भी उपलब्ध हैं। चीतों के लिए उपयुक्त खुले मैदान और कम मानवीय हस्तक्षेप इसे आदर्श स्थल बनाते हैं। सितम्बर 2022 में दक्षिण अफ्रीका से चीता प्रोजेक्ट के तहत नामीबिया से 9 चीते जहां एमपी में लाये गए वहीं फरवरी 2023 में दक्षिण अफ्रीका से 12 चीते आये। बोत्सवाना से लाये गए नौ चीतों में 6 मादा और 3 नर शामिल हैं। कूनो में कई मादा गामिनी, ज्वाला आदि के शावकों को जन्म दिया और अब तक दर्जनों शावक यहां पैदा हो चुके हैं। यह 'प्रोजेक्ट चीता' के अंतर्गत तीसरा बड़ा अंतर्राष्ट्रीय चरण है। इस वर्ष बोत्सवाना से अतिरिक्त चीते आने से अब इनकी आबादी में इजाफे के आसार दिखाई दे रहे हैं। राज्य की मोहन सरकार की वन्य जीव संरक्षण की मजबूत इच्छाशक्ति का परिणाम है। कूनो की इस परियोजना ने मध्यप्रदेश में तेजी से प्रगति की है जिसके परिणाम अब धरातल पर दिखाई दे रहे हैं। अप्रैल 2026 में कूनो ने वन्य जीव संरक्षण में इतिहास रचा। गामिनी की बेटी केजीपी-2 ने खुले जंगल में चार शावकों को जन्म दिया। यह पहला मामला है जब भारत में जन्मी चीता ने जंगली परिवेश में संतान दी। इससे पहले शावक मुख्यतः बाड़े वाले क्षेत्रों में पैदा होते थे। इस सफलता के साथ भारत में चीतों की कुल संख्या 57 पहुंच गई है जिनमें से लगभग 37 भारत में जन्मे हैं। यह आंकड़ा दर्शाता है कि परियोजना अब पुनर्वास से आगे बढ़कर स्थायी प्रजनन की ओर अग्रसर हो रही है। कूनो नेशनल पार्क देश में वन्यजीव संरक्षण और पारिस्थितिकी पुनर्स्थापना का एक महत्वपूर्ण केंद्र बनकर उभर रहा है। कूनो में हिरण, चीतल, सांभर, नीलगाय और जंगली सुअरों की पर्याप्त संख्या चीतों के लिए अनुकूल साबित हो रही है। यही वजह है कि चीते यहां आराम से रह रहे हैं। दिसंबर 2023 में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद से एमपी के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने वन्यजीव संरक्षण को सांस्कृतिक विरासत, जैव विविधता, पर्यटन और ग्रामीण अर्थव्यवस्था से जोड़ने का कार्य किया है जिसके चलते मध्यप्रदेश में वन्य जीव संरक्षण और संवर्धन की दिशा में कई अभूतपूर्व निर्णय लिए गए। रातापानी टाइगर रिजर्व को देश का 8वां और प्रदेश का नया टाइगर रिजर्व घोषित करना मोहन सरकार का सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक रहा।

(....शेष भाग पेज न.3 पर)

नेपाल सीमा पर भारतीय वाहनों के लिए शुरू हो गया नया नियम

साल में 30 बार ही नेपाल की सीमा में प्रवेश

निज संवाददाता : भारत-नेपाल सीमा पर आवाजाही करने वाले निजी और पर्यटक वाहनों के लिए अब नियम बेहद सख्त हो गए हैं। नेपाल में नई सरकार के गठन के बाद सीमा प्रबंधन को लेकर बड़े बदलाव किए गए हैं, जिसका सीधा असर सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले नागरिकों और पर्यटकों पर पड़ने वाला है। नई व्यवस्था के अनुसार, अब भारतीय निजी वाहन और पर्यटक गाड़ियां एक साल में केवल 30 बार ही भंसार (सीमा शुल्क) जमा कर नेपाल की सीमा में प्रवेश कर सकेंगी। यदि कोई वाहन 30 बार की निर्धारित सीमा से अधिक बार प्रवेश करता है, तो उसे न केवल भंसार देना होगा, बल्कि भारी जुर्माना भी भुगतना पड़ेगा। इस नई प्रणाली को प्रभावी बनाने के लिए नेपाल सरकार ने अब भंसार की प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटल कर दिया है।

सीमा चौकियों पर अब क्यूआर कोड के जरिए भंसार शुल्क जमा किया जा रहा है। इस डिजिटल व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य वाहनों का ऑनलाइन रिकॉर्ड रखना है, जिससे यह आसानी से पता चल सके कि कौन सा वाहन कितनी बार सीमा पार कर चुका है। पहले यह रिकॉर्ड मैनुअल होता था, जिससे निगरानी में कठिनाई आती थी, लेकिन अब ऑनलाइन डाटा उपलब्ध होने से 30 बार की सीमा पार करने वाली गाड़ियों की पहचान तुरंत हो जाएगी। सिर्फ प्रवेश की संख्या ही नहीं, बल्कि रुकने की अवधि पर भी पाबंदी लगाई गई है। भारतीय वाहन एक साल में कुल मिलाकर अधिकतम 30 दिन ही नेपाल में रुक सकते हैं। यदि कोई वाहन निर्धारित अवधि से अधिक रुकता है, तो दोपहिया वाहनों पर दो हजार और चार पहिया वाहनों पर 2500 नेपाली रुपये प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना लगाया जाएगा। फिलहाल, मालवाहक वाहनों को इस नियम से छूट दी गई है। नेपाल सरकार ने स्पष्ट किया है कि संदिग्ध गतिविधियों पर अंकुश लगाने, टैक्स चोरी रोकने और सुरक्षा संबंधी खतरों को कम करने के लिए यह सख्ती अनिवार्य है। बिना अनुमति या भंसार के नेपाल की सड़कों पर वाहन चलाना अब गैर-कानूनी माना जाएगा और पकड़े जाने पर वाहन जब्त भी किए जा सकते हैं। वर्तमान में दोपहिया वाहनों के लिए 100, तीन पहिया के लिए 400 और चार पहिया वाहनों के लिए 600 नेपाली रुपये प्रतिदिन का शुल्क तय है। परिवर्तन की इस कड़ी में पहले ही 100 रुपये से अधिक के भारतीय सामान और बिना एमआरपी वाले उत्पादों पर कड़ाई की जा चुकी है। अब वाहनों पर लगे इन नए प्रतिबंधों से सीमावर्ती क्षेत्रों के सामाजिक और व्यावसायिक रिश्तों पर गहरा प्रभाव पड़ने की आशंका है।

'हिंदूधारा' के सहारे वेग से बढ़ रही बीजेपी

संदर्भ-बंगाल चुनाव

संजय सक्सेना

पश्चिम बंगाल में जीत के बाद एक नया ट्रेंड दिखाई दे रहा है। पहले जो बीजेपी कहा करती थी कि हमें मुसलमानों का वोट नहीं मिलता है, अब वही बीजेपी खुलेआम कहती है कि वह हिंदुओं के वोट से चुनाव जीती है। इसके साथ ही यह भी जोड़ देती है कि जो हमारे साथ था, हम उसके साथ हैं। जबकि इससे पहले मोदी कहा करते थे 'सबका साथ, सबका विकास'। सवाल यह है कि क्या अब बीजेपी बदल रही है? बीजेपी लगातार हिंदूधारा के सहारे आगे बढ़ती जा रही है। हिंदुओं को एकजुट करने के लिए बीजेपी का यह चुनावी मंत्र कहीं उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव के पीडीए की धार तो कुंद नहीं कर देगा, जैसा 2017 और 2022 के विधानसभा चुनाव में देखा जा चुका है। कहीं ऐसा न हो कि 2024 के लोकसभा चुनाव में पीडीए (पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक) के सहारे भाजपा को काफी हद तक रोकने में सफल रहे सपा प्रमुख अखिलेश यादव का यह फार्मूला 2027 में धराशायी हो जाए। वैसे भी हर चुनाव में वोटरों की सोच बदलती रहती है। राजनीति में कोई भी फार्मूला हमेशा के लिए हिट नहीं होता है।ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि पश्चिम बंगाल में बीजेपी की शानदार जीत ने राजनीतिक हलकों में हलचल मचा दी है। वहां की सड़कों पर उत्सव मनाते कार्यकर्ता चिल्ला रहे हैं कि हम हिंदुओं के वोटों से जीते। पहले जहां बीजेपी कहती थी कि मुसलमानों का वोट हमें नहीं मिलता, अब वही दल खुलकर स्वीकार कर रहा है कि हिंदू भाइयों के बल पर हमने सत्ता की कुर्सी हासिल की। साथ ही जोर देकर कहते हैं कि जो हमारे साथ रहा, हम उसके साथ हैं। यह नया सुर सुनकर सवाल उठता है कि क्या बीजेपी अपना रास्ता बदल रही है? प्रधानमंत्री का पुराना नारा तो था 'सबका साथ, सबका विकास', लेकिन अब लगता है हिंदू एकजुटता का जाप जोर पकड़ रहा है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में यह बदलाव अखिलेश यादव के पीडीए फॉर्मूले को चुनौती दे सकता है। दोबारा देखें तो 2017 और 2022 के विधानसभा चुनावों में यही हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण सपा को पटखनी दे चुका है, तो क्या 2024 के लोकसभा चुनाव में सफल रहा पीडीए का जादू अब फीका पड़ जाएगा?बहरहाल, पश्चिम बंगाल में हुई जीत कोई साधारण घटना नहीं है। वहां बीजेपी ने टीएमसी के किले को हिलाकर रख दिया। कार्यकर्ता खुशी से फूले नहीं समा रहे। वे मंचों पर चढ़कर घोषणा कर रहे हैं कि हिंदू भाइयों ने हमें चुना, इसलिए हम उनके हितों की रक्षा करेंगे।

पहले बीजेपी पर इल्जाम लगता था कि वह मुसलमान वोटों से वंचित है। अब उसी दल के नेता बिना झिझक कह रहे हैं कि हिंदुओं की एकजुटता ही हमारी ताकत है। जो हमारे साथ खड़ा हुआ, हम उसी के साथ खड़े रहेंगे। यह बातें सुनकर विपक्षी दल सन्न रह गए। तृणमूल कांग्रेस तो पहले से ही आरोप लगाती रही है कि बीजेपी ध्रुवीकरण की राजनीति करती है, लेकिन अब बीजेपी खुद इसे स्वीकार कर रही है। क्या यह रणनीति का नया मोड़ है? पश्चिम बंगाल जैसे राज्य में, जहां हिंदू आबादी बहुमत में है लेकिन बिखरी हुई रही, वहां यह नारा काम कर गया। अब सवाल यह है कि क्या यही नारा उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में भी धमाल मचाएगा?उत्तर प्रदेश की राजनीति हमेशा से ही जटिल रही है। यहां वोट बैंक की गणित बड़ी बारीकी से सेट होती है। अखिलेश यादव ने 2024 के लोकसभा चुनाव में पीडीए का फार्मूला अपनाया। पिछड़ों, दलितों और अल्पसंख्यकों को एकजुट कर बीजेपी को कड़ी टक्कर दी। सपा ने समाजवादी नीतियों के साथ गठबंधन की ताकत दिखाई। कई सीटों पर जीत हासिल की। लेकिन विधानसभा चुनावों का इतिहास कुछ और कहता है। 2017 में बीजेपी ने हिंदू कार्ड खेला। राम मंदिर का मुद्दा उठाया। गोरखपुर से बनारस तक हिंदू एकता का नारा गूंजा। नतीजा, सपा-बसपा गठबंधन धूल चाट गया। फिर 2022 में भी यही हुआ।

योगी आदित्यनाथ ने बुलडोजर की राजनीति से अपराधियों पर नकेल कसी। हिंदू वोट सिमटे। सपा का पीडीए फार्मूला फेल हो गया। अखिलेश यादव पिछड़ों को जोड़ने की कोशिश करते रहे, लेकिन हिंदू ध्रुवीकरण ने सब बर्बाद कर दिया। अब पश्चिम बंगाल की जीत के बाद बीजेपी फिर वही पुराना हथियार उठा रही है। क्या अखिलेश का पीडीए फिर कुंद पड़ जाएगा?जानकार कहते हैं कि राजनीति में वोटरों की सोच बदलती रहती है। हर चुनाव अलग कहानी लिखता है। कोई फार्मूला हमेशा हिट नहीं होता। 2014 में मोदी लहर चली। 'सबका साथ, सबका विकास' का नारा गूंजा। विकास, राष्ट्रवाद और भ्रष्टाचार विरोधी मुहिम ने कांग्रेस को धराशायी कर दिया। लेकिन 2019 में राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा हावी रहा। पुलवामा हमला और बालाकोट स्ट्राइक ने हिंदू राष्ट्रवाद को पंख दिए। 2024 में विपक्ष ने एकता दिखाई। इंडिया गठबंधन बना। उत्तर प्रदेश में पीडीए ने कमाल कर दिया। सपा ने कहा कि हम सबको साथ लेंगे। यादव, मुस्लिम और दलित को जोड़ा। कुछ हद तक सफल रहे। लेकिन अब बीजेपी बंगाल मॉडल को यूपी में आजमाने को तैयार है। वहां हिंदू वोटों से जीतकर उत्साहित नेता कह रहे हैं कि यही फार्मूला राष्ट्रीय स्तर पर चलेगा। उत्तर प्रदेश में हिंदू आबादी करीब 80 प्रतिशत है। अगर ये एकजुट हो गए, तो पीडीए का क्या होगा?बीजेपी के नेता अब खुलकर कह रहे हैं। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी पर हमला बोला गया कि वे हिंदू विरोधी हैं, इसलिए हिंदुओं ने हमें चुना। अब उत्तर प्रदेश में भी योगी आदित्यनाथ ऐसा ही करेंगे। बुलडोजर अब भी खड़ा है। कानून-व्यवस्था का डर दिखाकर हिंदू वोट साधे जाएंगे। अखिलेश यादव को चुनौती दी जाएगी कि तुम्हारा पीडीए सिर्फ वोट लेने का धंधा है।

हम हिंदुओं के सच्चे हितैषी हैं। मंदिर-मस्जिद विवाद फिर गरमाएगा। अयोध्या राम मंदिर का श्रेय लिया जाएगा। काशी और मथुरा पर नजर रखी जाएगी। क्या अल्पसंख्यक वोट सपा के पास टिकेंगे? या डर से बिखर जाएंगे? 2017 और 2022 में यही हुआ था। मुसलमान वोट सपा को मिले, लेकिन हिंदू बीजेपी के पाले में चले गए।अब 2027 के विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं। बीजेपी बंगाल का जाप यूपी में गूंजाएगी। अखिलेश यादव की मुश्किल बढ़ सकती है। उनका पीडीए पिछड़ों को लुभाने का प्रयास है। लेकिन हिंदू ध्रुवीकरण में ब्राह्मण, ठाकुर, वैश्य सब बीजेपी की गोद में चले जाते हैं। दलित भी कभी-कभी बहुजन समाज पार्टी से नाराज होकर बीजेपी की ओर झुक जाते हैं। 2024 में सपा ने ब्राह्मण चेहरों को आगे किया। कुछ सफलता मिली। लेकिन अगर बीजेपी कहे कि हम हिंदू एकता के लिए लड़ रहे हैं, तो ब्राह्मण वोट फिसल सकते हैं। यादव भाईचारे पर सपा निर्भर है, लेकिन ग्रामीण इलाकों में हिंदू भावना भड़क सकती है। अखिलेश को नया जवाब ढूंढना होगा। शायद विकास और रोजगार पर जोर दें या गठबंधन मजबूत करें। लेकिन राजनीति में वोटर का मन बदलता है। पश्चिम बंगाल ने दिखा दिया कि हिंदू नारा कितना कारगर है। विपक्षी दलों को भी सोचना होगा। कांग्रेस और अन्य दल बीजेपी के इस नए सुर से परेशान हैं। वे कहते हैं कि यह संविधान विरोधी है। लेकिन जनता क्या सोचेगी?इस पर उत्तर प्रदेश के गांवों में चाय की दुकानों पर बहस छिड़ जाएगी। कोई कहेगा बीजेपी सही कह रही है, हिंदू एकजुट हो जाओ। कोई बोलेगा अखिलेश सबको साथ लेकर चलेगा। चुनावी रणनीति बदल रही है। बीजेपी का 'सबका साथ' वाला नारा पीछे छूट रहा है। अब हिंदू हित का जाप है।

पश्चिम बंगाल की जीत इसका प्रमाण है। उत्तर प्रदेश में अगर यही चला, तो सपा का पीडीए धराशायी हो सकता है। यह सब वोटरों की सोच पर निर्भर है। हर चुनाव नई उम्मीदें जगाता है, लेकिन इतिहास दोहराने का खतरा मंडरा रहा है। यह बदलाव बीजेपी के लिए बड़ा दांव है। पहले वे सभी को लुभाते थे, अब खुलकर हिंदू कार्ड खेल रहे हैं। क्या इससे मुस्लिम वोट पूरी तरह खिसक जाएंगे? या विकास के नाम पर कुछ लौट आएंगे? उत्तर प्रदेश में परीक्षा कठिन है। यहां जातियां बिखरी हैं। यादव, जाट, कुर्मी, मौर्य सब अलग-अलग सोचते हैं। पीडीए ने इन्हें जोड़ा था, लेकिन हिंदू एकता का नारा इन सबको लपेट सकता है। अखिलेश को सतर्क रहना होगा। नया नैरेटिव गढ़ना पड़ेगा। शायद किसान मुद्दे उठाएं या युवाओं को नौकरी का वादा करें। राजनीति का खेल अनिश्चित है। पश्चिम बंगाल ने एक संकेत दिया है। उत्तर प्रदेश में क्या होगा, समय बताएगा। वोटर ही राजा है। उसकी सोच बदलेगी, तो फार्मूले भी बदलेंगे।

केरल में सतीशन की ताजपोशी, जमीनी नेता ने दिल्ली दरबार को पीछे छोड़ा

निज संवाददाता : केरल की राजनीति में इस बार सिर्फ सरकार नहीं बदली, कांग्रेस की अंदरूनी ताकत का नक्शा भी बदल गया। दस वर्षों बाद सत्ता में लौटी यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट सरकार ने जब वीडी सतीशन को मुख्यमंत्री चुना तो यह फैसला केवल एक व्यक्ति को कुर्सी सौंपने का नहीं था, बल्कि कांग्रेस के भविष्य की राजनीतिक दिशा तय करने वाला कदम बन गया। चुनाव नतीजे आने के बाद लगभग दस दिनों तक दिल्ली से तिरुवनंतपुरम तक जिस तरह की खींचतान चली, उसने साफ कर दिया था कि यह लड़ाई सिर्फ मुख्यमंत्री पद की नहीं, बल्कि कांग्रेस में 'दिल्ली मॉडल बनाम जमीनी मॉडल' की थी। आखिरकार पार्टी ने संगठन महासचिव और राहुल गांधी के सबसे करीबी नेताओं में गिने जाने वाले केसी वेणुगोपाल के बजाय उस नेता पर भरोसा जताया, जिसने पांच वर्षों तक विपक्ष में रहकर कांग्रेस को दोबारा खड़ा किया। 2026 के विधानसभा चुनाव में 140 सदस्यीय विधानसभा में यूडीएफ ने 102 सीटें जीतकर इतिहास रच दिया। कांग्रेस ने अकेले 63 सीटें हासिल कीं, जबकि उसकी सहयोगी इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने 22 सीटें जीतीं। एलडीएफ गठबंधन 35 सीटों पर सिमट गया। 2021 में कांग्रेस नीत यूडीएफ को सिर्फ 41 सीटें मिली थीं और एलडीएफ 99 सीटों के साथ सत्ता में लौटा था। यानी पांच वर्षों में कांग्रेस ने 22 सीटों की सीधी बढ़त दर्ज की, जबकि वाम मोर्चा 64 सीटें खो बैठा। यही आंकड़े बताते हैं कि यह जीत किसी सामान्य सत्ता विरोधी लहर का परिणाम नहीं थी, बल्कि विपक्ष के नेता के रूप में वीडी सतीशन की बनाई राजनीतिक रणनीति का असर थी।दरअसल, 2021 की हार कांग्रेस के लिए केवल चुनावी पराजय नहीं थी, बल्कि संगठनात्मक संकट भी थी। पार्टी के भीतर वर्षों से चल रही 'ए ग्रुप' और 'आई ग्रुप' की राजनीति ने कार्यकर्ताओं को थका दिया था। ओमन चांडी और के. करुणाकरण के दौर से चली आ रही गुटबाजी ने कांग्रेस को जनता से दूर कर दिया था। ऐसे समय में राहुल गांधी ने रमेश चेन्निथला की जगह वीडी सतीशन को विपक्ष का नेता बनाया। उस समय यह फैसला जोखिम भरा माना गया, क्योंकि सतीशन के पास न दिल्ली की लॉबी थी और न ही संगठन पर वैसी पकड़, जैसी केसी वेणुगोपाल के पास मानी जाती थी। लेकिन पांच साल बाद वही फैसला कांग्रेस के पुनर्जीवन की सबसे बड़ी वजह बन गया। सतीशन ने विपक्ष का नेता बनने के बाद सबसे पहले कांग्रेस की चुनावी राजनीति की शैली बदली। उन्होंने साफ कहा कि टिकट वितरण में गुटीय वफादारी नहीं, बल्कि जीतने की क्षमता देखी जाएगी। इसका असर स्थानीय निकाय चुनावों में दिखाई दिया। दिसंबर 2025 में हुए स्थानीय निकाय चुनावों में यूडीएफ ने 941 पंचायतों में से 505 पर जीत हासिल की। 87 नगरपालिकाओं में से 54 यूडीएफ के खाते में गईं। 14 जिला पंचायतों में से 7 पर कब्जा हुआ, जबकि 6 में से 4 नगर निगमों में कांग्रेस गठबंधन को सफलता मिली। इन नतीजों ने पहली बार यह संकेत दिया कि एलडीएफ की पकड़ कमजोर हो रही है और कांग्रेस सत्ता में वापसी कर सकती है।सतीशन की सबसे बड़ी राजनीतिक ताकत उनकी 'डेटा आधारित राजनीति' रही। विधानसभा में उन्होंने सिर्फ राजनीतिक आरोप नहीं लगाए, बल्कि सरकारी आंकड़ों के जरिए पिनाराई विजयन सरकार को घेरा। केरल में बेरोजगारी दर, राज्य का बढ़ता कर्ज, सरकारी संस्थानों में भ्रष्टाचार और युवाओं के पलायन जैसे मुद्दों को उन्होंने लगातार उठाया। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के अनुसार, 2025 में केरल की शहरी बेरोजगारी दर 18 प्रतिशत के करीब पहुंच गई थी, जबकि युवाओं में यह आंकड़ा 30 प्रतिशत से अधिक था। पिछले पांच वर्षों में लगभग 18 लाख युवा रोजगार और शिक्षा के लिए राज्य से बाहर गए। सतीशन ने इन आंकड़ों को लगातार राजनीतिक मुद्दा बनाया और कांग्रेस को 'भविष्य की अर्थव्यवस्था' की भाषा बोलने वाली पार्टी के रूप में पेश किया। केरल की सामाजिक संरचना को समझे बिना इस फैसले को समझना मुश्किल है। राज्य की राजनीति में नायर, ईसाई और मुस्लिम समुदाय निर्णायक भूमिका निभाते हैं। वीडी सतीशन और केसी वेणुगोपाल दोनों नायर समुदाय से आते हैं, जिसकी आबादी राज्य में लगभग 14 से 15 प्रतिशत मानी जाती है। लेकिन फर्क यह रहा कि सतीशन लगातार नायर बहुल परवूर सीट से पांच बार चुनाव जीत चुके हैं। 2001, 2006, 2011, 2016 और 2021 में उन्होंने लगातार जीत दर्ज की। इससे उनकी जमीनी पकड़ मजबूत मानी जाती है। दूसरी ओर, वेणुगोपाल लंबे समय से राष्ट्रीय राजनीति में सक्रिय रहे और राज्य की सक्रिय राजनीति से उनकी दूरी बढ़ती गई।कांग्रेस के लिए सबसे अहम बात यह थी कि सतीशन को अल्पसंख्यक समुदायों का भी व्यापक समर्थन हासिल था। केरल की लगभग 26 प्रतिशत आबादी मुस्लिम और करीब 18 प्रतिशत ईसाई है। यूडीएफ की सबसे बड़ी सहयोगी आईयूएमएल शुरू से सतीशन के पक्ष में थी। मुस्लिम लीग को यह आशंका थी कि अगर दिल्ली से कोई नेता मुख्यमंत्री बनकर आता है तो गठबंधन के भीतर संतुलन बिगड़ सकता है। चर्च समूहों के बीच भी सतीशन की छवि एक ऐसे नेता की रही, जो वैचारिक रूप से उदार हैं लेकिन धार्मिक तुष्टिकरण की खुली राजनीति नहीं करते। यही वजह रही कि कांग्रेस नेतृत्व ने उन्हें 'सर्वस्वीकार्य चेहरा' माना। केसी वेणुगोपाल की दावेदारी के सामने सबसे बड़ा संकट उनकी राजनीतिक स्थिति थी। वे लोकसभा सांसद हैं और पार्टी महासचिव भी। अगर उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जाता तो पहले संसद सदस्यता छोड़नी पड़ती। इसके बाद किसी विधायक की सीट खाली कराकर उन्हें छह महीने के भीतर विधानसभा पहुंचाना पड़ता। यानी एक लोकसभा और एक विधानसभा उपचुनाव का अतिरिक्त जोखिम पैदा होता। कांग्रेस पहले ही जानती थी कि सत्ता में आने के बाद शुरुआती महीनों में किसी भी तरह की राजनीतिक अस्थिरता का संदेश नुकसानदेह साबित हो सकता है। यही कारण है कि अंतिम समय में हाईकमान ने 'कम जोखिम वाले विकल्प' पर भरोसा जताया।इस फैसले का राष्ट्रीय राजनीतिक संदेश भी बड़ा है। कांग्रेस लंबे समय से इस आलोचना का सामना करती रही है कि पार्टी में फैसले सिर्फ दिल्ली दरबार के आधार पर होते हैं। लेकिन केरल में पार्टी ने पहली बार साफ संकेत दिया कि अब चुनाव जिताने वाले क्षेत्रीय नेताओं को प्राथमिकता दी जाएगी। सतीशन की ताजपोशी कांग्रेस के भीतर पीढ़ीगत बदलाव का भी प्रतीक मानी जा रही है। मुख्यमंत्री पद की दौड़ में शामिल प्रमुख चेहरों केसी वेणुगोपाल, रमेश चेन्निथला और वीडी सतीशन में सतीशन को अपेक्षाकृत युवा और नई पीढ़ी के नेता के तौर पर देखा गया। उनका पूरा राजनीतिक अभियान 'नई कांग्रेस' की अवधारणा पर आधारित था। भाजपा के बढ़ते प्रभाव को रोकना भी इस फैसले के पीछे एक बड़ा कारण रहा। पिछले कुछ वर्षों में भाजपा ने केरल में हिंदू वोटों, खासकर नायर समुदाय के बीच अपनी पैठ बढ़ाने की कोशिश की। 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा का वोट प्रतिशत 16 प्रतिशत के करीब पहुंच गया था। कांग्रेस समझती थी कि उसे ऐसा चेहरा चाहिए, जो हिंदू समाज में स्वीकार्य हो लेकिन अल्पसंख्यकों के बीच भी भरोसेमंद बना रहे। सतीशन इस राजनीतिक संतुलन में फिट बैठते हैं। उनकी छवि आक्रामक सांप्रदायिक राजनीति से दूर लेकिन सांस्कृतिक रूप से जुड़ी हुई मानी जाती है। अब सबसे बड़ी चुनौती वादों को जमीन पर उतारने की होगी। केरल इस समय लगभग 4 लाख करोड़ रुपये के कर्ज के बोझ से जूझ रहा है। राज्य में निजी निवेश की रफ्तार धीमी है और युवाओं का पलायन लगातार बढ़ रहा है। सतीशन ने चुनाव के दौरान 'ग्लोबल जॉब नेटवर्क', शिक्षा सुधार और स्टार्टअप अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने का वादा किया था। अगर वे इन मोर्चों पर ठोस परिणाम देते हैं तो कांग्रेस सिर्फ केरल में ही नहीं, बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी एक नया राजनीतिक मॉडल पेश कर सकती है। वीडी सतीशन की जीत ने यह साफ कर दिया है कि कांग्रेस अब केवल हाईकमान आधारित राजनीति के भरोसे नहीं चलना चाहती। केरल में पार्टी ने पहली बार यह स्वीकार किया है कि जनता और कार्यकर्ताओं के बीच स्वीकार्यता रखने वाला नेता ही सबसे बड़ा राजनीतिक निवेश होता है। यही कारण है कि इस बार दिल्ली की ताकत पर जमीन की हकीकत भारी पड़ गई।

जलपाईगुड़ी में सामने आई बुढ़ापा, अकेलापन और मानसिक अवसाद की एक मार्मिक तस्वीर

निज संवाददाता : जलपाईगुड़ी की हालिया घटना निस्संदेह चौंकाने वाली और असहज करने वाली है। लेकिन ऐसे संवेदनशील मामलों में मानवता, चिकित्सा विज्ञान और मानसिक स्वास्थ्य के पहलुओं को भी समान महत्व देना आवश्यक है।बुढ़ापा, अकेलापन और मानसिक अवसाद की एक मार्मिक तस्वीरजलपाईगुड़ी की एक असामान्य घटना ने एक बार फिर वृद्धावस्था से जुड़ी मानसिक अव्यवस्था और अकेलेपन के प्रश्न को सामने ला दिया है। एक साठ वर्षीय व्यक्ति ने अपने गुदा मार्ग में आलू डाल लिया, जिसके कारण उन्हें गंभीर शारीरिक समस्या का सामना करना पड़ा। लगातार तीन दिनों तक पीड़ा सहने के बाद उन्हें जलपाईगुड़ी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में भर्ती कराया गया। बाद में डॉक्टरों ने लगभग एक घंटे के ऑपरेशन के बाद उनके शरीर से करीब 100 ग्राम वज़न का आलू बाहर निकाला।डॉक्टरों के अनुसार, इस प्रकार का व्यवहार सामान्य मानसिक स्थिति का संकेत नहीं है। लंबे समय तक अकेलापन, अवसाद या मानसिक विकार कई बार व्यक्ति को असामान्य व्यवहार की ओर धकेल देते हैं। हमारे समाज में अक्सर ''बुढ़ापे की सनक'' कहकर ऐसी घटनाओं को मज़ाक में टाल दिया जाता है, जबकि इसके पीछे गहरा मानसिक संकट छिपा हो सकता है।यह घटना केवल एक व्यक्ति के विचित्र व्यवहार की खबर नहीं है, बल्कि हमारे समाज में बुज़ुर्गों के मानसिक स्वास्थ्य, अकेलेपन और उपेक्षा की एक कठोर सच्चाई को भी उजागर करती है। जिस तरह डॉक्टरों ने अपनी दक्षता से मरीज को स्वस्थ किया, उसी तरह समाज की भी ज़िम्मेदारी है कि वह बुज़ुर्गों के प्रति अधिक संवेदनशील, सहानुभूतिपूर्ण और जिम्मेदार बने।

भाजपा की शानदार सफलता ने उत्तर प्रदेश के सियासी गलियारों में मचाई हलचल

निज संवाददाता : पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भाजपा की शानदार सफलता ने उत्तर प्रदेश की सियासी गलियारों में हलचल मचा दी है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक्स पर जो पोस्ट किया, उसमें एक गहरी चेतावनी छुपी थी। उन्होंने लिखा, हर फरेबी फतह की एक मियाद होती है, ये बात ही सच्चाई की बुनियाद होती है। यह बयान महज ट्वीट नहीं, बल्कि 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव के लिए विपक्ष की मनोस्थिति का आईना है। बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की हार के बाद सपा और कांग्रेस गठबंधन अब यूपी में अपनी रणनीति को नई सिरे से ढालने में जुट गया है। दरअसल, बंगाल के नतीजे विपक्ष के लिए कई सबक लेकर आए हैं। सपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष किरनमय नंदा ने साफ कहा कि तृणमूल की हार की बड़ी वजह भ्रष्टाचार और पुरानी सरकार के खिलाफ गुस्सा था। यूपी में भी भाजपा की सरकार दस साल पूरे कर चुकी है। ऐसे में एंटी इनकम्बेंसी का सवाल स्वाभाविक रूप से उठता है। लेकिन विपक्ष जानता है कि केवल इसी पर भरोसा करके 2027 नहीं जीता जा सकता। 2024 लोकसभा चुनाव में सपा-कांग्रेस गठबंधन ने यूपी में 43 सीटें हासिल की थीं। विधानसभा क्षेत्रों में यह आंकड़ा बहुमत के काफी करीब था। इस बढ़त को मोमेंटम में बदलने की कोशिश सपा कर रही है, लेकिन बंगाल की जीत ने भाजपा के कार्यकर्ताओं में नई जान फूंक दी है।प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पांच राज्यों के नतीजों के बाद पार्टी कार्यालय में जो भाषण दिया, उसमें यूपी पर खास फोकस था। उन्होंने सपा पर तीखा हमला बोला और मिशन यूपी की शुरुआत का संकेत साफ दे दिया। अखिलेश यादव भी अपने कार्यकर्ताओं को पहले से ही चेतावनी दे रहे थे कि बंगाल के बाद भाजपा का पूरा अमला यूपी की ओर मुड़ जाएगा। इसलिए सतर्क रहने की जरूरत है। विपक्ष की सबसे बड़ी चिंता अब कार्यकर्ताओं का मनोबल बनाए रखने की है। बंगाल में ममता बनर्जी के

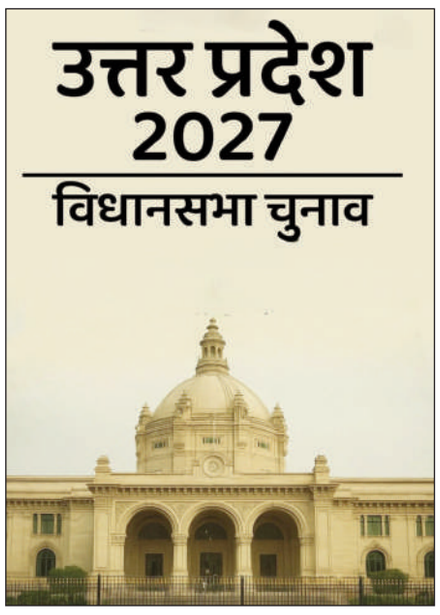

साथ अखिलेश के अच्छे संबंध रहे हैं। ममता यूपी में प्रचार भी करने आई थीं। उनकी हार ने विपक्षी खेमे में निराशा फैलाई है। बसपा के लिए तो यह स्थिति और भी चुनौती भरी है। बाइपोलर चुनावों में बसपा का अस्तित्व बचाना अब आसान नहीं रह गया है। मायावती की पार्टी को बी टीम का टैग झेलना पड़ रहा है। ऐसे में कई दलित और पिछड़े वोटर सपा को विकल्प के रूप में देख रहे हैं। सपा के वरिष्ठ नेता मानते हैं कि गैर-यादव ओबीसी, दलित और अन्य वर्गों में उनका सामाजिक विस्तार काफी हद तक कामयाब रहा है। कांग्रेस के साथ गठबंधन भी कायम रखने की कोशिश है। बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत करने का काम पिछले काफी समय से चल रहा है।विपक्ष को लगता है कि बंगाल में भाजपा की जीत में सांप्रदायिक ध्रुवीकरण और अल्पसंख्यक वोटों के बंटवारे ने भी भूमिका निभाई। यूपी में इसे रोकने के लिए अखिलेश यादव ने अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं को सख्त हिदायत दी है। कोई ऐसा बयान या आचरण न हो जिससे भाजपा को फायदा मिले। कानून-व्यवस्था को लेकर लगाई जाने वाली आलोचना भी सीमित रखने की सलाह दी गई है।

सॉफ्ट हिंदुत्व की छवि बनाने की कोशिश साफ नजर आ रही है। इटावा में केदारेश्वर मंदिर का लोकार्पण सावन के महीने में प्रस्तावित है। इसे भव्य बनाने की तैयारी चल रही है। महिला आरक्षण जैसे मुद्दों पर भी सपा भाजपा को घेर रही है। विपक्ष की रणनीति अब ध्रुवीकरण से बचते हुए सामाजिक समीकरणों पर जोर देने की है। बंगाल के नतीजों का मनोवैज्ञानिक असर भले ही हो, लेकिन यूपी में एंटी इनकम्बेंसी भाजपा के खिलाफ काम कर सकती है। यह तर्क सपा के नेतृत्व को भरोसा दिला रहा है।दूसरी ओर भाजपा में बंगाल की जीत से अपार उत्साह है। 2024 लोकसभा चुनाव में यूपी भाजपा का प्रदर्शन काफी खराब रहा था। मात्र 33 सीटें मिलीं और वोट प्रतिशत 41.37 प्रतिशत पर सिमट गया। सहयोगी दलों को मिलाकर एनडीए 36 सीटों पर अटक गया। 2014 में 71 सीटों और 42.32 प्रतिशत वोट के मुकाबले यह गिरावट काफी तेज थी। 2019 में वोट प्रतिशत बढ़ा लेकिन सीटें घटीं। विधानसभा चुनावों में भी 2017 की तुलना में 2022 में भाजपा की सीटें कम हुईं। 312 से घटकर 255 रह गईं। इन निराशाजनक आंकड़ों के बावजूद भाजपा 2027 की तैयारी में पूरी तरह जुट गई है। प्रदेश महामंत्री संगठन दो साल से क्षेत्रवार और विधानसभा वार बैठकें कर रहे हैं। बूथ स्तर पर नए सिरे से समीक्षा हो रही है। नई जिला इकाइयां गठित की गई हैं। पंकज चौधरी प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद लगातार दौरों पर हैं। दूध और शक्ति केंद्रों का सत्यापन कर निष्क्रिय पदाधिकारियों को हटाया जा रहा है। बंगाल में यूपी के कई मंत्रियों और नेताओं की टीम लगी थी, इसलिए यह जीत यूपी भाजपा के लिए खास महत्व रखती है।फिर भी चुनौतियां कम नहीं हैं। पार्टी के अंदर जातीय गोलबंदी एक बड़ी समस्या बन गई है। क्षत्रिय, ब्राह्मण, कुर्मी, लोध समेत अलग-अलग जातियों की बैठकें और दबाव पार्टी नेतृत्व के लिए चिंता का विषय हैं। यूजीसी विवाद और शंकराचार्य विवाद जैसे मुद्दों पर भी जातीय रंग साफ दिखा। सरकार और संगठन के बीच समन्वय की कमी की शिकायतें भी आती रहती हैं। अधिकतर बड़े चेहरे पूर्वांचल से होने के कारण क्षेत्रीय संतुलन बनाना भी मुश्किल हो रहा है। भाजपा नेतृत्व इन मुद्दों पर लगातार काम कर रहा है। मंडल और जिला कमेटियों में विभिन्न जातियों और क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने की कोशिश हो रही है। मंत्रिमंडल विस्तार और प्रदेश कार्यकारिणी में बदलाव के जरिए संतुलन साधने की कवायद चल रही है। सरकार और संगठन की बैठकें नियमित रूप से हो रही हैं ताकि कोई अंतर न रहे।2027 का चुनाव अब सिर्फ एक साल से भी कम समय में है। दोनों तरफ तैयारियां तेज हो गई हैं। सपा सामाजिक विस्तार और समीकरणों पर भरोसा कर रही है तो भाजपा बंगाल की जीत से मिले मोमेंटम और संगठनात्मक मजबूती को भुनाने की कोशिश में है। अखिलेश यादव कार्यकर्ताओं को सतर्क रखने पर जोर दे रहे हैं तो भाजपा मिशन मोड में काम कर रही है। यूपी की सियासत में यह लड़ाई अब केवल वोट और सीटों की नहीं, बल्कि मनोबल, रणनीति और भविष्य की दिशा तय करने की भी है। बंगाल का नतीजा यूपी के लिए एक नया अध्याय खोल गया है। देखना होगा कि विपक्ष इस चुनौती का कितना मुकाबला कर पाता है और भाजपा अपनी पिछली गिरावट को कितना दूर कर पाती है। 2027 का समर सामाजिक समीकरणों, जातीय गणित और विकास के एजेंडे के बीच होगा। दोनों पक्ष पूरी ताकत झोंक रहे हैं। नतीजा जो भी हो, यूपी की राजनीति फिर से नई दिशा लेगी।

मुस्लिम पॉकेट्स तक सिमटता सेकुलरिज्म का भारतीय चेहरा

बंगाल व असम चुनाव ने उजागर कर दी राष्ट्रीय राजनीति की गहरी सच्चाई

अजय कुमार

पश्चिम बंगाल और असम के ताजा विधानसभा चुनावी नतीजों ने भारतीय राजनीति की उस गहरी सच्चाई को उजागर कर दिया है जिसे लंबे समय से नजरअंदाज किया जा रहा था। जहां एक तरफ हिमंता बिस्वा सरमा असम में 'मियां' शब्द का इस्तेमाल कर विपक्ष की वोटबैंक राजनीति को निशाने पर ले रहे थे, वहीं शुभेंदु अधिकारी बंगाल में 'जय सनातन' का नारा लगाकर हिंदू बहुल इलाकों में भावनाओं को छू रहे थे। यह सिर्फ शब्दों का खेल नहीं था। नतीजे बताते हैं कि 'सेकुलरिज्म' का झंडा उठाने वाली पार्टियां अब खास समुदाय के मुट्ठी भर इलाकों तक सिकुड़ गई हैं। कांग्रेस असम में और तृणमूल कांग्रेस बंगाल में मुस्लिम बहुल पॉकेट्स की कैद में फंस गई हैं। असम की 126 सीटों वाली विधानसभा में कांग्रेस महज 19 सीटें जीत सकी। इनमें से 18 विधायक मुस्लिम समुदाय से हैं। यानी गैर-मुस्लिम वोटरों ने कांग्रेस को लगभग पूरी तरह नकार दिया। गौरव गोगोई जैसी युवा चेहरों की हार इस बात का प्रमाण है कि पार्टी का आधार अब केवल एक खास वोटबैंक तक रह गया है।

बदरुद्दीन अजमल की एआईयूडीएफ को सिर्फ दो सीटों पर संतोष करना पड़ा, जबकि कांग्रेस के मुस्लिम उम्मीदवारों ने टैक्टिकल वोटिंग के जरिए फायदा उठाया। मुस्लिम मतदाताओं ने अजमल को छोड़कर कांग्रेस को बीजेपी के खिलाफ मजबूत विकल्प माना, लेकिन इस प्रक्रिया में कांग्रेस ने अपना पुराना हिंदू और असमिया आधार लगभग गंवा दिया।असम कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भूपेन बोरा ने पार्टी छोड़ते वक्त जो आरोप लगाए थे, वे अब नतीजों में साफ दिख रहे हैं। बोरा ने कहा था कि पार्टी मूल निवासियों की भावनाओं को नजरअंदाज कर एक खास वोटबैंक को खुश करने में लगी है। नतीजे इस फ्रस्ट्रेशन की पुष्टि करते हैं। असम में आइडेंटिटी पॉलिटिक्स हमेशा से चरम पर रही है। बंगाल की तरह यहां भी 'सर्वधर्म समभाव' का नारा अब 'तुष्टिकरण' के रूप में देखा जा रहा है। हिमंता बिस्वा सरमा की सरकार ने डेलिमिटेशन के जरिए मुस्लिम बहुल सीटों की संख्या घटाई, जिससे स्वदेशी समुदायों का वजन बढ़ा। नतीजा यह कि 103 सीटों पर अब मूल निवासी निर्णायक बन गए। बंगाल की तस्वीर और भी चौंकाने वाली है। ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस लंबे समय से 27 से 30 फीसदी मुस्लिम मतदाताओं को अपना सबसे मजबूत सहारा मानती रही। इस बार पार्टी ने 47 मुस्लिम उम्मीदवार उतारे और 32 ने जीत हासिल की। यह स्ट्राइक रेट शानदार लगता है, लेकिन हकीकत यह है कि ये 32 विधायक टीएमसी के कुल विधायकों में करीब 40 फीसदी हिस्सा बनाते हैं। एक कथित सेकुलर पार्टी का इतना बड़ा हिस्सा एक ही समुदाय से आना खुद पार्टी की व्यापक स्वीकार्यता पर सवाल खड़ा करता है। मुर्शिदाबाद, मालदा, उत्तर-दक्षिण दिनाजपुर और दक्षिण 24 परगना जैसे मुस्लिम बहुल इलाकों में टीएमसी पहले निर्विरोध दबदबा रखती थी। अब वहां भी सेंध लग गई है। मुस्लिम वोटरों में बिखराव साफ दिखा। हुमायूं कबीर, कांग्रेस के कुछ मुस्लिम

इतिहास गवाह है कि एक समुदाय विशेष पर निर्भर राजनीति लंबे समय तक टिक नहीं पाती। व्यापक विकास, अस्मिता और स्थानीय मुद्दे अंततः निर्णायक बनते हैं। असम और बंगाल के इन नतीजों ने साबित कर दिया कि भारतीय मतदाता अब 'सेकुलर' शब्द के जाल में फंसने को तैयार नहीं है। वह जमीन पर उतरकर देख रहा है कि कौन सी पार्टी वाकई सबके लिए काम कर रही है। मुस्लिम तुष्टिकरण की राजनीति अब अपनी सीमा पर पहुंच गई है। इसके आगे का सफर या तो समावेशी विकास की ओर होगा या फिर और गहरे ध्रुवीकरण की ओर। फिलहाल नतीजे दूसरी दिशा की ओर इशारा कर रहे हैं।

उम्मीदवार और पीरजादा अब्बास सिद्दीकी की इंडियन सेकुलर फ्रंट जैसी ताकतें टीएमसी के एकाधिकार को चुनौती दे रही हैं। मुस्लिम मतदाता अब सिर्फ 'बीजेपी के डर' पर वोट नहीं देना चाहते। उन्हें लगता है कि जमीनी स्तर पर स्थानीय विकल्प बेहतर हो सकते हैं। इस बिखराव ने बीजेपी को मुस्लिम बहुल बेल्ट में भी सेंध लगाने का मौका दिया। दोनों राज्यों में एक समान पैटर्न दिखता है। जहां 'सेकुलर' पार्टियां मुस्लिम पॉकेट्स में सिमट गईं, वहीं बहुसंख्यक समुदाय में एक काउंटर पोलराइजेशन हुआ। बंगाल में बीजेपी ने हिंदू बहुल इलाकों में भारी बढ़त बनाई, जबकि असम में हिमंता सरकार ने पहले से ही स्वदेशी अस्मिता को मजबूत किया।

'सेकुलरिज्म' का भारतीय संस्करण अब कम्युनल रिप्रेजेंटेशन में बदलता जा रहा है। जब कोई पार्टी खुद को सेकुलर बताती है लेकिन उसका इलेक्टोरल बेस मुख्य रूप से एक समुदाय तक सीमित हो जाता है, तो वह दावा खोखला हो जाता है। यह बदलाव अचानक नहीं आया। पिछले कुछ दशकों में 'सेकुलरिज्म' शब्द का मतलब जमीन पर तेजी से बदला है। पहले इसे सर्वधर्म समभाव के रूप में पेश किया जाता था। अब यह खास भौगोलिक इलाकों और खास वोटबैंक तक सिमट गया है। बंगाल में ममता बनर्जी की हिजाब वाली तस्वीरें, ईद पर दिए गए भाषण, सीएए-एनआरसी और वक्फ कानून का विरोध इन सबको बीजेपी ने एजेंडा बनाया। नतीजा यह कि हिंदू बहुल इलाकों में टीएमसी के प्रति नाराजगी बढ़ी और पार्टी मुस्लिम बेल्ट तक धकेल दी गई। असम में कांग्रेस का हाल और बदतर है। 19 में से 18 मुस्लिम विधायकों वाली पार्टी अब 'मुस्लिम लीग' जैसी छवि बन गई है। गैर-मुस्लिम उम्मीदवारों में से महज एक जीत सका। यह ध्रुवीकरण का स्पष्ट संकेत है। मुस्लिम मतदाता टैक्टिकल वोटिंग कर रहे हैं, लेकिन इससे कांग्रेस की व्यापक अपील खत्म हो गई है। अजमल के साथ कभी गठबंधन, कभी समझौता यह लव-हेट रिलेशनशिप भी अंततः कांग्रेस के लिए घातक साबित हुई।ये नतीजे भारतीय राजनीति को एक सबक देते हैं। तुष्टिकरण की राजनीति का एक सैचुरेशन पॉइंट होता है। जब बहुसंख्यक समाज को लगता है कि सेकुलरिज्म उनके हितों की बलि चढ़ाकर एक वर्ग को खुश करने का माध्यम बन गया है, तो वे काउंटर पोलराइजेशन की ओर बढ़ते हैं। बंगाल और असम इसी चौराहे पर खड़े हैं। यहां वोटर अब या तो हिंदू है या मुस्लिम। बीच का 'सेकुलर' विकल्प लगभग गायब हो गया है। यह बदलाव सिर्फ दो राज्यों तक सीमित नहीं है। देश भर में वोटिंग पैटर्न में समान रुझान दिख रहे हैं। पार्टियां अब खुलकर अपनी असली पहचान स्वीकार कर रही हैं। भाजपा हिंदू बहुल आधार पर मजबूत हो रही है, जबकि विपक्षी दल मुस्लिम समर्थन पर निर्भर हो गए हैं। लेकिन इतिहास गवाह है कि एक समुदाय विशेष पर निर्भर राजनीति लंबे समय तक टिक नहीं पाती। व्यापक विकास, अस्मिता और स्थानीय मुद्दे अंततः निर्णायक बनते हैं।

असम और बंगाल के इन नतीजों ने साबित कर दिया कि भारतीय मतदाता अब 'सेकुलर' शब्द के जाल में फंसने को तैयार नहीं है। वह जमीन पर उतरकर देख रहा है कि कौन सी पार्टी वाकई सबके लिए काम कर रही है। मुस्लिम तुष्टिकरण की राजनीति अब अपनी सीमा पर पहुंच गई है। इसके आगे का सफर या तो समावेशी विकास की ओर होगा या फिर और गहरे ध्रुवीकरण की ओर। फिलहाल नतीजे दूसरी दिशा की ओर इशारा कर रहे हैं।

थम नहीं रहा सनातन पर हमले का ना खत्म होने वाला सिलसिला

तमिलनाडु विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष स्टालिन के बयान ने बढ़ाई चिंता

निज संवाददाता : तमिलनाडु विधानसभा में बीते 12 मई 2026 को एक ऐसा दृश्य देखने को मिला जिसने करोड़ों सनातनियों की भावनाओं को गहरी ठेस पहुंचाई। डीएमके नेता और नवनिर्वाचित नेता प्रतिपक्ष उदयनिधि स्टालिन ने विधानसभा में नये मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय के सामने खड़े होकर यह कहा कि सनातन धर्म लोगों को बांटने का काम करता है, इसलिए इसे जड़ से मिटा देना चाहिए। यह बयान किसी साधारण मंच पर नहीं, बल्कि एक संवैधानिक सदन में दिया गया, जो इसकी गंभीरता को और अधिक बढ़ा देता है। नेता प्रतिपक्ष के रूप में यह उनका पहला आधिकारिक भाषण था,जिसमें उन्होंने द्रविड़ विचारधारा को सदन में मजबूती से रखने के उद्देश्य से यह तीखा रुख अपनाया। वहीं नये-नवेले मुख्यमंत्री जोसेफ विजय ने उदयनिधि के बयान पर ठंडा रुख अख्तियार करके साबित कर दिया कि उन्हें उदयनिधि की सोच से कोई फर्क नहीं पड़ता है। यह पहली बार नहीं है जब उदयनिधि ने ऐसा जहर उगला हो। सितंबर 2023 में उन्होंने सनातन धर्म को डेंगू, मलेरिया और कोरोना जैसी बीमारियों की संज्ञा देते हुए कहा था कि जिस तरह इन बीमारियों को खत्म करना जरूरी है, उसी तरह सनातन धर्म को भी समूल नष्ट कर देना चाहिए। उस बयान के बाद देशभर में भारी विरोध हुआ और मामला सर्वोच्च न्यायालय तक पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट और मद्रास हाईकोर्ट ने उनके बयान पर कड़ी टिप्पणी की थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि एक मंत्री होने के नाते उन्हें अपने शब्दों की जिम्मेदारी समझनी चाहिए। लेकिन इन सबके बावजूद उदयनिधि न केवल बेखौफ रहे, बल्कि डीएमके सरकार ने पुराने बयान पर कोई कार्रवाई करने की बजाय उन्हें प्रमोशन देकर डिप्टी सीएम बना दिया था। और अब, विधानसभा चुनाव में करारी हार झेलने के बाद भी उनकी अकड़ ढीली नहीं हुई और उन्होंने वही बयान दोहरा दिया। खैर, तमिलनाडु की राजनीति में सनातन धर्म के प्रति यह विरोध किसी अचानक उभरी प्रवृत्ति का नाम नहीं है। उदयनिधि स्टालिन का यह भी कहना है कि तमिलनाडु में पिछले 100 सालों से सनातन धर्म के खिलाफ आवाजें उठ रही हैं और वे अगले 200 सालों तक भी इसके खिलाफ बोलना जारी रखेंगे। यह बयान द्रविड़ आंदोलन की उस विचारधारा की जड़ों से जुड़ा है जिसकी नींव पेरियार और अन्नादुरई जैसे नेताओं ने रखी थी। तमिलनाडु में जिस तरह की

राजनीति का बोलबाला है, उसमें हिंदू धर्म की आलोचना को प्रगतिशील राजनीति का प्रतीक माना जाता है। एक वरिष्ठ मंत्री बहुसंख्यक धर्म के खिलाफ इतना अपमानजनक बयान दे और फिर भी बिना किसी राजनीतिक नुकसान के कुर्सी पर बना रहे, यही तमिलनाडु की राजनीतिक संस्कृति की वास्तविकता है। हालांकि हाल के विधानसभा चुनाव में डीएमके को भारी हार का सामना करना पड़ा, जो यह दर्शाता है कि तमिलनाडु की जनता का एक बड़ा वर्ग अब इस राजनीति से ऊब चुका है। नई सरकार थलपति विजय की पार्टी तमिलगा वेट्री कषगम के नेतृत्व में बनी है, जो इस बात का संकेत है कि प्रदेश में सनातन विरोध की राजनीति को जनता ने अस्वीकार करना शुरू किया है। फिर भी, डीएमके का वही रवैया बरकरार है जो दशकों से चला आ रहा है। यह कहना गलत नहीं होगा कि सनातन धर्म के विरुद्ध यह राजनीतिक अभियान केवल तमिलनाडु तक सीमित नहीं है। भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला का आरोप है कि कांग्रेस, टीएमसी, राजद, सपा और डीएमके का एक ही प्लान है सनातन हिंदू का अपमान और वोट बैंक की दुकान। यह आरोप हवाई नहीं है, क्योंकि इन दलों के नेताओं के बयानों की एक लंबी फेहरिस्त है। समाजवादी पार्टी के सांसद अफजल अंसारी ने महाकुंभ 2025 को लेकर व्यंग्य करते हुए कहा था कि अगर कुंभ स्नान से सच में पाप धुलते हैं तो नरक तो खाली हो जाएगा। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी महाकुंभ को लेकर विवादित बयान देते हुए सनातन धर्म की मान्यताओं पर कटाक्ष किया और यहां तक कह दिया कि महाकुंभ जैसी कोई चीज है ही नहीं। तेलंगाना के कांग्रेस मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को आहत करते हुए हिंदू देवताओं पर आपत्तिजनक टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि जो लोग दो शादी करते हैं उनके लिए अलग भगवान हैं और जो शराब पीते हैं उनके लिए अलग भगवान हैं। कमल हासन ने भी राज्यसभा सांसद बनने के बाद एक कार्यक्रम में दावा किया कि शिक्षा ही वह एकमात्र हथियार है जो तानाशाही और सनातन धर्म की जंजीरों को तोड़ सकती है। भारतीय दंड संहिता की धारा 295-ए धार्मिक भावनाओं को जानबूझकर आहत करने को दंडनीय अपराध मानती है। इसके अलावा धारा 153-ए धर्म, जाति, भाषा के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता बढ़ाने पर दो साल तक की सजा का प्रावधान करती है। लेकिन इन धाराओं का प्रयोग सनातन के अपमानकर्ताओं के खिलाफ शायद ही कभी प्रभावी ढंग से हो पाता है। बता दें, भारतीय संविधान देश को एक पंथनिरपेक्ष लोकतंत्र घोषित करता है और विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता की गारंटी देता है। लेकिन यही पंथनिरपेक्षता एकतरफा होकर रह जाती है, जब एक धर्म विशेष को निशाना बनाना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और दूसरे धर्म की आलोचना सांप्रदायिक मान ली जाती है। कोई नया विशेष कानून नहीं बना जो विशेष रूप से सनातन धर्म के अपमान पर कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित कर सके। हां, एनएसए और यूएपीए का प्रयोग धार्मिक उग्रवाद रोकने के लिए जरूर हुआ, पर राजनेताओं के बयानों पर यह हथियार नहीं चला। जब तक संसद में स्पष्ट कानून नहीं बनता जो किसी भी धर्म के उन्मूलन की मांग करने वाले बयान को राष्ट्रीय एकता के लिए खतरा मानकर अभियोजन का आधार बनाए, तब तक यह खेल यूं ही चलता रहेगा। किसी को भी यह नहीं भूलना चाहिए कि सनातन धर्म भारत की सभ्यता का मूल आधार है। यह किसी राजनीतिक दल की सम्पत्ति नहीं, बल्कि करोड़ों भारतीयों की आस्था, संस्कृति और जीवन-दर्शन है। इसके विरुद्ध हर बार उठने वाली आवाज़ें जब दण्डमुक्त रहती हैं, तो यह लोकतंत्र और संविधान दोनों की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े करती हैं। समय आ गया है कि राजनीतिक लाभ के लिए धर्म को अपमानित करने की इस प्रवृत्ति पर संसद, न्यायपालिका और समाज तीनों एकजुट होकर लगाम लगाएं। वहीं, सनातन धर्म मानने वालों को भी ऐसी घटनाओं का अपने स्तर पर जोरदार विरोध करना चाहिए।

टीएमसी नेता के घर मिला सीक्रेट लग्जरी तहखाना, सोने का बेड और कुएं वाला बाथटब

निज संवाददाता : हावड़ा के शिवपुर इलाके में बंगाल पुलिस ने एक बड़ी छापेमारी की। यह छापा तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के चर्चित और विवादास्पद नेता शमीम अहमद के घर पर पड़ा था। छापेमारी में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। टीएमसी नेता शमीम अहमद के घर के अंदर एक अंडरग्राउंड तहखाना मिला है। यह तहखाना आलीशान और लग्जरी तरीके से बनाया गया था। इस तहखाने के बारे में शमीम अहमद के करीबी लोगों को ही पता था।

शमीम अहमद के घर में बने तहखाने में पुलिस की टीम दाखिल हुई तो उसका इंटीरियर देखकर हैरान हो गई। यहां एक के बाद एक कमरों से जुड़े कई अंडरग्राउंड कमरे बने थे। यहां महंगे फर्नीचर, बेड, टीवी समेत कई ब्रांडेड आइटम मिले। यहां तक कि तहखाने में सीसीटीवी लगा था। इसमें पूरे घर के कैमरों का एक्सेस था। तहखाने में भी सीसीटीवी कैमरा लगा था। हावड़ा में शिवपुर चौराबस्ती इलाके में बीते दिनों चुनावी हिंसा और बमबाजी हुई थी। पुलिस मामले में आरोपी शमीम अहमद के घर इसी सिलसिले में छापा मारने पहुंची थी। शमीम अहमद मध्य हावड़ा में टीएमसी के एक जाने-माने स्थानीय नेता हैं। चुनावी हिंसा मामले में केस दर्ज होने के बाद से शमीम अहमद फरार है। ठिकाने के बारे में जानकारी मिलने पर शिवपुर पुलिस स्टेशन की टीम वॉर्ड 36 में स्थित शमीम अहमद के घर पर छापा मारने पहुंची थी। छापेमारी करने गई पुलिस टीम को बाहर से शमीम अहमद का घर सामान्य लग रहा था। लेकिन जब टीम अंदर गई तो आंखें फटी रह गईं, यह अंदर से किसी महल जैसा था। यहां एक आलीशान गेट लगा था। नक्काशीदार इस दरवाजे पर बड़ा सा ताला लगा था। टीम ताला तोड़कर अंदर गई तो यहां एक सीक्रेट तहखाना नजर आया। जब टीम तहखाने में उतरी तो नीचे का नजारा देखकर दंग रह गई। यहां एक अलग ही दुनिया बसी थी। तहखाने में एक कमरे के अंदर दूसरा कमरा और ऐसे ही रहस्यमई तरीके से यह पोर्शन बना था। यहां पर बेहद खूबसूरत हस्तशिल्प वाले कीमती फर्नीचर थे। डिजाइनर डेसिंग टेबल समेत आलीशान इंटीरियर था। हावड़ा पुलिस ने बताया कि बाहर से देखने पर यह घर बिल्कुल साधारण लगता था, लेकिन पुलिस अधिकारियों को एक सीढ़ी और एक गुप्त दरवाज़ा मिला, जो दूसरी मंज़िल पर बने एक छिपे हुए फ्लैट की ओर जाता था। पुलिस ने बताया कि घर के बाकी हिस्सों में जहां आम ज़रूरत का ही सामान था, वहीं इस छिपे हुए हिस्से में आलीशान इंटीरियर, सीसीटीवी कैमरे, एक बेडरूम, लिविंग रूम, किचन और बाथरूम बने हुए थे। पुलिस ने बताया कि इन चीज़ों की क़ीमत का आकलन किया जाएगा। एक बेड था, जो गोल्डन रंग का था। इस बेड को सोने का बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस इसकी जांच कर रही है। यहां बाथरूम में एक कुएं जैसा बाथटब भी बना था।

अजब-गजब

पारंपरिक बैटरियों की तुलना में वैज्ञानिकों ने पेश की 'क्वांटम बैटरी', रोशनी के जरिए होगी चार्ज

निज संवाददाता : वैज्ञानिकों ने अत्याधुनिक क्वांटम बैटरी का प्रोटोटाइप विकसित किया है, जो रोशनी के जरिए चार्ज हो सकती है। एसआईआरओ, आरएमआईटी विश्वविद्यालय और मेलबर्न विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने मिलकर इस क्रांतिकारी तकनीक को विकसित किया है। पारंपरिक बैटरियां रासायनिक प्रक्रियाओं पर आधारित होती हैं, जिनमें चार्ज होने में समय लगता है। इसके विपरीत यह नई आर्गेनिक क्वांटम बैटरी क्वांटम मैकेनिक्स के सिद्धांतों पर काम करती है। इसमें लेजर ऊर्जा का उपयोग कर वायरलेस चार्जिंग को संभव बनाया गया है। इसकी सबसे खास विशेषता 'सुपरएक्सटेंसिव चार्जिंग' है, जिसका अर्थ है कि बैटरी का आकार जितना बड़ा होगा, वह उतनी ही तेजी से चार्ज होगी।यह पारंपरिक बैटरियों के उस सिद्धांत को चुनौती देता है, जिसमें आकार बढ़ने के साथ कार्यक्षमता घटती जाती है। एक शोध के अनुसार, वैज्ञानिकों ने मल्टी-लेयर्ड आर्गेनिक सेमीकंडक्टर का उपयोग किया है, जिससे लेजर के जरिए दूर से चार्जिंग संभव हो पाती है। इस तकनीक में माइक्रोकैविटी का इस्तेमाल किया गया है, जहां फोटॉनों को एक सूक्ष्म गुहा में फंसाकर 'को-ऑपरेटिव' प्रभाव के माध्यम से बैटरी को चार्ज किया जाता है। इसके साथ ही 'सुपर-एब्जॉर्पशन' तकनीक ऊर्जा अवशोषण की दर को कई गुना बढ़ा देती है, क्योंकि इसमें क्विबिट्स मिलकर सामूहिक रूप से ऊर्जा को तेजी से ग्रहण करते हैं। एक और बड़ी उपलब्धि यह है कि यह बैटरी सामान्य कमरे के तापमान पर काम कर सकती है। आमतौर पर क्वांटम तकनीकों के लिए बेहद कम तापमान की जरूरत होती है, लेकिन आर्गेनिक मैटेरियल के उपयोग से इस बाधा को दूर किया गया है। इस तकनीक का सबसे बड़ा असर इलेक्ट्रिक वाहनों और मोबाइल उपकरणों पर पड़ेगा। भविष्य में 'ओवर-द-एयर' चार्जिंग संभव हो सकती है, जिसमें गाड़ियों को प्लग से जोड़ने की आवश्यकता नहीं होगी। लेजर और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के जरिए उन्हें दूर से ही चार्ज किया जा सकेगा। इसके अलावा, यह बैटरी पारंपरिक बैटरियों की तुलना में समय के साथ कम खराब होगी, जिससे इसकी कार्यक्षमता लंबे समय तक बनी रहेगी।

रोजाना 22 घंटे तक सोने वाला आलसी जानवर स्लॉथ

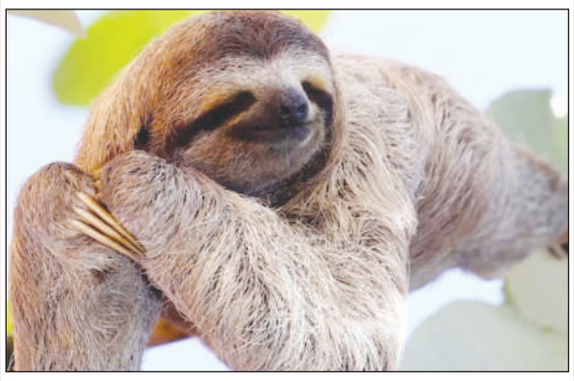

निज संवाददाता : आपको सुनकर हैरानी होगी कि मध्य और दक्षिण अमेरिका के जंगलों में रहने वाला स्लॉथ नाम का जानवर रोजाना 20 से 22 घंटे तक सोता रहता है। यह इतना आलसी है कि पेड़ पर उल्टा लटककर अपनी पूरी जिंदगी बिताता है, और कई बार इसी अत्यधिक आलस की वजह से उसकी मौत भी हो जाती है। स्लॉथ मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं टू-टोएड (दो पंजों वाले) और थ्री-टोएड (तीन पंजों वाले)। थ्री-टोएड स्लॉथ को ज्यादा आलसी माना जाता है। ये जानवर इतने सुस्त हैं कि उनकी चाल की रफ्तार सिर्फ 0.24 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। इसका मतलब है कि अगर कोई स्लॉथ किसी एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर जाना चाहे तो उसे पूरा एक दिन लग सकता है। वैज्ञानिकों के अनुसार, इनका मेटाबॉलिज्म इतना धीमा और कमजोर होता है कि वे दूसरे स्तनधारियों की तुलना में सिर्फ एक तिहाई ऊर्जा का ही इस्तेमाल करते हैं। यही वजह है कि वे दिन में ज्यादातर समय सोते रहते हैं और कम ऊर्जा खर्च करते हैं। स्लॉथ का पूरा जीवन पेड़ों पर ही बीतता है। वे शायद ही कभी जमीन पर उतरते हैं। हफ्ते में सिर्फ एक बार शौच के लिए नीचे आते हैं और फिर तुरंत वापस पेड़ पर चढ़ जाते हैं। इस दौरान वे इतने धीमे होते हैं कि शिकारी आसानी से उन्हें पकड़ सकते हैं। लेकिन प्रकृति ने उन्हें एक खास बचाव भी दिया है उनके फर पर हरे रंग का शैवाल उग आता है। इससे वे पेड़ों के पत्तों के साथ घुल-मिल जाते हैं और शिकारियों से छिप जाते हैं, जिससे उन्हें बेहतरीन छद्मावरण (कैमोफ्लाज) मिलता है। उनका फर उल्टी दिशा में बढ़ता है ताकि बारिश का पानी आसानी से बह जाए और वे सूखे रहें। फोटोग्राफरों ने जंगल में इस कामचोर जानवर को कई बार कैद किया है। ये पेड़ की डाल पर ज्यादातर उल्टा लटका हुआ दिख जाता है, जिसकी आंखें बंद, मुंह थोड़ा खुला और बिल्कुल निश्चिंत नजर आता है। देखने वाले हैरान रह जाते हैं कि इतना आलसी जानवर कैसे जिंदा रहता है। दरअसल, स्लॉथ का आहार मुख्य रूप से पत्तियां, टहनियां और फल होता है। लेकिन ये पत्तियां इतनी कम पोषक तत्व वाली होती हैं कि स्लॉथ को इन्हें पचाने में एक महीना तक लग जाता है। इसलिए वे कम खाते हैं और ज्यादा सोते हैं, क्योंकि भोजन से ऊर्जा निकालने की प्रक्रिया बहुत धीमी होती है। कई बार खाना ना मिलने या पेड़ से गिरने से उनकी मौत हो जाती है। वैज्ञानिक कहते हैं कि स्लॉथ का शरीर इतना अनुकूलित है कि वे 10 डिग्री सेल्सियस तक का कम तापमान भी आसानी से सहन कर लेते हैं। उनका शरीर इतना धीमा चलता है कि वे हफ्तों तक बिना खाए-पीए रह सकते हैं। लेकिन यही आलस उनके लिए खतरा भी बन जाता है। अगर वे किसी पेड़ से गिर गए तो वापस चढ़ने में इतना समय लगता है कि शिकारी उन्हें आसानी से मार सकते हैं। कुछ मामलों में वे भूख से कमजोर होकर मर जाते हैं। फिर भी ये जानवर लाखों सालों से जंगलों में अपनी धीमी रफ्तार से जी रहे हैं। स्लॉथ की जिंदगी देखकर लगता है कि आलस भी एक सर्वाइवल स्ट्रेटजी (जीवित रहने की रणनीति) है। वे इतने कम ऊर्जा खर्च करते हैं कि उनके पास ज्यादा खाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। मादा स्लॉथ साल में सिर्फ एक बच्चा देती है।

चीन में बने ह्यूमनॉइड रोबोट की रफ्तार ने छोड़ी गहरी छाप

निज संवाददाता : पडोसी देश चीन ने रोबोटिक्स के क्षेत्र में अपनी गहरी छाप छोड़ी है, और हालिया प्रगति ने पूरी दुनिया को हैरत में डाल दिया है। चीन में हाल ही में रोबोट्स का मैराथन आयोजित किया गया था, जिसमें देश के कई ह्यूमनॉइड मशीनों ने भाग लिया। इस मैराथन में चीनी रोबोटिक्स कंपनी यूनिट्री रोबोटिक्स ने अपने नवीनतम 'एच1' ह्यूमनॉइड रोबोट

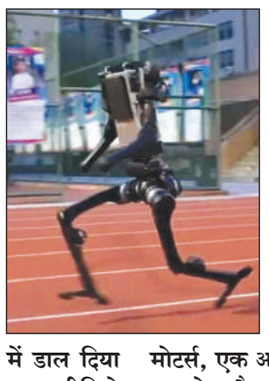

की रफ्तार से पूरी दुनिया को हैरत में डाल दिया है। एक मैराथन के दौरान जारी किए गए वीडियो में यह रोबोट ट्रैक पर 10.1 मीटर प्रति सेकंड, यानी लगभग 36 किलोमीटर प्रति घंटा की अविश्वसनीय गति से दौड़ता दिखा है। यह रफ्तार विश्व के सबसे तेज धावक, जमैका के दिग्गज एथलीट उसैन बोल्ट द्वारा 2009 में बनाए गए 100 मीटर विश्व रिकॉर्ड की औसत गति के बेहद करीब है। उस ऐतिहासिक दौड़ में, उसैन बोल्ट ने 9.58 सेकंड में 100 मीटर की दूरी तय की थी, जिसकी औसत गति लगभग 10.44 मीटर प्रति सेकंड थी। यूनिट्री का 'एच1' अब इस जादुई आंकड़े के बेहद करीब पहुंच गया है। कंपनी ने वीडियो जारी करते हुए गर्व से लिखा-10 मीटर/सेकंड!! यूनिट्री ने फिर तोड़ा वर्ल्ड रिकॉर्ड। एक आम इंसान के शरीर वाले आकार के साथ वर्ल्ड चैंपियन की स्पीड।' 'एच1' रोबोट को विशेष रूप से इंसानी चाल और गतिशीलता की नकल करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसका कुल वजन 62 किलोग्राम है और इसके पैरों की लंबाई लगभग 0.8 मीटर है। इसकी अद्भुत गति क्षमताओं के पीछे इन-हाउस विकसित हाई-टॉर्क जॉइंट मोटर्स, एक अनुकूलित गियर सिस्टम और लिदारल तथा डेप्थ कैमरा जैसी अत्याधुनिक सेंसिंग तकनीक का संयोजन है। हाई-स्पीड टेस्ट के दौरान रोबोट के प्रदर्शन को अधिकतम करने के लिए कुछ गैर-आवश्यक हिस्सों, जैसे कि सिर, को हटा दिया गया था। यूनिट्री रोबोटिक्स के सीईओ वांग जिंगजिंग ने तो यहां तक दावा किया है कि 2026 के मध्य तक उनके ह्यूमनॉइड रोबोट 100 मीटर की रेस में 10 सेकंड की बाधा को भी तोड़ देंगे। इस बीच, चीन की ही एक अन्य कंपनी मिररमी ने फरवरी 2026 में अपना प्रतिद्वंद्वी रोबोट 'बोल्ट' पेश किया है, जो 175 सेंटीमीटर लंबा और 75 किलो वजनी है और यह भी 10 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से दौड़ने में सक्षम है।

मिसाल

कीमोथेरेपी के 82 दौर के बाद, एड्रिजा ने हायर सेकेंडरी की मेरिट सूची में बनाई जगह

निज संवाददाता : अपनी ज़िंदगी की सबसे मुश्किल लड़ाई जीतने के बाद, अद्रिजा गाना ने अब मेरिट के मामले में भी एक मिसाल कायम की है। चार साल तक कैंसर से लड़ने और 82 राउंड कीमोथैरेपी से गुज़रने के बाद, उत्तर 24 परगना की इस मेधावी छात्रा ने हायर सेकेंडरी स्कूल की मेरिट लिस्ट में जगह बनाकर प्रेरणा की एक नई मिसाल कायम की है। कैंसर जीतने वाली अद्रिजा गाना ने इस साल हायर सेकेंडरी स्कूल की मेरिट लिस्ट में दसवीं जगह हासिल की है। उनके मार्क्स 487 हैं। वह पहले फेज़ के एग्जाम में भी मेरिट लिस्ट में थीं। तीसरे सेमेस्टर में नौवीं जगह पाने के बाद, इस बार उनके परसेंटेज में सुधार हुआ है लेकिन वह दसवीं जगह से थोड़ी पीछे रह गई हैं। अद्रिजा के साथ इस लिस्ट में 12 और लोग हैं। फिर भी, उनकी यह कामयाबी सिर्फ़ मार्क्स के मामले में ही नहीं, बल्कि ज़िंदगी की लड़ाई के मामले में भी एक बड़ी जीत है। रामकृष्ण सारदा मिशन सिस्टर निवेदिता गर्ल्स स्कूल की स्टूडेंट अद्रिजा ने आर्ट्स डिपार्टमेंट में पढ़ाई की। ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर एप्लीकेशन और साइकोलॉजी उनके पसंदीदा विषय थे। वह भविष्य में क्लिनिकल साइकोलॉजी पढ़ना चाहती हैं। उसका लक्ष्य ग्रेजुएशन के लिए बेथ्यून कॉलेज में एडमिशन लेना है, हालांकि वह जरूरी हुआ तो विदेश में पढ़ाई करने के बारे में भी सोच रही है। छठी क्लास के बाद अद्रिजा की जिंदगी ने करवट ली। उत्तर 24 परगना के निमता की रहने वाली अद्रिजा को सालाना परीक्षा खत्म होने के बाद टी-सेल लिंफोमा कैंसर का पता चला। उसके बाद लंबा इलाज शुरू हुआ- एक के बाद एक

कीमोथेरेपी, शारीरिक दर्द और मानसिक संघर्ष। उस मुश्किल समय में परिवार और स्कूल के शिक्षकों के सपोर्ट ने उसे आगे बढ़ने की हिम्मत दी। दूसरी तरफ अद्रिजा की शारीरिक हालत के बारे में जानने के बाद उसकी दादी गंभीर रूप से बीमार पड़ गईं। एक तरफ बेटी तो दूसरी तरफ अद्रिजा के पिता जॉयमंगल गाना लगभग व्याकुल हो गए। वह खुद टाकी हाउस गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड मल्टीपर्पस ब्वॉयज स्कूल में पॉलिटिकल साइंस के टीचर हैं। उस समय अद्रिजा की मां ज्योति गाना ने कमान संभाली। बेलघरिया ब्वॉयज स्कूल में शिक्षिका ज्योति ने अकेले ही अपनी बेटी के लिए लड़ाई शुरू कर दी। वह इलाज के लिए बेटी को लेकर अकेले ही मुंबई चली गईं। उनके पिता, जॉयमंगल गाना, उस समय अपने प्रोफ़ेशन में कंगाल थे, लेकिन उन्होंने परिवार को चलाया। अद्रिजा के स्कूल टीचरों का इमोशनल सपोर्ट भी बहुत ज़रूरी था। लगातार कीमो, स्कूल की माताजी, टीचरों के साथ और रेगुलर थेरेपी की मदद से अद्रिजा धीरे-धीरे ठीक हो गईं। आखिरकार, चार साल के लंबे इलाज के बाद, वह 2021 में इस बीमारी से पूरी तरह आज़ाद हो गईं। हालांकि, उन्हें अभी भी रेगुलर हेल्थ चेक-अप के लिए मुंबई जाना पड़ता है। फिर भी, अब उनकी आँखों में एक नया सपना है - अपने अनुभव से दूसरों के साथ खड़ी होना। अद्रिजा गाना के शब्दों में, सिर्फ शरीर ही नहीं, बल्कि मन को भी मज़बूत होना पड़ता है। वह लड़ाई सबसे मुश्किल होती है। और उस लड़ाई को जीतने के बाद, वह अब सिर्फ एक सफल स्टूडेंट ही नहीं, बल्कि हज़ारों लोगों के लिए प्रेरणा हैं।

भैरोसिंह शेखावत : 50 रुपए में लड़ा था पहला चुनाव

निज संवाददाता : राजनीति के दबंग नेता माने जाने वाले देश के पूर्व उपराष्ट्रपति और तीन बार राजस्थान के सीएम रहे भैरोसिंह शेखावत का जीवन संघर्ष से सफलता की मिसाल था। उन्होंने राजनीति में बाबोसा या ठाकर साहब के नाम से अपनी अलग पहचान बनाई थी। भैरोसिंह शेखावत उन तमाम दिग्गज नेताओं की फेहरिस्त में शामिल हैं, जिनकी भूमिका को शायद ही नजरअंदाज किया जा सके। तत्कालीन जयपुर रियासत के गांव खाचरियावास में 23 अक्तूबर 1923 को भैरोंसिंह का जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम देवी सिंह शेखावत था और मां का नाम बने कुंवर था। शुरूआती शिक्षा गांव से पूरी करने के बाद उन्होंने हाई स्कूल

के लिए जोबनेर जाने की कठिन डगर तय की। हाईस्कूल पूरा करने के बाद उन्होंने जयपुर के महाराजा कॉलेज में प्रवेश लिया। इस दौरान उनके पिता का निधन हो गया और परिवार के 8 सदस्यों के भरण-पोषण का भार उनके कंधों पर आ गया। ऐसे में भैरोंसिंह ने खेत में हल थाम लिया। वहीं उनको पुलिस में भी नौकरी मिली, लेकिन इस नौकरी में भैरोंसिंह का मन नहीं लगा और वह फिर खेती की तरफ लौट आए।इसी बीच जन संघ के सक्रिय सदस्य रहने पर साल 1952 में भैरोंसिंह को दांतारामगढ़ से विधानसभा चुनाव लड़ने का मौका मिला। इस मौके को भुनाते हुए भैरोंसिंह ने पहला चुनाव जीता और इस तरह से उन्होंने राजनीति के पायदान पर पहला सफल कदम रखा। इस चुनाव को लड़ने के लिए भैरोंसिंह के पास रुपए नहीं थे। उन्होंने जब यह परेशानी तत्कालीन जनसंघ के नेताओं के सामने रखी, तो किशन सिंह हाजरिका ने चुनावी मदद के रूप में 50 रुपए दिए थे। तब भैरोंसिंह ने किशन सिंह सेठ की पदवी दी थी। 15 मई 2010 को भैरोंसिंह शेखावत का निधन हो गया था।

रथींद्र बसु निर्विरोध चुने गए पश्चिम बंगाल विधानसभा के नए स्पीकर

निज संवाददाता : कूचबिहार से बीजेपी के विधायक रथींद्र बसु पश्चिम बंगाल विधानसभा के नए स्पीकर बिना किसी विरोध के चुने गए हैं। वे कूचबिहार दक्षिण से बीजेपी के विधायक हैं। बड़ी बात यह कि यह पहली बार है जब वे विधानसभा चुनाव जीते हैं। शुक्रवार सुबह विधानसभा में प्रोटेम स्पीकर तपस रॉय की देखरेख में स्पीकर का चुनाव पूरा हुआ। रथींद्र ने बिना किसी विरोध के स्पीकर की कुर्सी संभाली। सत्तारूढ़ बीजेपी ने स्पीकर के तौर पर रथींद्र का नाम प्रस्तावित किया था। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने शुक्रवार को विधानसभा में यह प्रस्ताव रखा। दिलीप घोष ने इसका समर्थन किया। रथींद्र ने वॉयस वोट से स्पीकर का चुनाव जीता। सत्र की शुरुआत वंदे मातरम के गायन से हुई। हालांकि, स्पीकर चुनाव के दौरान तृणमूल विधायक सदन में मौजूद नहीं थे। वे बाद में मीटिंग में लौट आए। विधानसभा सदस्यों के समर्थन के बाद रथींद्र मुख्यमंत्री और सत्ताधारी पार्टी के पार्लियामेंट्री पार्टी के नेता शुभेंदु और विपक्ष के नेता शोभनदेव चटर्जी का हाथ पकड़कर स्पीकर की कुर्सी पर बैठे। तृणमूल के विधायकों ने इस चुनाव का विरोध नहीं किया। पूर्व स्पीकर बिमान बनर्जी ने रथींद्र को बधाई दी।विधानसभा के नियमों के मुताबिक, स्पीकर ने पहले मुख्यमंत्री को बोलने की इजाजत दी। शुभेंदु ने रथींद्र का स्वागत किया। उन्होंने यह भी उम्मीद जताई कि यह विधानसभा अगले पांच सालों तक राज्य के लोगों की उम्मीदों को पूरा करने के लिए कंस्ट्रक्टिव तरीके से काम कर पाएगी। विपक्ष को अपनी बात रखने का मौका मिलेगा। हालांकि, शुभेंदु ने उम्मीद जताई कि विपक्षी विधायक शुरू से ही विधानसभा की कार्यवाही में रुकावट डालने की कोशिश से बचेंगे। मुख्यमंत्री के बाद, स्पीकर की इजाजत से विपक्षी नेता शोभनदेव ने बात की। इसके बाद अलग-अलग पार्टियों के विधायकों को एक-एक करके बोलने का मौका दिया गया। आईएसएफ के विधायक नौशाद सिद्दीकी और सीपीएम के विधायक मुस्तफिजुर रहमान राणा ने भी विधानसभा में स्पीकर रथिंद्र का अभिवादन किया। मालूम हो कि रथींद्र पहली बार विधायक बने हैं। वे पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। वे लंबे समय तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) से जुड़े रहे। बाद में, वे सक्रिय राजनीति में आ गए। 2026 के विधानसभा चुनाव में, उन्होंने कूचबिहार दक्षिण सीट से तृणमूल कैंडिडेट अभिजीत दे भौमिक को 23,000 से ज़्यादा वोटों से हराया।

बेलियाघाटा के सिद्धा स्काई कॉम्प्लेक्स में पधारे मंत्री दिलीप घोष

निज संवाददाता : पश्चिम बंगाल में शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में नई भाजपा सरकार ने कार्यभार संभाल लिया है। मुख्यमंत्री के रूप में एक तरफ जहां शुभेंदु अधिकारी ने शपथ ली है, वहीं दिलीप घोष समेत पांच मंत्रियों ने भी शपथ ली है। सभी विभागीय मंत्रियों ने कार्य शुरू कर दिया है। इसी क्रम में मंत्री दिलीप घोष शुक्रवार को कोलकाता के बेलियाघाटा के सिद्धा स्काई कॉम्प्लेक्स में पधारे। कॉम्प्लेक्स में रहने वालों के लिए यह आनंद और गर्व का क्षण था। दिलीप घोष के आने से सिद्धा स्काई कॉम्प्लेक्स के निवासियों ने खुद को सम्मानित महसूस किया। उन्होंने मंत्री के साथ अंतरंग बातचीत की। कॉम्प्लेक्स के निवासियों ने भाजपा सरकार को हर तरह के सहयोग व समर्थन का वादा किया। साथ ही विधानसभा चुनाव में भाजपा की शानदार जीत पर घोष को बधाई दी। मंत्री ने भी निवासियों को निर्भय होकर रोजी-रोजगार व आजीविका चलाने का भरोसा दिया। घोष ने कहा कि पिछली तृणमूल कांग्रेस की सरकार में राज्य में जितने भी अनैतिक कार्य व भ्रष्टाचार हुए हैं, शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में भाजपा सरकार उन सब बुराइयों को दूर कर सुशासन स्थापित करेगी।

फुटबॉल विश्व कप के मंच पर फिर जादू बिखेरेगा शकीरा का संगीत

शुभ्रांशु राय

आगामी फुटबॉल विश्व कप को लेकर दुनिया भर में उत्साह धीरे-धीरे बढ़ने लगा है। मैदान पर मुकाबले शुरू होने में अभी कुछ समय बाकी है, लेकिन संगीत की दुनिया में विश्व कप का माहौल अभी से बनना शुरू हो गया है। बीते 8 मई को सोशल मीडिया पर इस बार के विश्व कप के बहुप्रतीक्षित थीम गीत ''दाई दाई'' का टीज़र जारी कर दिया गया। टीज़र सामने आते ही फुटबॉल प्रेमियों और संगीत के दीवानों के बीच जबरदस्त उत्सुकता पैदा हो गई है। लैटिन पॉप की विश्व विख्यात गायिका शकीरा ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से यह टीज़र वीडियो पोस्ट किया। इस वीडियो की शूटिंग ब्राज़ील के ऐतिहासिक माराकाना स्टेडियम में हुई है, जो फुटबॉल इतिहास के कई यादगार पलों का साक्षी रहा है। यही वजह है कि टीज़र की शुरुआत से ही फुटबॉल की विरासत और जज़्बात को समेटे एक विशेष माहौल बन गया है। वीडियो में दिखता है कि नर्तक इस बार के विश्व कप के मेज़बान देशों मेक्सिको, संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के राष्ट्रीय झंडों के रंगों से सजी पोशाकों में डांस कर रहे हैं। रंग, रौशनी और ताल का यह संगम एक जीवंत और उत्सवी वातावरण तैयार करता है, जो विश्व कप की बहुराष्ट्रीय और बहुसांस्कृतिक पहचान

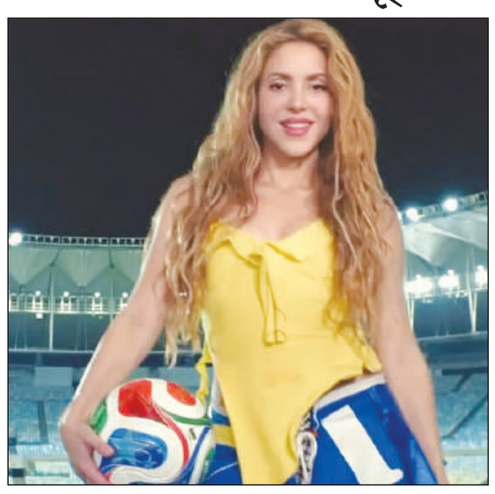

को बखूबी दर्शाता है। हालांकि, प्रशंसकों के लिए सबसे भावुक पल वह था जब 2006, 2010 और 2014 विश्व कप की आधिकारिक मैच गेंदों को दिखाया गया। कई फुटबॉल प्रेमियों का कहना है कि यह शकीरा की उन तीन विश्व कप यात्राओं को सम्मान देने का एक प्रतीकात्मक प्रयास है, जिन्होंने संगीत जगत पर अपनी अमिट छाप छोड़ी। खास तौर पर 2010 विश्व कप का गाना ''वाका वाका (दिस टाइम फॉर अफ्रीका)'' आज भी विश्व कप इतिहास के सबसे लोकप्रिय थीम गीतों में शुमार है। इसके अलावा 2006 का ''हिप्स डोंट लाइ'' और 2014 का ''ला ला ला'' भी दुनियाभर में धमाल मचा चुके हैं।

ऐसे में नए गीत ''दाई दाई'' में भी प्रशंसक शकीरा के पुराने जादू की झलक देख रहे हैं।इस बार के गाने का एक और बड़ा आकर्षण नाइजीरिया के मशहूर गायक बर्ना बॉय की मौजूदगी है। जानकारी के मुताबिक, ''दाई दाई'' में लैटिन पॉप के साथ अफ्रो-बीट (अफ्रीकी ताल) का एक अनोखा फ़्यूज़न देखने को मिलेगा। शकीरा की पहचानी हुई लय और आवाज़ के साथ बर्ना बॉय के अफ्रीकी संगीत और आधुनिक ध्वनियों का यह मेल नई पीढ़ी के श्रोताओं के लिए एक अलग ही अनुभव लेकर आ सकता है, ऐसा संगीत समीक्षक मानते हैं। विश्व कप का थीम गीत सिर्फ एक गाना नहीं होता; यह विश्व फुटबॉल के जुनून, संस्कृति और एकता का प्रतीक होता है। अतीत में भी देखा गया है कि एक सफल थीम गीत पूरे टूर्नामेंट के माहौल को नई दिशा और ऊंचाई देता है। इसी नज़रिए से ''दाई दाई'' से काफी उम्मीदें हैं।

बंगाल में चुनाव संपन्न कराने में आयोग व प्रशासनिक विभाग की रही सराहनीय भूमिका

निज संवाददाता : पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव संपन्न हो गया और मतगणना के बाद भाजपा को पूर्ण बहुमत मिल गया। अब भाजपा के नेतृत्व में ही राज्य में नई सरकार का गठन होगा। दो चरणों में हुए चुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने में एक तरफ जहां चुनाव आयोग की सराहनीय भूमिका रही, वहीं दूसरी तरफ, राज्य के प्रशासनिक अधिकारियों व पुलिस विभाग ने भी इसमें सक्रिय योगदान दिया। इसमें बंगाल के पूर्व मुख्य सचिव दुष्यंत नरिआला की विशेष भूमिका रही। मालूम हो कि इस बार राज्य में दो चरणों में विधानसभा चुनाव कराया गया, जिसमें पहला चरण 23 अप्रैल व दूसरा चरण 29 अप्रैल को हुआ। वहीं, मतगणना 4 मई को संपन्न हुई। आगामी 9 मई को राज्य में नई सरकार का गठन होगा। इस बीच, दुष्यंत नरिआला ने 4 मई को एक अधिसूचना जारी की। इसमें राज्य प्रशासन के सभी विभागों के सचिव व विभागीय प्रमुख को निर्देश दिया गया है। निर्देश के मुताबिक बिना किसी आधिकारिक आदेश के किसी भी महत्वपूर्ण दस्तावेज को हटाने, नष्ट करने या कहीं ले जाने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है।

मनोरंजन

नृत्यांगना लीला सैमसन : दुनिया भर में भरतनाट्यम को दिलाई नई पहचान

निज संवाददाता : वर्षों की साधना, समर्पण और मेहनत के दम पर नृत्यांगना लीला सैमसन ने भारतीय शास्त्रीय नृत्य को देश ही नहीं, बल्कि दुनिया भर में नई पहचान दिलाई। उन्होंने भरतनाट्यम को केवल एक नृत्य शैली नहीं, बल्कि अपने जीवन का उद्देश्य बना लिया। एक कलाकार, गुरु और प्रशासक के रूप में उनका योगदान भारतीय कला जगत में बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। लीला सैमसन का जन्म 6 मई 1951 को तमिलनाडु के कूनूर में हुआ था। उनके पिता बेंजामिन अब्राहम सैमसन भारतीय नौसेना में अधिकारी थे, जबकि उनकी मां लैला को संगीत और कला से विशेष लगाव था। परिवार का सांस्कृतिक माहौल ही ऐसा था कि बचपन से ही लीला का झुकाव कला की ओर होने लगा। उनकी मां ने उनकी प्रतिभा को पहचाना और उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। जब लीला सैमसन मात्र नौ वर्ष की थीं, तब उनके पिता ने उन्हें चेन्नई के प्रसिद्ध कला संस्थान 'कलाक्षेत्र' में दाखिला दिलाया। यहीं से उनके जीवन की असली यात्रा शुरू हुई। उन्होंने महान नृत्य गुरु रुक्मिणी देवी अरुंडेल से भरतनाट्यम की शिक्षा प्राप्त की। कलाक्षेत्र में बिताए गए वर्षों ने उनकी सोच और व्यक्तित्व को पूरी तरह बदल दिया। इसी दौरान उन्होंने तय कर लिया था कि वह अपना पूरा जीवन नृत्य और कला को समर्पित करेंगी। पढ़ाई के साथ-साथ लीला सैमसन ने नृत्य की साधना लगातार जारी रखी। समय के साथ उनकी प्रतिभा निखरती गई और वह एक उत्कृष्ट भरतनाट्यम नृत्यांगना के रूप में पहचानी जाने लगीं। अपने करियर की शुरुआत में उन्होंने दिल्ली के श्रीराम भारतीय कला केंद्र और गंधर्व महाविद्यालय में छात्रों को भरतनाट्यम सिखाया। उनकी शिक्षण शैली और कला के प्रति समर्पण ने उन्हें एक सफल गुरु के रूप में भी स्थापित किया। धीरे-धीरे लीला सैमसन ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी पहचान बनाई।

उन्होंने यूरोप,अफ्रीका और अमेरिका सहित कई देशों में मंच प्रस्तुतियां दीं और भारतीय शास्त्रीय नृत्य को वैश्विक मंच पर पहुंचाया। उनकी प्रस्तुतियों में पारंपरिकता के साथ गहरी भावनात्मक अभिव्यक्ति देखने को मिलती थी, जिसने दर्शकों को हमेशा प्रभावित किया। साल 1995 में उन्होंने 'स्पंदा' नाम से एक डांस ग्रुप की स्थापना की। इसका उद्देश्य भरतनाट्यम को नए अंदाज में प्रस्तुत करना और नई पीढ़ी को इस कला से जोड़ना था। उन्होंने अनेक छात्रों को प्रशिक्षण दिया, जिनमें से कई आगे चलकर प्रसिद्ध कलाकार बने। लीला सैमसन ने कला के साथ प्रशासनिक जिम्मेदारियां भी बखूबी निभाईं। वह 2005 से 2012 तक कलाक्षेत्र की निदेशक रहीं।

हर किसी को अपने विचारों को फैलाने का अधिकार है : जावेद अख्तर

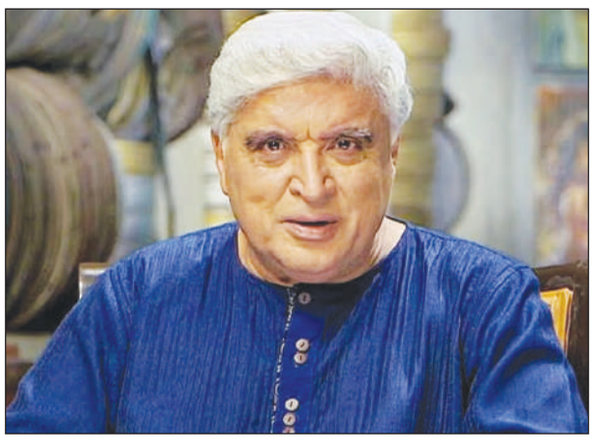

निज संवाददाता : जाने-माने गीतकार और पटकथा लेखक जावेद अख्तर ने कहा कि हर किसी को अपने रचनात्मक कामों के ज़रिए अपने विचार को फैलाने का हक है। उन्होंने कुछ फिल्मों को प्रोपेगैंडा कहने का विरोध किया। अख्तर कोलकाता के ज्वेलरी ब्रांड पी. सी. चंद्रा ज्वैलर्स से स्पेशल अवॉर्ड लेने के बाद पत्रकारों से बात कर रहे थे। पत्रकारों ने उनसे हाल की कुछ फिल्मों को प्रोपेगैंडा कहने के बारे में पूछा था। अख्तर ने कहा-मुझे नहीं पता कि प्रोपेगैंडा फिल्मों से आपका क्या मतलब है। मुझे 'धुरंधर' बहुत पसंद आई, जो एक बेहतरीन फिल्म थी। मुझे पहली वाली दूसरी वाली से ज़्यादा पसंद आई। अख्तर ने कहा-हर कहानी का कोई न कोई स्टैंड होता है, लेकिन क्या यह प्रोपेगैंडा बन जाती है क्योंकि कहानी दर्शकों के एक हिस्से के लिए सही नहीं है? हर किसी को अपने विचार को फैलाने का हक है। प्रोपेगैंडा फिल्मों में क्या गलत है? हर फिल्ममेकर का काम सच दिखाना है। उन्होंने आगे कहा कि फैंटेसी पर आधारित फिल्मों में भी एक आइडियोलॉजिकल (विचारधारात्मक) मज़बूती होती है। बांग्ला कवि श्रीजातो बंद्योपाध्याय के खिलाफ करीब दस साल पहले लिखी गई एक कविता को लेकर जारी वारंट के बारे में पूछे जाने पर, अख्तर ने कहा कि उनके पास इस मुद्दे पर टिप्पणी करने के लिए पूरी जानकारी नहीं है। खुद को नास्तिक बताने पर अख्तर ने कहा-एक नास्तिक अपने आप सोचता है, बिना किसी भेदभाव के, समझदारी से सोचता है। मुझे पिछले साल वेस्ट बंगाल उर्दू एकेडमी ने एक इवेंट के लिए बुलाया था जो कैंसिल हो गया था। उन्होंने कुछ इस्लामी समूह की आपत्तियों का जिक्र करते हुए कहा-यह सिर्फ उन लोगों की समस्या है जो धार्मिक रूप से संकीर्ण सोच रखते हैं और जिनमें सहनशीलता कम होती है। अख्तर ने यह भी कहा कि हर फिल्म में एक सीख होती है जिसका दर्शक अलग-अलग मतलब निकाल सकते हैं। उन्होंने कहा-फिल्में आईने की तरह होती हैं। समय के साथ नैतिकता बदलती है, और उम्मीदें बदलती हैं। जैसे-जैसे समाज बदलता है, कंटेंट भी बदलता है। अख्तर ने कहा कि वह आखिरकार एक ऐसी मेनस्ट्रीम फिल्म बनाना चाहेंगे जो क्लास और आम दर्शकों, दोनों को पसंद आए। 2014 में केंद्र में भारतीय जनता पार्टी के सत्ता में आने से हुए राजनीतिक बदलाव पर अख्तर ने कहा कि बदलाव तो होना ही है। उन्होंने कहा-कभी-कभी बदलाव अच्छे नहीं लगते और कभी-कभी अच्छे लगते हैं। मैं आमतौर पर मानता हूं कि युवा पीढ़ी मेरी पीढ़ी से बेहतर है। वे इस समाज को और बेहतर बनाएंगे।

इस साल लंबा चलेगा पितृ पक्ष

26 सितंबर से शुरू होकर 10 अक्टूबर तक रहेगा

निज संवाददाता : इस साल पितृ पक्ष लंबा होने जा रहा है। यह 26 सितंबर से शुरू होकर 10 अक्टूबर को सर्व पितृ अमावस्या तक रहेगा। पितृ पक्ष का आरंभ भाद्रपद पूर्णिमा से अश्विन अमावस्या के इस पखवाड़े को 16 श्राद्ध के नाम से भी जाना जाता है। इस समय पितर पृथ्वी लोक पर अपने वंशजों के पास आते हैं और श्रद्धा से किए गए तर्पण और पिंडदान को स्वीकार करते हैं। पितृ पक्ष में किए गए श्राद्ध और तर्पण से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और परिवार में कभी गम के बादल नहीं मंडराते हैं, पूर्वजों का आशीर्वाद हर मुसीबत से बचाता है।

पितृ पक्ष का महत्व

मार्कण्डेयपुराण के अनुसार आयुः प्रजां धनं विद्यां स्वर्गं मोक्ष सुखानि च। प्रयच्छन्ति तथा राज्यं पितरः श्राद्धतर्पिताः।। अर्थात- श्राद्ध से संतुष्ट होकर पितृगण श्राद्धकर्ता को धन, विद्या, सुख, संतति, दीर्घायु सहित मुक्ति और मोक्ष भी प्रदान करते हैं। श्राद्ध कर्म से ही व्यक्ति अपने पितरों का ऋण चुकाता है। शास्त्रों में देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण बताए गए हैं।

श्राद्ध पक्ष का सबसे खास दिन

पितृ पक्ष में जिस दिन पितरों की मृत्यु हुई हो उसी तिथि पर उनका श्राद्ध करना चाहिए लेकिन अगर पूरखों की मृत्यु तिथि याद न हो तो ऐसे में सर्वपितृ अमावस्या पूरे श्राद्ध में तर्पण, पिंडदान के लिए सबसे अहम मानी जाती है। इसे महालय अमावस्या के नाम से जाना जाता है पितृ पक्ष में महालय अमावस्या सर्वाधिक मुख्य दिवस होता है।

पितृ पक्ष में नहीं होते ये काम

पितृ पक्ष में शुभ कार्यों को टालना ही उचित है क्योंकि ये समय पूर्वजों की स्मृति और तर्पण का समय माना जाता है, इसलिए इस दौरान लोग सादगी और संयम का पालन करते हैं। मान्यता है कि श्राद्ध पक्ष में नए कपड़े, गहने, वाहन या अन्य सुख-सुविधाओं की खरीदारी से बचना चाहिए। इस अवधि में विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन, उपनयन संस्कार, भूमि पूजन जैसे शुभ और मांगलिक कार्य भी नहीं किए जाते हैं।

श्राद्ध के दिन क्या न करें

श्राद्ध शाम और रात्रि के समय करना वर्जित है। दिन के आठवें मुहूर्त (कुतपकाल, सुबह 11.36 से दोपहर 12.24 तक) में पितरों के लिए दिया गया दान अक्षय होता है। अतः कुतपकाल में श्राद्ध करें। श्राद्ध वाले दिन पान का सेवन, तेल की मालिश, स्त्रीसंभोग, अन्न का भक्षण नहीं करना चाहिए।

पितृ पक्ष में श्राद्ध की तिथियां

26 सितंबर 2026, शनिवार-पूर्णिमा श्राद्ध
27 सितंबर 2026, रविवार-प्रतिपदा श्राद्ध
28 सितंबर 2026, सोमवार-द्वितीया श्राद्ध
29 सितंबर 2026, मंगलवार-तृतीया श्राद्ध और महा भरणी श्राद्ध
30 सितंबर 2026 बुधवार-चतुर्थी श्राद्ध और पंचमी श्राद्ध
1 अक्टूबर 2026 गुरुवार-षष्ठी श्राद्ध
2 अक्टूबर 2026 शुक्रवार-सप्तमी श्राद्ध
3 अक्टूबर 2026 शनिवार-अष्टमी श्राद्ध
4 अक्टूबर 2026 रविवार-नवमी श्राद्ध
5 अक्टूबर 2026, सोमवार-दशमी श्राद्ध
6 अक्टूबर 2026, मंगलवार -एकादशी श्राद्ध
7 अक्टूबर 2026, बुधवार- द्वादशी श्राद्ध और मघा श्राद्ध
8 अक्टूबर 2026, गुरुवार-त्रयोदशी श्राद्ध
9 अक्टूबर 2026, शुक्रवार-चतुर्दशी श्राद्ध
10 अक्टूबर 2026, शनिवार- सर्वपितृ अमावस्या श्राद्ध

संजना पांडे ने बढ़ाया भोजपुरी का मान

निज संवाददाता : अपनी दमदार अभिनय क्षमता से भोजपुरी अभिनेत्री संजना पांडे ने फिर दर्शकों और समीक्षकों का दिल जीत लिया है। अभिनेत्री को हाल ही में 'जी भोजपुरी 2026' अवॉर्ड समारोह में उनकी चर्चित फिल्म 'कलेक्टर साहिबा' के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री और 'बहुमुखी अभिनेत्री' के सम्मान से नवाजा गया। इस उपलब्धि के बाद अभिनेत्री ने अपनी खुशी सोशल मीडिया के जरिए प्रशंसकों के साथ साझा की और पूरी टीम के प्रति आभार जताया। संजना पांडे ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट पर पुरस्कार समारोह की कई तस्वीरें साझा कीं, जिनमें वह ट्रॉफी के साथ बेहद भावुक और गर्वित नजर आ रही थीं। उन्होंने अपनी पोस्ट में लिखा कि यह सम्मान उनके लिए केवल एक अवॉर्ड नहीं, बल्कि जिंदगी का बेहद खास और भावनात्मक पल है। अभिनेत्री ने कहा कि जिस बिहार की मिट्टी में उन्होंने जन्म लिया और परवरिश पाई, उसी धरती पर सम्मानित होना किसी भी कलाकार के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि होती है। अभिनेत्री ने अपनी सफलता का श्रेय पूरी टीम को देते हुए फिल्म के निर्देशक इश्तियाक शेख बंटी और सह-कलाकार गौरव झा का विशेष धन्यवाद किया। इसके अलावा उन्होंने फिल्म के लेखक अरविंद तिवारी सहित सभी कलाकारों और तकनीकी टीम के प्रति भी आभार व्यक्त किया।संजना ने कहा कि टीमवर्क, विश्वास और सभी के सहयोग के बिना यह मुकाम हासिल करना संभव नहीं था। अपने संदेश में संजना पांडे ने परिवार, दर्शकों और ईश्वर का भी धन्यवाद किया। उन्होंने लिखा कि जब कोई कलाकार पूरी मेहनत, ईमानदारी और समर्पण के साथ काम करता है, तो उसकी मेहनत एक न एक दिन जरूर पहचानी जाती है। उन्होंने भोजपुरी भाषा और समाज के प्रति गर्व व्यक्त करते हुए 'जय भोजपुरी, जय भोजपुरी समाज' का संदेश भी दिया।

रीति- रिवाज

स्वामी मोहता पब्लिशिंग हाउस के लिए, प्रकाशक, मुद्रक : अजय कुमार मोहता द्वारा अरिहंत मुद्रा, 61, सूर्यसेन स्ट्रीट, कोलकाता-700009 से मुद्रित एवं प्रकाशित। **संपादकीय कार्यालय** : 10, डॉ. राजेन्द्र प्रसाद सरणी, (क्लाइव रो), 5बी मंजिल, रूम नं. 9, कोलकाता-700001, **स्थानीय कार्यालय** : 28-5 कन्वेंट रोड, मौलाली, कोलकाता-700014। **संपादक : अजय कुमार मोहता**, मो. 9830045693, E-mail-gambheersamachar@gmail.com. Website. www.gambheersamachar.in (प्रकाशित रचनाओं के चयन, संपादन हेतु पीआरबी एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी, सभी कानूनी विवाद के लिए कोलकाता न्याय क्षेत्र)